राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 36

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14



इंग्लैंड दौरे पर गए विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत कोरोना पाजिटिव

>> 12

जागरण विशेष



नईदुनिया : छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के ग्राम बदराई में ग्रामीणों ने 'पानी बैंक' बनाया है। गांव में एक छोटा नाला (सरार) है। सिंचाई संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने व्यर्थ बहने वाले पानी को सरार तक दिशा दी। इससे आसपास के खेतों में सिंचाई आसान हो गई। पेज-10

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय राजधानी ▶ पृष्ठ 2

राज्य बताएं, कैसे लगाएंगे पराली जलाने पर लगाम

नई दिल्ली : इस बार सर्दी में एनसीआर का दम न घुटे, इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पांचों राज्यों से पराली प्रबंधन पर एक्शन प्लान मांगा है। प्लान 31 जुलाई तक देना है। पहली बार इन राज्यों को चार विकल्प दिए गए हैं। राज्यों को अपने एक्शन प्लान में आयोग को बताना होगा कि वे इनमें से कौन सा विकल्प अपनाएंगे।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

अब आपका हुनर ही बनेगा पहचान, होगा प्रमाणीकरण

नई दिल्ली : पढ़ाई छोड़कर छोटे-मोटे काम धंधे में लगे लोगों के लिए उनका यही हुनर अब उनकी पहचान बनेगा। इसका उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके जरिये वे आसानी से भविष्य की नई राहें भी चुन सकेंगे। कौशल विकास को बढ़ावा देने में जुटी सरकार कामगारों के हुनर का प्रमाणीकरण करने की तैयारी में है।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

झारखंड में 15 लाख का इनामी नक्सली ढेर

रांची : झारखंड के गुमला जिले के जंगल में विस्फोट कर एक ग्रामीण और सुरक्षा बल के श्वान की जान लेने वाले 15 लाख के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव को सुरक्षा बलों ने गुरुवार को कैरागनी जंगल में एक मुठभेड़ में मार गिराया। बुद्धेश्वर उरांव भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी सदस्य था।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 6

किसान की तीन बेटियां एक साथ बनीं आरएएस अधिकारी

जयपुर : राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भैरूसरी गांव की तीन बहनों का एकसाथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) में चयन हुआ है। किसान की तीनों बेटियों ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति और अच्छी परवरिश की जाए तो बेटियां बोझ नहीं होती हैं। उनकी दो बड़ी बहनें पहले से आरएएस अधिकारी हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 7

पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत की उम्मीद

नई दिल्ली : गुरुवार को देश की जनता को पेट्रोल व डीजल के खुदरा मूल्यों में एक और वृद्धि की मार झेलनी पड़ी है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे संकेतों के हिसाब से हफ्ते-दस दिनों में कीमतों में नरमी आ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि के बाद अब कमी आ रही है।

गांधी के खिलाफ इस्तेमाल हुए कानून को खत्म क्यों नहीं करते

मांगा जवाब ▶ राजद्रोह की धारा 124ए के दुरुपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से किया सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने आइपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह) के दुरुपयोग और इस पर कार्यपालिका की जवाबदेही न होने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, इस कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह कानून अंग्रेजों के समय का है। वे स्वतंत्रता आंदोलन दबाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। उन्होंने महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए इसका प्रयोग किया। आजादी के इतने साल बाद भी इसकी जरूरत क्यों है। सरकार ने बहुत से पुराने कानून रद किये हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका बहुत दुरुपयोग होता है। ये कानून लोगों व संस्थाओं के लिए बड़ा खतरा है। कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर विचार करने का मन बनाते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। हालांकि जवाब के लिए कोई तिथि नहीं दी है।

कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए ये तीखी टिप्पणियां चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राजद्रोह कानून पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इसी मुद्दे पर पहले से लंबित याचिकाओं को भी इसी के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने का आदेश दिया।

मौजूदा याचिका मेजर जनरल (अवकाश प्राप्त) एसजी वोमबटकेरे ने दाखिल की है। याचिका में राजद्रोह कानून को रद करने की मांग की गई है। एक याचिका एडीटर्स गिल्ड की ओर से भी दाखिल की गई है। गुरुवार को वकील श्याम दीवान ने एडीटर्स गिल्ड की याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें कानून को रद करने और दिशा निर्देश जारी करने की मांग है। उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। बुधवार को कोर्ट ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से वोमबटकेरे की याचिका पर सुनवाई में कोर्ट की मदद करने को कहा था।

कानून के खिलाफ तीन याचिकाएं : गुरुवार को अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह की दो अन्य याचिकाएं भी लंबित हैं जिन पर दूसरी पीठें सुनवाई कर रही हैं। उन मामलों में कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। वेणुगोपाल की दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है और वे देखेंगे कि क्या मामलों को एक साथ सुनवाई के लिए संलग्न किया जा सकता है अथवा और क्या हो सकता है। सैन्य अधिकारी के वकील ने कहा कि उनकी याचिका बाकी से अलग है। इस पर भी सुनवाई होनी चाहिए। जस्टिस रमना ने कहा कि अगर इतिहास देखा जाए, तो इस कानून में दोषी साबित होने की दर बहुत कम है। लेकिन इसका प्रयोग ऐसे हो रहा है जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी दी जाए और वह पूरा जंगल ही काट डाले। आइटी एक्ट की धारा 66ए का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि उस कानून के रद होने के बाद भी उसमें हजारों केस दर्ज हुए।

- कानून को परखने का मन बनाते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
- आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून के बरकरार रहने से कोर्ट हैरान



कोर्ट की टिप्पणियां

- अंग्रेज इस कानून का दुरुपयोग स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए करते थे।
- सरकार ने कई कानून रद किए, पता नहीं इस पर ध्यान क्यों नहीं गया।
- राजद्रोह कानून का इस तरह प्रयोग हो रहा है, जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी दी जाए और वह पूरा जंगल ही काट डाले।

'हमारी चिंता दुरुपयोग को लेकर' : पीठ ने कहा कि अगर पुलिस किसी को फंसाना चाहती है तो धारा 124ए भी लगा देती है। जिस पर भी यह धारा लगती है वह डर जाता है। इन मुद्दों पर विचार किए जाने की जरूरत है। हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग और कार्यपालिका की कोई जवाबदेही न होने को लेकर है। पीठ ने कहा कि वह सभी मामलों को एक साथ संलग्न कर सुनवाई करेगी।

लोगों को फंसाने का हथकंडा : केके वेणुगोपाल ने कहा, कानून रद करने की जरूरत नहीं है। सख्त दिशानिर्देश तय करने से भी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। पीठ ने कहा, एक गुट दूसरे गुट के लोगों को फंसाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है। ये लोगों लिए खतरा है। पीठ ने याचिका को प्रामाणिक व याचिकाकर्ता को वास्तविक बताते हुए कहा, उसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है। हम यह नहीं कह सकते कि यह प्रेरित अर्जी है।

विधायक विधानसभा में रिवाल्वर निकाल ले तो क्या उस पर केस दर्ज नहीं होगा पेज>>3

बंगाल में कानून का राज नहीं, शासक का कानून

एनएचआरसी की रिपोर्ट ▶ बंगाल हिंसा पर ममता सरकार की कड़ी आलोचना

मानवाधिकार आयोग ने की हत्या और दुष्कर्म मामलों की सीबीआइ जांच की सिफारिश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम की कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी गई अंतिम जांच रिपोर्ट में ममता सरकार की कड़ी आलोचना की गई है। 50 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। टीम ने गुरु रवींद्रनाथ टैगोर की कविता की कुछ पंक्तियों को उल्लेख करते हुए कहा है कि टैगोर की धरती बंगाल में कानून का राज नहीं है बल्कि यहां शासक का कानून चल रहा है। रिपोर्ट में चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) से कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कुख्यात अपराधियों की सूची में तृणमूल कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। ज्ञात हो, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर एनएचआरसी ने राजीव जैन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की थी।

गणतंत्र की हत्या हो जाएगी : रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर राज्य में हिंसा नहीं रोकी गई तो भारत जैसे महान देश में गणतंत्र की हत्या हो जाएगी। हिंसा दूसरे राज्यों में फैलने लगेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच के दौरान दुष्कर्म, हत्या, आगजनी जैसे सैकड़ों मामले सामने आए जिनकी शिकायतें तक दर्ज नहीं की गई हैं। पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, उनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है। समिति को मिली शिकायतों को पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है ताकि केस दर्ज हो। ज्यादातर मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं तो आरोपित जमानत पर रिहा हो गए हैं। अधिकांश आरोपित खुले घूम रहे हैं।

तृणमूल ने आयोग से की बंगाल में जल्द उपचुनाव कराने की मांग पेज>>4

- कुख्यात अपराधियों की सूची में तृणमूल के बड़े नेताओं के नाम, ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट का भी जिक्र
- हिंसा के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य के बाहर फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने की अनुशंसा



बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा कार्यालयों को जमकर निशाना बनाया गया था। जागरण आर्काइव

बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की घटनाओं से पीड़ितों के प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता दिखाई देती है। -रिपोर्ट का एक अंश (आइएएनएस के अनुसार)

1,900 से अधिक शिकायतें मिलीं जांच टीम को दुष्कर्म, हत्या, आगजनी की

9,304 के खिलाफ प्राथमिकी, 1,354 बंदी, 97 फीसद आरोपित खुले घूम रहे

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- दबाव में पुलिस नहीं कर रही शिकायतों पर कार्रवाई, गंभीर मामलों के लिए एसआइटी बने
- विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने व गवाहों की सुरक्षा देने की बात
- केंद्रीय बलों की तैनाती व प्रभावितों के पुनर्वास पर भी हो काम
- हिंसा के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो

अदालत की निगरानी में सीबीआइ जांच करे

रिपोर्ट के अनुसार, हत्या और दुष्कर्म के मामले की जांच सीबीआइ से कराई जाए और सुनवाई राज्य के बाहर हो। हिंसा में अन्य गंभीर अपराधों के लिए विशेष जांच टीम (एसआइटी) का गठन किया जाए जिसकी मानिटरिंग कोर्ट करे। पीड़ितों को आर्थिक सहायता के साथ पुनर्वास, सुरक्षा और आजीविका की व्यवस्था कराई जाए। यह सिफारिश की गई है कि रिटायर्ड जज की देखरेख में मानिटरिंग कमेटी बने और हर जिले में एक स्वतंत्र अफसर आब्जर्वर के रूप में तैनात किया जाए। जांच का आदेश जल्दी हो क्योंकि दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है। पीड़ितों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं।

कुख्यात अपराधियों में बड़े नेता भी

रिपोर्ट में कुख्यात अपराधियों की सूची में तृणमूल सरकार में मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक, विधायक पार्थ भौमिक, विधायक शौकत मोल्ला, विधायक खोकन दास, तृणमूल नेता जीबन साहा, उदयन गुहा, नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पोलिंग एजेंट रहे शेख सुफियान समेत अनेक तृणमूल नेताओं के नाम हैं। इन नेताओं ने कहा है कि केंद्र के इशारे पर बदले की भावना से रिपोर्ट में उनका नाम दिया गया है।

रिपोर्ट लीक होने पर भड़कीं ममता

ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। एनएचआरसी ने विकृत रिपोर्ट पेश की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में जांच के लिए कितने कमीशन भेजे? हाथरस से लेकर उन्नाव तक कई घटनाएं हो चुकी हैं। एनएचआरसी ने रिपोर्ट लीक कर दी। उसे कोर्ट का सम्मान करना चाहिए।

समिति में शामिल थे ये सदस्य : एनएचआरसी की जांच समिति में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतीफ रशीद, महिला आयोग की डा. राजुबेन देसाई, एनएचआरसी के महानिदेशक (जांच) संतोष मेहरा, बंगाल मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा, राज्य लीगल सर्विस कमीशन के सचिव राजू मुखर्जी और महानिरीक्षक मंजिल सैनी शामिल थीं।

'आत्मनिर्भर भारत' से आकर्षित हो रहे निवेशक

जागरण संवाददाता, वाराणसी

अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को इस साल पहली बार प्रत्यक्ष संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां उनसे अपनापन घनीभूत किया, वहीं यह आश्वस्ति भी दी कि देश-प्रदेश के साथ बनारस के समावेशी विकास का उनका संकल्प फलीभूत हो रहा है। उन्होंने कहा, 'आत्मनिर्भर भारत' योजना से दुनिया के निवेशक आकर्षित हुए हैं। विशेषकर उप्र में जिस प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, उससे यह उनका पसंदीदा राज्य बना है। 'भाई-भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से सरकार चलती है'- कहकर उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना भी साधा। मोदी ने जापान सरकार के सहयोग से बने 'रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर' के लोकार्पण के साथ ही करीब 1,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

'हर-हर महादेव' और स्थानीय बोली (काशिका) में लोगों का अभिवादन करने के बाद मोदी ने कहा कि जापान के सहयोग से भारत में कई परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। सबसे विश्वसनीय दोस्तों में एक इस मित्र राष्ट्र का सहयोग 'न्यू इंडिया' की ताकत है। 'रुद्राक्ष' प्रेम की माला की तरह है और जापान के सहयोग से गुजरात में भी 'जैन गार्डन' जैसा प्रकल्प प्रेम की सुगंध फैला रहा है। फ्रेट कारिडोर और हाईस्पीड ट्रेन आदि योजनाओं में भी जापान का सहयोग प्रशंसनीय है। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री सुगा योशीहिदे और पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रति कृतज्ञता अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने कहा- 'भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चलती है सरकार'

काशी को दी करीब 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का किया लोकार्पण



वाराणसी में गुरुवार को आइआइटी बीएचयू के टेक्नो पवेलियन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट

मेरे बनारस के रोम-रोम में संस्कृति की धारा बहती है। सात सालों में कई विकास योजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा था, लेकिन यह रुद्राक्ष के बिना अधूरा था।

प्रधानमंत्री ने योगी सरकार के कामकाज को जमकर सराहा

प्रधानमंत्री ने उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी सरकार के कामकाज की भरपूर प्रशंसा भी की। याद कराया कि उप्र में वर्ष 2017 से पहले भी केंद्र से पैसा आता था, लेकिन लखनऊ में अटक कर रह जाता था। देश देख चुका है कि पहले के दौर में सुविधाओं की कितनी कमी थी और इच्छाशक्ति का कितना अभाव था। दिमागी बुखार को लेकर लोग कितने परेशान होते थे। उन्होंने बनारस को मेडिकल हब बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोरोना से निपटने की तैयारियों से भी बीएचयू के डाक्टरों से संवाद भी किया। आगाह भी किया, लापरवाही हुई तो तीसरी लहर भारी पड़ेगी। सरकार ने हाल ही में 23,000 करोड़ रुपये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपलब्ध कराया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम का स्वागत किया। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी भी मंच पर उपस्थित थे।

बीएचयू के टेक्नोग्राउंड में गुरुवार को डिफेंस कारिडोर समेत उप्र के अन्य एक्सप्रेस-वे की गिनती कराते हुए मोदी ने कहा, एक्सप्रेस-वे केवल सड़क परिवहन के उद्देश्य के लिए नहीं बन रहे, इस रास्ते आत्मनिर्भर भारत के क्लस्टर तैयार होंगे। चूंकि कृषि उत्पाद और खेती की देश के विकास में बड़ी भूमिका है, इसलिए सरकार का जोर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ज्यादा है। एक लाख करोड़ रुपये के विशेष फंड का प्रविधान इसके लिए किया गया है। कृषि मंडी को आधुनिक और सुविधायुक्त बनाने की शुरुआत हो गई है। नतीजा है कि देश में गेहूं और धान की रिकार्ड खरीद होने लगी है।

काशी के मंच से योगी के यूपी माडल पर मोदी ने लगाई मुहर पेज>>4

अफगानिस्तान पर टाप गियर में भारतीय कूटनीति

नई दिल्ली : अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को देख भारत की कूटनीतिक गतिविधियां भी काफी तेज हो गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर न सिर्फ अफगानिस्तान के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं बल्कि दूसरे देशों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं। गत तीन दिनों में दुशांबे (ताजिकिस्तान) में कई देशों के साथ विमर्श के बाद जयशंकर गुरुवार को ताशकंद (उज्बेकिस्तान) पहुंचे, जहां शुक्रवार को एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें अफगानिस्तानी राष्ट्रपति अशरफ घनी, पाक के पीएम इमरान खान, अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि खलीलजाद समेत कई मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेता होंगे। (पेज-3)

कमल नाथ बन सकते हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष

- सोनिया गांधी से कमल नाथ की मुलाकात ने पार्टी में बढ़ाई हलचल
- पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी



पार्टी नेतृत्व ने आज तक जो भी दायित्व सौंपा है, उसका ईमानदारी से निर्वहन किया है। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे भी उसी प्रकार निभाऊंगा। हालांकि, यह भी सच है कि मप्र नहीं छोड़ूंगा। -कमल नाथ

प्रशांत किशोर ने दी थी सलाह : चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) ने भी कमल नाथ की बड़ी भूमिका की पार्टी नेतृत्व को सलाह दी है। पीके ने चंद दिनों पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकजुटता की रणनीति पर चर्चा के लिए राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस की राजनीतिक वापसी के लिए संगठन के मौजूदा ढांचे में बदलाव और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व ने विमर्श का दौर शुरू कर दिया है। पार्टी के शीर्ष ढांचे में बड़े बदलाव के तहत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। इस बीच कमल नाथ की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से गुरुवार को हुई मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है।

उप्र समेत पांच राज्यों के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को लेकर जारी दुविधा खत्म करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इसके मद्देनजर जल्द ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया फिर शुरू करने की तैयारी हो रही है। इस बारे में अंतिम फैसले के लिए यथाशीघ्र कार्यसमिति की बैठक बुलाई जाएगी। कार्यसमिति ही अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम का फैसला करती है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के बाद एआइसीसी का सत्र भी अगस्त-सितंबर में बुलाए जाने की संभावना है। साथ ही पार्टी के शीर्ष संगठन के पदाधिकारियों में भी बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है। चर्चा के अनुसार, राहुल गांधी दूसरी बार अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसे में बड़ा वर्ग सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बनाए रखने के पक्ष में है। हालांकि, सेहत के चलते सोनिया की सियासी सक्रियता कम हो गई है। इसीलिए कमल नाथ को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है।

कई मायनों में कमल नाथ मुफीद

- असंतुष्ट नेताओं के साथ पार्टी के सभी वर्ग को स्वीकार्य चेहरा हैं व गांधी परिवार के भी भरोसेमंद हैं
- पार्टी में पिछले साल जी-23 की ओर से उठे असंतोष के स्वरों के बीच असंतुष्ट नेताओं ने कमल नाथ को साधने का प्रयास किया था।
- कांग्रेस नेतृत्व ने भी असंतुष्टों को समझाने का जिम्मा कमल नाथ को सौंपा था। उन्होंने जी-23 के आक्रामक रुख को नरम भी किया।
- दूसरे विपक्षी दलों और उनके नेताओं के साथ कमल नाथ के मैत्री पूर्ण रिश्ते उनकी बड़ी ताकत हैं
- अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में रहे यह सुनिश्चित करने में कमल नाथ कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव से लेकर स्टालिन तक उनके अच्छे रिश्ते हैं

उपलब्धि

भारत में हर तीसरे वयस्क को लग चुका टीका

देश में कोरोना टीकाकरण के छह महीने पूरे, वैक्सीन सप्लाई की धीमी गति बन रही अभियान में बड़ी चुनौती, दिसंबर तक 135 करोड़ अतिरिक्त डोज की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी सरकार

नीलू रंजन, नई दिल्ली

भारत में हर तीसरे वयस्क को कम-से-कम एक टीका लग चुका है। भारत में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 94 करोड़ है। उनमें से गुरुवार की सुबह सात बजे तक 31.35 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। सात करोड़ 78 लाख लोग दोनों डोज ले चुके हैं, लेकिन भारत की आबादी को देखते हुए, यह नाकाफी है। वैक्सीन की सप्लाई अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। लिहाजा सरकार ने खामियों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर तक 135 करोड़ डोज सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

ज्ञात हो, देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने टीकाकरण अभियान को सबसे विशाल बताते हुए कहा, दुनिया में किसी भी देश में अभी तक इतने टीके नहीं लगाए गए। चीन में 105 करोड़ डोज लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, उसके



डाटा पर दुनिया में किसी को भरोसा नहीं है। इसीलिए उससे तुलना नहीं की जा सकती है। अधिकारी ने कहा, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला देश अमेरिका है। वहां भी अभी तक 33.5 करोड़ डोज ही दिए जा सके हैं। ब्रिटेन में 8.11 करोड़, फ्रांस में 6.23 करोड़, ब्राजील में 11.72 करोड़ और जर्मनी में 8.41 करोड़ डोज ही दी गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, भारत का कोरोना टीकाकरण अभियान न सिर्फ विशाल है, बल्कि सबसे तेज गति से चलने वाला भी है। दुनिया में इस समय औसतन तीन करोड़ डोज रोजाना दिए जा रहे हैं। इनमें 38 लाख अकेले भारत में दिए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में 5.48 लाख, ब्राजील में 13.55 लाख, जर्मनी में 7.77 लाख, ब्रिटेन में 2.35 लाख और फ्रांस में 5.55 लाख डोज प्रतिदिन दिये जा रहे हैं। वैसे 21 जून को भारत एक दिन में 88 लाख डोज देकर कीर्तिमान स्थापित कर चुका है।

दुनिया में सबसे अधिक और सबसे तेज टीकाकरण के बावजूद भारत की चुनौतियां बरकरार हैं। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच जल्द से जल्द बड़ी संख्या में टीकाकरण जरूरी है। गुरुवार सुबह तक 39.13 डोज लगाने के बावजूद 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को टीका लगाने के लिए 149 करोड़ अतिरिक्त डोज की जरूरत पड़ेगी। सरकार को इसका अहसास है। दिसंबर तक 135 करोड़ डोज देना सुनिश्चित किया जा रहा है। जाहिर है कि वैक्सीन उत्पादन की रफ्तार और बढ़ानी पड़ेगी। कंपनियों ने जुलाई माह में 18 करोड़ के मुकाबले केवल 13.5 करोड़ डोज की सप्लाई की।

अगस्त से बढ़ेगी टीके की सप्लाई

स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने टीकाकरण के 31 जुलाई के लक्ष्य के पीछे रहने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने में आई दिक्कतों के कारण भले ही इसे पूरा नहीं किया जा सका हो, लेकिन अगस्त से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ना सुनिश्चित है। उनके अनुसार अगस्त से भारत में बनने वाली स्पुतनिक-वी वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जायडस-कैडिला ने अपनी वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर आफ इंडिया से आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद अगस्त से उसकी वैक्सीन की भी सप्लाई शुरू हो जाएगी।

72 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं गुरुवार को राजधानी में, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। 24 घंटे में 69,212 सैंपल की जांच हुई। इसमें से 0.10 फीसद सैंपल पाजिटिव पाए गए।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 16 जुलाई, 2021

न्यूज गैलरी

चार हजार वकीलों की कोविड रिपोर्ट की होगी जांच

नई दिल्ली : बार काउंसिल आफ दिल्ली के सचिव पीयूष गुप्ता ने पत्र जारी कर सूचित किया है कि महामारी के बीच आर्थिक मदद पाने वाले चार हजार वकीलों की कोविड रिपोर्ट की जांच कराई जाएगी। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। 10 वकीलों की रिपोर्ट फर्जी पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। इन वकीलों ने फर्जी कोविड रिपोर्ट के आधार पर बीसीडी से आर्थिक मदद ली थी। इसके अलावा इन वकीलों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, साथ ही उन सभी रिपोर्ट की अलग-अलग पैथ लैब में जांच कराने का फैसला लिया गया है, जिनके आधार पर आर्थिक मदद ली गई थी। पीयूष गुप्ता ने कहा कि कुछ वकीलों द्वारा फर्जी तरीके से आर्थिक मदद लेना दु:खद है। उनकी वजह से वे लोग मदद से महरूम रह गए, जिन्हें असल में दरकार थी। (जासं)

अंतिम जिरह के लिए अटके मामलों की होगी सुनवाई

नई दिल्ली : राजधानी की सभी सात जिला अदालतों में अंतिम जिरह की प्रक्रिया में लंबित पड़े मामलों की जल्द ही सुनवाई शुरू होगी। कोविड-19 के चलते जिला अदालतों में फिलहाल अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होती है। अब प्रबंधन कमेटी ने सभी न्यायाधीशों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे मामलों की पहचान की जाए, जो अंतिम जिरह की प्रक्रिया में अटके हुए हैं। पहचान के बाद जल्द से जल्द इन मामलों के निपटान के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए शिकायतकर्ता से कोर्ट स्टाफ बातचीत कर वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करने के लिए राजी करेगा। अगर शिकायतकर्ता राजी हो जाता है तो मामले में जल्द से जल्द तारीख लगाकर फैसला सुनाया जाए। (जासं)

इग्नू में अब 31 जुलाई तक करें दाखिले के लिए पंजीकरण

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जुलाई सत्र में दाखिले के लिए पंजीकरण और पुन:पंजीकरण की अंतिम तिथि गुरुवार को फिर बढ़ा दी है। अब छात्र दाखिले के लिए 31 जुलाई तक पंजीकरण और पुन:पंजीकरण कर सकेंगे। इसमें नए छात्र पंजीकरण और पुराने छात्र अगले सेमेस्टर और वर्ष में दाखिले के लिए पुन:पंजीकरण कर सकेंगे। पहले इसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई को खत्म हो रही थी। इग्नू 200 से ज्यादा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कोर्स संचालित करता है। (वि)

तीन तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला

नई दिल्ली : जाफराबाद इलाके में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता मोमिना की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि बेटी के जन्म के बाद ससुराल वालों ने उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया था। ससुराल वालों ने आरोप ने इन्कार किया है। पुलिस के अनुसार मोमिना परिवार के साथ गली जाफराबाद में रहती हैं। वर्ष 2005 में मोमिना की शादी जाफराबाद निवासी राशिद से हुई थी। आरोप है शादी के कुछ बाद ससुराल वालों ने दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने पीटना शुरू कर दिया। गत 28 मई को पति ने शराब के नशे में पीड़िता को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। (जासं)

आज से लगेगा निमोनिया का मुफ्त टीका : केजरीवाल

नई दिल्ली : दिल्ली के स्वास्थ्य केंद्रों पर अब तक 12 बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता था, पर अब से इन सभी केंद्रों पर निमोनिया के लिए न्यूमोकोकल टीके की तीनों डोज बच्चों को मुफ्त लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम विहार स्थित पालीक्लीनिक से न्यूमोकोकल टीके की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण कदमों में से यह भी एक अहम कदम है। (जासं)

राज्य बताएं, कैसे लगाएंगे पराली जलाने पर लगाम

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संबंधित राज्यों से मांगा एक्शन प्लान

जागरण एक्सक्लूसिव

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

- चार विकल्प देकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मांगा एक्शन प्लान
- अभी तक पराली के प्रबंधन में विफल ही साबित हुए हैं संबंधित राज्य



पराली जलाने का दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फाइल

ये विकल्प सुझाए

- बायो डिकंपोजर का पराली के ऊपर छिड़काव।
- पराली को जमीन के नीचे दबाकर उस पर बायो डिकंपोजर डाला जाना।
- पराली को एकत्रित कर बिजली या ईंधन बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को देना।

सर्दी की दस्तक में बहुत लंबा समय नहीं रह गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर पराली प्रबंधन की समय रहते तैयारी भी जरूरी हो गई है। राज्यों के प्लान के आधार पर आयोग बाद में अपना केंद्रीय प्लान और दिशा- निर्देश जारी करेगा। -डा. के. जे. रमेश, तकनीकी सदस्य, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

कोराना की संभावित तीसरी लहर के बीच इस बार सर्दी में एनसीआर का दम न घुटे, इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संबंधित पांचों राज्यों से पराली प्रबंधन पर पुख्ता एक्शन प्लान मांगा है। यह प्लान 31 जुलाई तक देना होगा। पहली बार इन राज्यों को चार विकल्प भी दिए गए हैं। राज्यों को अपने एक्शन प्लान में आयोग को बताना होगा कि वे इनमें से कौन सा विकल्प अपनाएंगे।

गौरतलब है कि सितंबर से ही एनसीआर के मौसम में बदलाव और वायु गुणवत्ता खराब होने की शुरुआत हो जाती है। अक्टूबर में पराली जलाने की घटनाएं भी जोर पकड़ने लगती हैं। इन सबसे निपटने की तैयारी करने के लिए बमुश्किल दो माह का समय ही शेष बचा है। आयोग का मानना है कि कोरोना संक्रमण और वायु प्रदूषण दोनों ही सीधे फेफड़ों पर असर डालते हैं। ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर के दौरान पराली के धुएं ने हवा में जहर घोला तो ज्यादा विकट स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से पराली से निपटने के लिए अपना एक्शन प्लान जमा कराने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि आयोग के पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन के नियमों में से वह प्रविधान भी हटा दिया है जिसमें पराली जलाने के दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने और जेल भेजने का नियम था। ऐसे में अब इस समस्या से निपटना चुनौतीपूर्ण भी हो गया है और इसका समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाना भी बाध्यता बन गया है। विडंबना यह कि अभी तक पराली के प्रबंधन में सभी राज्य विफल ही साबित हुए हैं।

दिल्ली के ढांचागत विकास के लिए यूटीपैक की कई परियोजनाओं को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी के ढांचागत विकास को विश्व स्तरीय बनाने एवं लोगों की आवागमन संबंधी सुविधाओं में इजाफा करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई। लोगों की पैदल चलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए डीडीए की इंजीनियरिंग विंग यूनीफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर यानी यूटीपैक की गवर्निंग बाडी की 63वीं बैठक में आवागमन से जुड़ीं इन परियोजनाओं पर उपराज्यपाल (एलजी) और डीडीए के अध्यक्ष अनिल बैजल की मौजूदगी में चर्चा की गई। इसके बाद इनको मंजूरी दी गई।

डीडीए उपाध्यक्ष अनुराग जैन एवं अन्य संबंधित एजेंसियों की मौजूदगी में आइएनए मार्केट/मेट्रो स्टेशन के वाक प्लान, आइटीओ जंक्शन, हौजखास-आइआइटी दिल्ली, दिल्ली विवि (नार्थ और साउथ कैंपस) एवं कमला नगर व लाजपत नगर परियोजना को स्वीकृति दी गई। बैठक में नवादा, उत्तम नगर वेस्ट व जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन का मल्टी माडल इंटीग्रेशन परियोजना भी पास की गई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में गवर्निंग बाडी द्वारा पूर्व में पास की गईं परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। इस दौरान एलजी ने विभिन्न विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों को दी गई समय सीमा में परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए।

टीसी के बिना भी होगा सरकारी स्कूलों में दाखिला : सिसोदिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार ने अब बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के ही स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला देने का फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली का कोई भी बच्चा यदि निजी स्कूल से निकलकर सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो टीसी न होने की वजह से उसे दाखिले के लिए मना नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि बहुत से निजी स्कूल बच्चों को टीसी नहीं दे रहे हैं। वे उनसे एक साल की फीस मांग कर रहे हैं। इस वजह से बड़ी संख्या में अभिभावक चाह कर भी अपने बच्चों को निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा पा रहे हैं। कई अभिभावकों से ऐसी शिकायत मिलने के बाद ही इस बाबत शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया गया है। सिसोदिया ने कहा कि यदि स्कूल टीसी देने से मना कर रहा है तो बाकी दस्तावेज के आधार पर भी बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे चिंता न करें। बच्चों के पिछले स्कूल से टीसी लाने का काम शिक्षा निदेशालय स्वयं करेगा।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अभी तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली क्लास के लिए 28,000 आवेदन मिले हैं। छठी से 12वीं कक्षा के लिए 90,000 आवेदन आ चुके हैं। दाखिला सूची 20 जुलाई को जारी की जाएगी। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण में छठी से नवीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन नहीं कर पाने वाले छात्र 23 जुलाई से छह अगस्त के बीच आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं, 10वीं और 12वीं के आनलाइन आवेदन 20 जुलाई तक किए जा सकेंगे, जबकि 11वीं के लिए आवेदन दसवीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद किए जा सकेंगे।

'हमारे खिलाड़ी मेडल जीतकर करेंगे देश का नाम रोशन'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने टोक्यो आलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे दिल्ली के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी मेडल जीतकर दिल्ली और देश का नाम रोशन करेंगे। टोक्यो आलिंपिक में दिल्ली के चार खिलाड़ी मनिका बत्रा, दीपक कुमार, अमोज जैकब और सार्थक भांबरी टेबल टेनिस, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनमें से तीन खिलाड़ी मिशन एक्सीलेंस स्कीम का हिस्सा रहे हैं।

चर्च गिराने पर गलत बयान दे रहे हैं मुख्यमंत्री : बिधूड़ी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक चर्च गिराने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने खुद यह कार्रवाई की है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यह बात स्वीकार भी की है। अब लोगों को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री वहां राजनीतिक दौरे पर गए हुए हैं और वहां के ईसाई समुदाय से झूठ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के तहत आने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में चर्च को गिरा दिया है। सच्चाई यह है कि दक्षिण दिल्ली की जिला अधिकारी ने दिल्ली सरकार की तरफ से कार्रवाई करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के अन्य नेता पहले भी इस तरह की गलत बयानबाजी कर चुके हैं। उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे भी हुए थे। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी है।

शहरी वन्यजीव गलियारा बनाने की प्रक्रिया की शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

योजना

- गलियारा बनने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में तेंदुओं व अन्य वन्य जीवों की नहीं होगी मौत
- असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के पास सूरजकुंड-पाली मार्ग पर गलियारे के निर्माण की अनुशंसा सौंपी

दिल्ली के आसपास के वन क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीवों के लिए वन विभाग ने गलियारा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस गलियारे से तेंदुओं व अन्य वन्य जीवों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत नहीं होगी। दिल्ली वन विभाग के अधिकारियों ने एक सर्वेक्षण पूरा करने के बाद असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के पास सूरजकुंड-पाली मार्ग पर वन्यजीव गलियारे के निर्माण की अनुशंसा मुख्य वन्य जीव वार्डन को सौंप दी गई है। यह भारत में शहरी परिवेश में इस तरह का पहला मार्ग होगा। बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के दिल्ली प्रमुख सोहेल मदान के मुताबिक वन्य जीव अभयारण्यों के बीच से या सटे रास्तों से गुजरते हुए पिछले पांच सालों में करीब पांच तेंदुओं की मौत हुई है।

वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 28 जून की घटना के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) से पाली-सूरजकुंड मार्ग पर वन्य जीवों के लिए सुरक्षित रास्ते के निर्माण की संभावना का सर्वेक्षण कराने को कहा। डीएमआरसी ने इस दिशा में एक अंडरपास बनाने का सुझाव दिया है।

उन्होंने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में मुख्य वन्य जीव वार्डन को अनुशंसा सौंप दी है। अधिकारी ने कहा कि वन विभाग ने गलियारे की जरूरत पर तब जोर देना शुरू किया, जब दो वर्ष की मादा तेंदुआ को 28 जून को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर एक वाहन ने कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। सूरजकुंड-पाली मार्ग जहां यह घटना हुई थी, वहां छोटा सा मार्ग दिल्ली के दायरे में आता है, इसलिए दिल्ली सरकार गलियारे का निर्माण करेगी।

'सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न दें पीएम'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली



दिल्ली विधानसभा परिसर में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के चित्र का अनावरण करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। साथ में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। सौ. दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्यावरणविद स्व. सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित करने की अपील की है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे तो देश के बच्चे-बच्चे तक उनका संदेश पहुंचेगा। केजरीवाल ने बहुगुणा की स्मृति में दिल्ली विधानसभा परिसर में पौधारोपण कर उनके चित्र का अनावरण किया। इस अवसर पर सीएम ने बहुगुणा के पुत्र राजीव और प्रदीप को स्मृति चिह्न और शाल भेंट कर सम्मानित भी किया। साथ ही उनके परिवार को सम्मान स्वरूप एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया।

केजरीवाल ने कहा कि बहुगुणा के जीवन का एक-एक क्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। वह न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उनका पर्यावरण प्रेम विश्व विख्यात था। आज समस्त मानव जाति समझ रही है कि पर्यावरण कितनी महत्वपूर्ण चीज है। यदि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ जारी रहा तो शायद एक समय आए, जब मानव जाति ही न बचे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में स्व. बहुगुणा का चित्र उन सभी लोगों के साथ लगा है, जिन्होंने भारत को आदर्श बनाने में काम किया है। जिनकी बदौलत हमारे देश में लोकतंत्र है और जिनकी बदौलत हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये लोग हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि बहुगुणा ने सातवें दशक में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने आंदोलन के जरिये यही संदेश दिया कि पर्यावरण को बचाना कितना आवश्यक है।

16 से 22 जुलाई तक पूरा करना होगा 11वीं-12वीं के अंकों का माडरेशन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली



केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को दिया निर्देश

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं का परिणाम जारी करने से पहले स्कूलों को 11वीं-12वीं के अंकों का अनुशोधन (माडरेशन) कार्य पूरा करने के लिए पोर्टल खोला है। सीबीएसई ने स्कूलों को एक आधिकारिक नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वह 11वीं-12वीं के अंकों का माडरेशन कार्य निष्पक्षता के साथ 16 से 22 जुलाई तक पूरा करे। बोर्ड के मुताबिक यदि कोई स्कूल इस निर्धारित समय सीमा के अंदर माडरेशन को पूरा करने में विफल होता है तो उनका परिणाम 31 जुलाई के बाद अलग से घोषित किया जाएगा।

बोर्ड के मुताबिक स्कूलों के समक्ष माडरेशन प्रक्रिया बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस नीति में किसी भी तरह के अंतर की वजह से कुछ छात्रों को लाभ या नुकसान हो सकता है। ऐसे में स्कूलों को अनिवार्य रूप से निष्पक्ष तरीके से अंक देने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी छात्र को किसी भी तरह का नुकसान या फायदा न हो। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई को जारी किया जाएगा।

क्या है माडरेशन प्रक्रिया

सीबीएसई ने 12वीं का परिणाम जारी करने के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं में मिले अंकों को आधार बनाया है। इसमें स्कूलों ने सीबीएसई के पोर्टल पर छात्रों को 11वीं और 12वीं में मिले मूल अंक अपलोड कर दिए। स्कूलों की ओर से अंक अपलोड करने के बाद सीबीएसई ने पोर्टल को लाक कर दिया। अब सीबीएसई 16 जुलाई से फिर से पोर्टल खोल रहा है। स्कूलों को इसमें पहले से ही अपलोड किए गए अंकों का माडरेशन करना होगा। इसमें स्कूल मूल अंक में से पांच अंक बढ़ा या पांच अंक कम कर सकते हैं।

आंतरिक मूल्यांकन से डीयू जारी करेगा यूजी व पीजी के परिणाम

जासं, नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) सत्र 2020-21 के स्नातक और परास्नातक के इंटरमीडिएट सेमेस्टर/टर्म/वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं नहीं लेगा। इन छात्रों का परिणाम अब आंतरिक मूल्यांकन के जरिए जारी किया जाएगा। डीयू की परीक्षा शाखा के डीन ने इस संबंध में परिपत्र जारी करते हुए कहा कि जो भी छात्र स्नातक के दूसरे या चौथे सेमेस्टर में और परास्नातक के दूसरे सेमेस्टर में हैं, उनका परिणाम अब बिना परीक्षा लिए ही जारी किया जाएगा।

परिणाम जारी करने के लिए 50 फीसद अंक असाइनमेंट आधारित या आंतरिक मूल्यांकन के जरिए और 50 फीसद अंक पिछले सेमेस्टर के प्रदर्शन के आधार पर जोड़े जाएंगे। जिन छात्रों का पिछले सेमेस्टर की परीक्षा का प्रदर्शन नहीं होगा तो उनके पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़े जाएंगे। स्कूल आफ ओपन लर्निंग (एसओएल) व नान कालेजिएट वूमेन एजुकेशन बोर्ड (एनसीडब्ल्यूईबी) के छात्रों का परिणाम भी आंतरिक मूल्यांकन के जरिए जारी किया जाएगा।

शरजील इमाम ने राजद्रोह के मामले में मांगी जमानत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार जवाहरलाल नेहरू विवि (जेएनयू) छात्र शरजील इमाम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के केस में जमानत अर्जी दायर की है। आरोप है कि शरजील इमाम ने अपने भाषण में असम और पूर्वोत्तर के शेष हिस्सों को भारत से 'काटने' की धमकी थी। इस बीच, कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत 13 आरोपितों की न्यायिक हिरासत 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। दंगे में नाम आने के बाद आप ने ताहिर को पार्टी से बाहर कर दिया था।

शरजील ने नागरिकता संशोधन (सीएए) कानून व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विवि में भाषण दिया था। जिसे भड़काऊ बताते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में शरजील इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने दावा किया कि उनका मुवक्किल हिंसा में शामिल नहीं रहा और न ही हिंसा को भड़काने में सहयोग किया। उन्होंने भाषणों के कुछ अंश कोर्ट में पढ़े और कहा कि वह राजद्रोह कानून के दायरे में नहीं आते। अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।

दिल्ली दंगा

तसलीम ने जान का खतरा बताया

दंगे की साजिश के मामले में रोहिणी जेल में बंद आरोपित तसलीम अहमद ने आनलाइन पेश होकर न्यायाधीश के समक्ष जान का खतरा बताते हुए जेल बदलने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि एक से दूसरी जेल में आरोपित को भेजने का निर्णय संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। बता दें, दिल्ली दंगे में 53 लोगों की जान गई थी, जबकि 550 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

कोरोना में जान गंवाने वाले डाक्टरों की याद में स्मारक बनें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) और इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबीइंग (आइएचडब्ल्यू) काउंसिल ने गुरुवार को कोरोना से मरने वाले डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए नेशनल ग्रेटिट्यूड मेमोरियल स्थापित करने की मांग की। दोनों संस्थाओं ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सभी डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का योगदान और बलिदान अनुकरणीय है।

आइएमए का दावा है कि देशभर में कोरोना से 1,500 डाक्टरों की जान गई है। आइएचडब्ल्यू द्वारा राष्ट्रीय धन्यवाद पहल के तहत पहली लहर के दौरान 2020 में मनाए गए ग्रेटिट्यूड वीक फार हेल्थ गार्जियंस (एक से सात जुलाई) के दौरान यह मांग उठाई गई थी। तब से आइएचडब्ल्यू विभिन्न स्वास्थ्य मंचों पर इस मांग को उठा रहा है। दोनों संगठनों ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि वे संयुक्त रूप से पीएम और दिल्ली के सीएम को कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले डाक्टरों की याद में राष्ट्रीय व दिल्ली राज्य स्मारक स्थापित करने के लिए पत्र लिखेंगे।

मौसम का हाल

दिन भर रही तेज धूप, दिल्लीवासी पसीना पोछते नजर आए, तापमान में दर्ज किया गया थोड़ा इजाफा

उमस से मानसून हुआ पसीना-पसीना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दस्तक के तीसरे दिन मानसून की बारिश के ब्रेक ले लेने से उमस भरी गर्मी एक बार फिर से बढ़ गई। तेज धूप में दिन भर दिल्लीवासी पसीना पोछते नजर आए। तापमान में थोड़ा इजाफा दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं। शनिवार से बारिश के दोबारा जोर पकड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में आरेंज व यलो अलर्ट भी जारी किया है।

मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 36.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री कम 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 26.3 मिमी बारिश रिकार्ड हुई है। हवा में नमी का स्तर 57 से 100 फीसद रहा। सुबह के समय कुछ देर के लिए बादलों ने डेरा डाला और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन इससे उमस और बढ़ गई।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 और 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद से शनिवार से झमाझम बारिश का दौर शुरू होने को लेकर विभाग ने आरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बाकी दिनों के लिए विभाग का यलो अलर्ट है।

संतोषजनक श्रेणी में रही दिल्ली-एनसीआर की हवा: दिल्ली-एनसीआर की हवा गुरुवार को संतोषजनक श्रेणी में रही। अगले 24 घंटों में भी हवा की गुणवत्ता में अधिक बदलाव नहीं होने की संभावना है। एनसीआर में सबसे साफ हवा गाजियाबाद की 64 एयर इंडेक्स के साथ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली का एयर इंडेक्स 83 रहा। फरीदाबाद का 141, ग्रेटर नोएडा का 68, गुरुग्राम का 68 व नोएडा का 70 एयर इंडेक्स रहा। सफर इंडिया के मुताबिक बारिश की संभावना को देखते हुए अगले तीन दिनों तक हवा की गुणवत्ता में बदलाव की उम्मीद नहीं है। पिछले 24 घंटों में हवा में पीएम 10 का स्तर 67 व पीएम 2.5 का स्तर 34 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर रहा।

बारिश से ढहा कुतुबमीनार परिसर की चहारदीवारी का कुछ हिस्सा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: राजधानी में बुधवार को हुई झमाझम बारिश से कुतुबमीनार परिसर की चारदीवारी का कुछ हिस्सा ढह गया। 30 मीटर लंबी दीवार बरसात के पानी की वजह से ढह गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। जिस जगह दीवार गिरी है उसके बगल में से नाला होकर गुजरता है। नाले का पानी दीवार से रिसकर अंदर परिसर में आ गया। इससे दीवार गिर गई। इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

मुख्यमंत्री आवास का पानी कनेक्शन काटेगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी के कई इलाकों में जल संकट के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता शुक्रवार को सीएम आवास का घेराव करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास का पानी कनेक्शन काटने की भी चेतावनी दी गई है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि जल संकट दूर करने को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है। सरकार की लापरवाही से लोग बूंद-बूंद शुद्ध जल के लिए तरस रहे हैं। पानी की किल्लत के विरोध में दो दिन पहले भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष व दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने पानी कनेक्शन काटने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। उसी दिन 48 घंटे में समस्या दूर नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास का पानी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई थी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे।

सुरक्षा के साथ बेहतर शिक्षा भी मुहैया करा रही है दिल्ली पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था देने के साथ ही दिल्ली पुलिस बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने पर भी जोर दे रही है। पुलिस फाउंडेशन फार एजुकेशन दिल्ली (पीएफइडी) और दिल्ली पुलिस की ओर से राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में तीन स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ये स्कूल अन्य स्कूलों से इसलिए अलग हैं क्योंकि इनमें छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ ही उन्हें सामाजिक सरोकार से जुड़ा ज्ञान व पुलिस अधिकारियों का समय-समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। अत्याधुनिक कक्षाएं व प्रयोगशालाओं के जरिये छात्रों को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। खेलकूद में रुचि रखने वाले छात्रों को विशेष रूप से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। खास बात यह है कि इन स्कूलों में पुलिसकर्मियों के बच्चों के साथ ही सामान्य वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं जो पुलिसकर्मी सेवा के दौरान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उनके बच्चों को पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इन स्कूलों की तरह अब अन्य राज्यों की पुलिस भी इसी तरह के स्कूल खोलने का मन बना रही है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पर काम करना शुरू किया है। इसके लिए यूपी पुलिस पीएफइडी से जरूरी सलाह ले रही है।

क्या है पीएफइडी

पुलिस फाउंडेशन फार एजुकेशन दिल्ली (पीएफइडी) की स्थापना वर्ष 1986 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई है। पीएफइडी को सामाजिक कार्यकर्ताओं व दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यह है कि पुलिसकर्मियों के बच्चों को सस्ती और गुणात्मक शिक्षा प्रदान किया जा सके।

19 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार 17 बिल पेश कर उन्हें पास कराने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में छह बिल अलग-अलग समितियों के पास लंबित हैं। सरकार उनको भी इसी सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी।

'नई पीढ़ी का कौशल विकास राष्ट्रीय जरूरत'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विश्व युवा कौशल दिवस पर पीएम ने कहा-जो स्किल्ड होगा, वही आगे बढ़ेगा
- स्किल इंडिया मिशन को नए सिरे से गति देने की जरूरत बताई



नई दिल्ली में गुरुवार को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएनआइ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीढ़ी के स्किल पर जोर देते हुए कहा कि देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाने का जिम्मा अब 21वीं सदी में पैदा हुए युवाओं का है। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा के साथ सभी को कौशल (स्किल) में भी दक्ष बनाया जाए। नई पीढ़ी का कौशल विकास राष्ट्रीय जरूरत है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का बड़ा आधार भी है। पीएम ने इस दौरान स्किल इंडिया मिशन को भी नए सिरे से गति देने की जरूरत बताई।

प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज स्किल की इतनी मांग है कि जो स्किल्ड होगा, वही अब तरक्की करेगा। यह बात व्यक्तियों के साथ देश पर भी लागू होती है। दुनिया को एक स्मार्ट और स्किल्ड मैनपावर हम दे सकें, यह हमारी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। इसको देखते हुए फिलहाल ग्लोबल स्किल गैप की मैपिंग की जा रही है। इसलिए नई पीढ़ी को स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग करने का अभियान लगातार चलते रहना चाहिए।

पीएम ने कहा कि आज बड़े-बड़े विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह से टेक्नोलाजी बदल रही है, ऐसे में आने वाले तीन से चार वर्षों में बड़ी संख्या में लोगों को री-स्किलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी देश को तैयार रहना होगा। वैसे भी कोरोना काल में स्किल और स्किल्ड लोगों की अहमियत देश ने बहुत करीब से देखी है। देश कोरोना की लड़ाई को प्रभावी ढंग से लड़ सका तो इसमें भी हमारे स्किल्ड लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पीएम ने कहा कि स्किल पहले से ही हमारे समाज का हिस्सा है। हमारे यहां विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश जैसे आयोजनों में स्किल का सम्मान होता है। इस दौरान बढ़ई, कुम्हार, बुनकर आदि का काम करने वालों को विशेष सम्मान दिया जाता है। पीएम ने इस मौके पर बाबा साहब आंबेडकर को भी याद किया और कहा कि वह युवाओं और कमजोर वर्ग को हुनरमंद बनाने पर सदैव जोर देते थे। उनके इसी सपने को स्किल इंडिया के जरिये पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। मंत्रालय ने इस दौरान 75 नए जन शिक्षण संस्थान खोलने की भी मंजूरी दी।

आपका हुनर ही बनेगा पहचान, होगा प्रमाणीकरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संस्था एनआइओएस ने कौशल विकास मंत्रालय ने मिलकर बनाई योजना
- नई नौकरी पाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रमाण पत्र दिखाने से चलेगा काम

पढ़ाई छोड़कर किसी छोटे-मोटे काम धंधे में लगे लोगों के लिए उनका यही हुनर अब उनकी पहचान बनेगा। इसका उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके जरिये वे आसानी से भविष्य में अपने लिए नई राहें भी चुन सकेंगे। कौशल विकास को बढ़ावा देने में जुटी सरकार देश भर के पढ़े-लिखे और अनपढ़ कामगारों के हुनर का प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) करने की तैयारी में है। यानी उनके पास पढ़ाई का भले ही कोई प्रमाण पत्र न हो, लेकिन अपने हुनर का प्रमाण पत्र जरूर होगा।

अलग-अलग क्षेत्र के स्किल के लिए तय होंगे मानकः इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआइओएस) ने कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर एक बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्र के हुनर (स्किल) के लिए मानक तय होंगे। पहले चरण में इनमें करीब 200 क्षेत्र के हुनर शामिल करने की योजना बनाई गई है। इनमें बढ़ई, मिट्टी के बर्तन बनाना, मैकेनिक, सिलाई-कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, माली का काम आदि शामिल हैं।

हुनर का प्रमाण पत्र दिखाकर कहीं भी आसानी से हासिल कर सकेंगे नौकरी : मंत्रालय की मानना है कि मौजूदा समय में इस क्षेत्र में लगे लोगों की कोई पहचान नहीं है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नौकरी पाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास अपने काम का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। अब प्रमाणीकरण से इस तरह की समस्याओं का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। वे अपने हुनर का प्रमाण पत्र दिखाकर आसानी से कहीं भी नौकरी हासिल कर सकेंगे। एनआइओएस की चेयरमैन प्रोफेसर सरोज शर्मा के मुताबिक, कौशल विकास मंत्रालय के साथ करार किया गया है। जल्द ही प्रमाणीकरण से जुड़े कोर्स को शुरू करेंगे। इनमें पढ़े-लिखे होने या नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं आएगी।

हुनर से जुड़े बदलावों को लेकर प्रशिक्षण भी मिलेगा

इस पहल के साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के हुनर से जुड़े लोगों के लिए तकनीकी बदलाव सीखने और अपने हुनर को मजबूत बनाने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। इसमें जरूरत को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को समय रहते हुनर में दक्ष बनाया जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे वे उस क्षेत्र में आगे भी अपनी सेवाएं देते रहेंगे अन्यथा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बता दें कि सरकार का पूरा फोकस इस समय सभी को हुनर से जोड़ना है।

सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए काम करेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाकर इससे जुड़े करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्प के साथ काम करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मंत्रियों के विभागों को फिर से आवंटित किए जाने के एक सप्ताह बाद सहकार भारती के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद शाह ने यह बात कही। शाह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शाह ने ट्वीट किया, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य के नेतृत्व में इसके प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त कर इससे जुड़े करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें संकल्पित भावना से कार्य करना है। सहकार भारती के अनुसार, यह सहकारी समितियों का एकमात्र अखिल भारतीय संगठन है। यह ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में सहकारी समितियों का एक मजबूत और समर्पित संवर्ग और सहकारी समितियों की एक श्रृंखला बनाने की परिकल्पना करता है।

अफगानिस्तान पर टाप गियर में भारतीय कूटनीति

कठिन चुनौती ▶ राष्ट्रपति अशरफ घनी व अमेरिकी प्रतिनिधि खलीलजाद के साथ हुई जयशंकर की अहम वार्ता

शुक्रवार को पाक पीएम इमरान के साथ मंच साझा करेंगे भारतीय विदेश मंत्री

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली



भारत के विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर ताजिकिस्तान के अपने समकक्ष सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन के साथ। जयशंकर अफगानिस्तान के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ उन देशों के नेताओं से भी लगातार विमर्श कर रहे हैं, जिनकी अफगानिस्तान में गहरी रुचि है। प्रेट्र

अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को देख भारत की कूटनीतिक गतिविधियां भी काफी तेज हो गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर न सिर्फ अफगानिस्तान के शीर्ष नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, बल्कि वहां के हालात को लेकर जिन दूसरे देशों की गहरी रुचि हैं उनके साथ भी लगातार विमर्श कर रहे हैं।

पिछले तीन दिनों में दुशांबे (ताजिकिस्तान) में कई देशों के साथ विमर्श के बाद जयशंकर गुरुवार को ताशकंद (उज्बेकिस्तान) पहुंचे हैं, जहां शुक्रवार को एक अहम बैठक में वह हिस्सा लेंगे। इस बैठक में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, अफगान मामले पर अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जाल्मई खलीलजाद समेत कई मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेता होंगे। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की अमेरिका, रूस और चीन के साथ अलग अलग स्तर पर संपर्क में है। गुरुवार का दिन विदेश मंत्री जयशंकर के लिए काफी गतिविधियों वाला रहा। पहले उनकी दुशांबे में ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और जब वे ताशकंद पहुंचे तो वहां कजाखस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिल्यूबर्दी के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों बैठकों में अफगानिस्तान का मुद्दा ही प्रमुखता से उठा। ये दोनों देश अफगानिस्तान के बिगड़ रहे हालात से सबसे ज्यादा चिंतित भी हैं। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री के बाद जयशंकर ने कहा है कि बदले माहौल में भारत-ताजिकिस्तान के रणनीतिक रिश्ते पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं।

इसके बाद जयशंकर के नेतृत्व में भारतीय दल की राष्ट्रपति घनी व उनके सहयोगियों के बीच ताशकंद में अहम बातचीत हुई है। इस बैठक के कुछ ही देर बार जयशंकर की अमेरिकी राष्ट्रपति की होमलैंड सिक्यूरिटी सलाहकार लिज शेरवुड रैंडाल और अफगान शांति वार्ता पर अमेरिकी प्रतिनिधि खलीलजाद के साथ एक संयुक्त बैठक हुई है। यह पिछले कुछ दिनों में खलीलजाद व अमेरिकी टीम के साथ भारतीय विदेश मंत्री की दूसरी बैठक है। इन सभी बैठकों में होने वाली मंत्रणा के बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है लेकिन इससे साफ है कि भारत 20 वर्ष पहले की स्थिति नहीं दोहराना चाहता जब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के समर्थन से तालिबानियों का कब्जा हो गया और कोई भी देश कुछ नहीं कर सका। विदेश मंत्री ने बुधवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में जो तीन सूत्रीय फार्मूला पेश किया है उसका मकसद यही है कि सभी संबंधित देश एक उग्रवाद समर्थक तालिबान के खतरे को समझ सके।

दूसरे देशों के बीच भी कई स्तरों पर चल रही बातचीत

अफगानिस्तान को लेकर दूसरे देशों के बीच भी कई स्तरों पर बातचीत चल रही है। स्वयं राष्ट्रपति घनी ताशकंद में शुक्रवार को होने वाली कनेक्टिविटी समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। वह अपने सभी पड़ोसी देशों के प्रमुखों से मिल कर तालिबान को शांति वार्ता के लिए तैयार करने के लिए कह रहे हैं। शुक्रवार को होने वाली बैठक का विषय वैसे तो सेंट्रल व साउथ एशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी परियोजना के भविष्य रखा गया है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर इसमें अफगानिस्तान के हालात पर ही चर्चाएं होने वाली हैं। पाकिस्तान सरकार इसको बहुत महत्व दे रही है।

पीएम इमरान खान, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इसमें हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान यह बताने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान के आने के बावजूद अफगानिस्तान से गुजरने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाओं को कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ भारत समेत दूसरे मध्य एशियाई देश तालिबान की बढ़ती ताकत को लेकर आशंकित हैं। भारत की कनेक्टिविटी परियोजना जो ईरान के चाबहार से जुड़ा है, अफगानिस्तान की अस्थिरता उसको भी प्रभावित करेगी। इस बैठक में अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस की तरफ से भी महत्वपूर्ण नेताओं को हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है।

विधायक विधानसभा में रिवाल्वर निकाल ले तो क्या उस पर केस दर्ज नहीं होगा

- सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानसभा में तोड़फोड़ के मामले की सुनवाई के दौरान किया सवाल
- राज्य सरकार ने विशेषाधिकार और छूट की दलील देकर की है आरोपित विधायकों के खिलाफ मामला रद करने की मांग



सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम मामले पर सुनवाई। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक उदाहरण देते हुए सवाल किया कि अगर एक विधायक विधानसभा में रिवाल्वर निकाल ले और उसे खाली कर दे तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा। क्या कोई कह सकता है कि सदन के भीतर का कृत्य होने के कारण उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा सकता और क्या कोई सदन की सर्वोच्चता का दावा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न केरल सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान किया जिसमें सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार के शिक्षा मंत्री वी. शिवकुट्टी समेत छह सदस्यों के खिलाफ अभियोजन रद करने की मांग की गई है। 2015 में विपक्ष में रहते हुए इन सदस्यों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की थी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए केरल सरकार से पूछा कि क्या सदन के ऐसे सदस्यों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की मांग करना न्यायोचित होगा जिन्होंने लोकतंत्र के गर्भगृह में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दरअसल, 13 मार्च, 2015 को तत्कालीन विपक्ष के एलडीएफ सदस्यों ने भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे तत्कालीन वित्त मंत्री केएम मणि को बजट पेश करने से रोकने के लिए सदन में तोड़फोड़ की थी। उन्होंने स्पीकर की कुर्सी को पोडियम से उठाकर फेंक दिया था और पीठासीन अधिकारी की डेस्क पर लगे कंप्यूटर, की-बोर्ड और माइक जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका : केरल हाई कोर्ट ने 12 मार्च को जारी अपने आदेश में राज्य सरकार की याचिका को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से सदन की प्रतिष्ठा बनाए रखने की उम्मीद की जाती है।

शीर्ष अदालत की यह थी चिंता

- सदन के भीतर बोलने की आजादी है, इसमें कोई संदेह नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सर वकीलों में गर्मागर्म बहस होती है, लेकिन क्या इससे अदालत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जायज हो जाएगा?
- विधानसभा में हो या सुप्रीम कोर्ट में, सभी संपत्तियां सरकार की हैं और सरकार ही सभी सार्वजनिक संपत्तियों की संरक्षक है। बचाव में दलीलें देकर सरकार केस क्यों वापस लेना चाहती है, यह तो आरोपितों को करना चाहिए?
- पांच जुलाई को भी शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसे संसद और विधानसभाओं में सदस्यों के उपद्रवी व्यवहार पर कड़ा रुख अपनाना होगा क्योंकि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और इस तरह के आचरण को माफ नहीं किया जा सकता।

केरल सरकार की दलील

- यह राजनीति अभिव्यक्ति का मामला। यह विरोध था और बोलने की तरह विरोध के अधिकार को भी सदन में मान्यता प्राप्त है। विशेषाधिकार और छूट हासिल होने का दिया हवाला।
- विधानसभा सचिव की ओर से दर्ज कराई गई एफआइआर की कोई संवैधानिक वैधता नहीं क्योंकि स्पीकर ने इसकी मंजूरी नहीं दी।

सीमा संबंधी मामलों का स्वीकार्य समाधान खोजने को चीन तैयार

बीजिंग, प्रेट्र : भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति के लंबे समय तक बने रहने के कारण द्विपक्षीय संबंध स्पष्ट रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके बाद चीन ने गुरुवार को कहा कि वह उन मामलों का आपस में स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए तैयार है, जिन्हें वार्ता के जरिये तुरंत सुलझाए जाने की आवश्यकता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के एक सम्मेलन के इतर बुधवार को एक घंटे तक चली बैठक के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति में कोई भी एकतरफा बदलाव भारत को स्वीकार्य नहीं है।

ताजिकिस्तान की राजधानी में यह बैठक ऐसे समय में हुई जब पूर्वी लद्दाख में टकराव के शेष बिंदुओं पर दोनों सेनाओं के बीच बलों को पीछे हटाने की प्रक्रिया में गतिरोध बना हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी बेवसाइट पर जयशंकर और वांग यी के बीच हुई वार्ता के संबंध में पोस्ट किए गए बयान में बताया कि मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के संबंध निचले स्तर पर बने हुए हैं, जबकि गलवन घाटी एवं पैंगोंग झील से बलों की वापसी के बाद सीमा पर हालात आमतौर पर सुधर रहे हैं। वांग ने कहा कि चीन उन मामलों का आपस में स्वीकार्य समाधान खोजने को तैयार है, जिन्हें भारतीय पक्ष के साथ वार्ता और विचार-विमर्श के जरिये तत्काल सुलझाए जाने की जरूरत है।

चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया कि वांग ने तत्काल समाधान की आवश्यकता वाले मामलों के आपस में स्वीकार्य समाधान के लिए वार्ता करने पर सहमति जताई और कहा कि दोनों पक्षों को सीमा संबंधी मामले को द्विपक्षीय संबंधों में उचित स्थान पर रखना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग के सकारात्मक पहलुओं को विस्तार देकर वार्ता के जरिये मतभेदों के समाधान के लिए अनुकूल माहौल पैदा करना चाहिए।

वांग ने कहा कि चीन-भारत संबंधों के सिद्धांत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति आपसी सम्मान, गैर-आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और एक-दूसरे के हितों के प्रति आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। वांग ने कहा कि चीन और भारत आज अपने-अपने क्षेत्रों और बड़े पैमाने पर दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमें अपने साझा रणनीतिक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और दोनों देशों के लोगों को अधिक लाभ पहुंचाना चाहिए।

राजद्रोह कानून पर कोर्ट की टिप्पणी का विपक्षी नेताओं ने किया स्वागत

- राहुल के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया
- कई फिल्मी हस्तियों ने कोर्ट के रुख का किया समर्थन

नई दिल्ली, प्रेट्र : विपक्षी दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से यह पूछे जाने का स्वागत किया है कि क्या देश में आजादी के 75 वर्ष बाद भी राजद्रोह कानून की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह संबंधी दंडात्मक कानून के भारी दुरुपयोग पर गुरुवार को चिंता व्यक्त की और केंद्र से सवाल किया कि स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के वास्ते महात्मा गांधी जैसे लोगों को 'चुप' कराने के लिए ब्रितानी शासनकाल में इस्तेमाल किए गए प्रविधान को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा।

सुप्रीम कोर्ट के रुख पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम शीर्ष अदालत की टिप्पणी का स्वागत करते हैं। इस पर भाजपा के महासचिव सीटी रवि ने पलटवार करते हुए कहा 2004 से 2014 तक आप सत्ता में दस साल कर तब आप क्या करते रहे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस कानून को खत्म करने के लिए आपकी सरकार को किसने रोक रखा था। हां, याद आया तब आप लोग देश को लूटने में व्यस्त थे।

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव समेत कुछ नेताओं ने इस ओर इशारा किया कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष की कार पर हमले के सिलसिले में राज्य में करीब 100 किसानों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। मोइत्रा ने कहा कि अब उन्हें आखिरकार उम्मीद है कि इस पुरातनकालीन कानून का भारत सरकार द्वारा दुरुपयोग समाप्त होगा। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कोर्ट की टिप्पणी पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन ट्वीट किया कि हरियाणा के किसानों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को फौरन और बिना शर्त आरोप वापस लेने चाहिए। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि असहमति को दबाने के लिए राजद्रोह के इस औपनिवेशिक काल के कानून के पूरी तरह दुरुपयोग पर सरकार से सवाल करने के लिए शीर्ष अदालत और चीफ जस्टिस की प्रशंसा होनी चाहिए।

अभिनेत्री और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि क्या आजादी के 75 साल बाद भी हमें इसकी जरूरत है। फिल्मकार और पूर्व सांसद प्रीतीश नंदी ने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल के सभी अवशेषों को समाप्त करने की बात होती है लेकिन इस भयावह कानून को समाप्त नहीं किया जाता जिसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला जाता था।

अरुण शौरी भी राजद्रोह कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर राजद्रोह कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया। याचिका, शौरी और गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) कामन काज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दायर की है। यह याचिका ऐसे दिन दायर की गई है, जब चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस कानून के भारी दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की।

शौरी की याचिका में दावा किया गया है कि राजद्रोह की परिभाषा (आइपीसी की धारा 124 ए) अस्पष्ट है। याचिका में कहा गया है कि यह एक औपनिवेशिक कानून है और इसका इस्तेमाल भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा असहमति की आवाज को दबाने में किया जाता था।

सियासी दौरा

बंगाल में तीसरी जीत के बाद पहली बार दिल्ली आ रहीं दीदी मानसून सत्र के दौरान राजधानी के सियासी पारे को बढ़ाएंगी, सोनिया गांधी, देवेगौड़ा, पवार, अखिलेश, केजरीवाल, फारूक समेत कई बड़े विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात

विपक्षी सियासत को मजबूती देने की पहल करेंगी ममता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली



तैयारी : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली के सियासी तापमान को बढ़ाएंगी। चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहीं दीदी भाजपा को चुनौती देने के लिए विपक्षी राजनीति को मजबूत बनाने की अपनी पहल को आगे बढ़ाएंगी। इस कोशिश के तहत ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जनता दल (सेक्यूलर) प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, राकांपा प्रमुख शरद पवार से लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगी।

तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी के 25 जुलाई को दिल्ली आने के कार्यक्रम के एलान के तत्काल बाद ही विपक्षी सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया। भाजपा के सारे सियासी चक्रव्यूहों को तोड़कर ममता ने बंगाल में न केवल तीसरी बार वापसी की है बल्कि अब तक की अपनी सबसे बड़ी चुनावी जीत भी दर्ज की है।

चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं के आक्रामक हमलों के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाने से बढ़े आत्मविश्वास के बाद दीदी ने भाजपा को चुनौती देने के लिए अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा साफ कर दी थी। इसकी शुरुआत ममता ने चुनाव के दौरान ही कर दी थी जब उन्होंने सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर भाजपा के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने की बात कही थी। चुनाव नतीजे के बाद 2024 में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी के लिए ममता ने खुद पहल करने की घोषणा भी की थी।

ममता ने इस पहल को गति देने और विपक्षी एकजुटता के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी सक्रिय रखा है। प्रशांत बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा शरद पवार समेत कुछ अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर इस सिलसिले में चर्चा कर चुके हैं। मानसून सत्र के दौरान चार-पांच दिनों के लिए दिल्ली आ रहीं ममता बनर्जी अब खुद इस पहल को आगे बढ़ाएंगी। सोनिया गांधी और शरद पवार से उनकी मुलाकात तो तय ही है। अखिलेश यादव, द्रमुक नेता टीआर बालू, आप के प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा उनकी मुलाकात नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से भी होने की संभावना है।

26 अगस्त से दो सितंबर के बीच होगा जेईई-मेन का चौथा संस्करण

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई-मेन के चौथे संस्करण को स्थगित कर दिया गया है और अब यह परीक्षा 26 अगस्त से दो सितंबर के बीच होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को बताया कि यह फैसला इस अहम परीक्षा के बीच छात्रों को चार सप्ताह का समय देने के लिए किया गया है। इससे पहले जेईई-मेन का चौथा संस्करण 27 जुलाई से दो अगस्त के बीच आयोजित करने का प्रस्ताव था। प्रधान ने ट्वीट किया, छात्र समुदाय की भारी मांग और अभ्यर्थियों को अधिकतम प्रदर्शन करने में सहायता के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जेईई-मेन, 2021 के दो सत्रों के बीच चार हफ्ते का अंतर रखने की सलाह दी थी। इसी के तहत जेईई-मेन, 2021 का चौथा सत्र अब 26, 27, 31 अगस्त और एक व दो सितंबर को आयोजित किया जाएगा। जेईई-मेन, 2021 के चौथे सत्र के लिए अब तक 7.32 लाख उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी



6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल। राज्यपाल ने इसको लेकर विभाग की ओर से प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 16 जुलाई, 2021

काशी के मंच से योगी के यूपी माडल पर मोदी ने लगाई मुहर

जमकर सराहा ▸ प्रधानमंत्री ने छह बार योगी का नाम लेकर गिनाईं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां

माफिया राज पर नकेल और कुशल कोरोना प्रबंधन का श्रेय मुख्यमंत्री को दिया

भारतीय बसंत कुमार, वाराणसी

बीएचयू के टेक्नोग्राउंड की सभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री के आने से चंद मिनट पहले मंच के ध्वनिविस्तारक यंत्र से रिकार्डिंग बज रही थी- 'गोरखपुर बोले, जौनपुर बोले... सुल्तानपुर बोले श्री योगी-श्री योगी।' यह संयोग ही हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ तो 'कर्मठ मुख्यमंत्री' के साथ 'श्री' से शुरू योगी की तारीफ के बोल प्रधानमंत्री के मुख से कई-कई बार दोहराए गए। उन्होंने जीभर कर तारीफ की। उपलब्धियों के कारक भी गिनाए। इस साल प्रधानमंत्री की यह पहली काशी यात्रा थी, लेकिन राजनीतिक हलकों में आज की उनकी तारीफ का संदेश संगठन से लेकर जनता तक बहुत कुछ स्पष्ट कर गया। यह केवल योगी सरकार के कामकाज की श्रेष्ठता पर लगी 'मोदी मुहर' नहीं थी, यह भविष्य का संकेतक गढ़ने वाली सुस्पष्ट घोषणा भी थी।

दरअसल, काशी यात्रा के बहाने प्रधानमंत्री ने अपने सात साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी रख दिया। भले ही प्रदेश के चुनाव की एक शब्द चर्चा नहीं हुई, लेकिन यूपी के सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बयां करके पीएम लोगों के जेहन में इसे बैठा गए। इस तरह काशी से मोदी पूरे यूपी को साध गए। मोदी के साथ एक मंच पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह थे तो दूसरी सभा के मंच पर थे पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह।



वाराणसी में जापान के सहयोग से बने 'रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर' के लोकार्पण अवसर पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंटर का माडल भेंट करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एएनआइ

प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में यूपी सरकार के बेहतर कामकाज के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत तारीफ भी की। कहा कि न केवल काशी बल्कि यूपी के एक-एक जिले में जाकर जितनी मेहनत इन्होंने की, वह प्रशंसनीय है। संबोधन की शुरुआत में योगी को कर्मठ मुख्यमंत्री बताया तो सभागार में तालियां भी गूंजीं। एक समय ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री योगी सरकार की तारीफ कर रहे थे तो खुद योगी के भी हाथ ताली बजाने को उठ गए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की अपनी दूसरी सभा में भी योगी को 'ऊर्जावान' व 'लोकप्रिय' मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया। कोरोना के समग्र प्रबंधन, सर्वाधिक टेस्ट व सर्वाधिक टीकाकरण के प्रयास को गिनाया। श्रेय योगी को दिया। माफिया राज और भ्रष्टाचार पर नकेल के योगी सरकार के प्रयासों की सराहना की। तुलना की कि पहले की सरकार में लोग यूपी में कारोबार से परहेज करते थे। उनका पूरा संबोधन एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड ही था। यह 2022 के प्रदेश चुनाव का घोषित 'आमुख' तो नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री के तेवर और बोल पार्टी की मजबूत तैयारी का भाव व्यक्त कर रहे थे। बोले, 'आधुनिक यूपी बनाने में मुख्यमंत्री तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह इनकी कार्यनिष्ठा का कमाल है। काशी के लोग देखते हैं कि कैसे एक-एक योजना की योगी खुद निगरानी करते हैं।' दरअसल, श्रीकाशी विश्वनाथ कारिडोर जैसी योजना का लगातार निरीक्षण-कार्य संपादन, बजट प्रबंधन, कोरोना काल में भी एक्सप्रेस-वे का जारी निर्माण और पूर्वांचल में कई नए मेडिकल कालेज का पूर्ण होना जैसा गिनाने को बहुत कुछ था। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी कि वे दुविधा में हैं कि किस योजना का नाम लें और किसे छोड़ें? जोड़ा कि यूपी आज सबकी पसंदीदा जगह बन गया है।

काशी का संदेश पूरे यूपी को जाता ही है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति का यह केंद्र भी है। मोदी जब कहते हैं कि यहां केवल ज्ञान की गंगा नहीं, विकास की भी गंगा बही तो यह संदेश किसी को साध कर ही कहा गया है।

डाक्टरों से बोले पीएम, भगवान करे कोरोना वार्ड खाली ही रहें

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी

▸ प्रधानमंत्री ने बीएचयू में बने एमसीएच विंग का किया निरीक्षण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को परखने के लिए बीएचयू के नवनिर्मित एमसीएच (मातृ-शिशु स्वास्थ्य) विंग पहुंचे। डाक्टरों के साथ संवाद में भावनाएं व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा- 'भगवान करे, कोरोना वार्ड हमेशा खाली रहें और तीसरी लहर आए ही नहीं। बावजूद इसके पूरी तैयारी रखनी है। उन्होंने मातृ-शिशु उपचार व तीसरी लहर की तैयारियों को परखा और सराहा।

प्रधानमंत्री ने डाक्टरों से कहा कि अपने अनुभवों व नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों का डाक्यूमेंटेशन (प्रलेखीकरण) कर खूब साझा करें, ताकि आगे की पीढ़ी सीख सके। उम्मीद जताई कि एक-दो माह में बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। पीएम ने कहा कि कोविड ऐसा है विषय है, जिसमें पीएम से ज्यादा डाक्टरों व विज्ञानियों का मार्गदर्शन काम आता है। काशीवासियों एवं डाक्टरों को लेकर अपनी बात दो शब्दों में कहूं तो कहूंगा-थैंक्यू। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने तीसरी लहर की तैयारियों पर प्रजेंटेशन दिया।

पीएम का जोर रहा कि जहां मरीज हो, वहीं उपचार की व्यवस्था मिले। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं, ताकि लेवल थ्री अस्पतालों पर ज्यादा भार न बढ़े। आइएमएस के निदेशक प्रो. बीआर मित्तल ने बताया कि तीसरी लहर के लिए सुपर स्पेशियलिटी कांप्लेक्स व एमसीएच विंग में पूरी तैयारी है।

पीएम ने पूछा कि काशी में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? लोगों में कितनी जागरूकता बढ़ी है? सीएमओ डा. वीबी सिंह ने बताया कि पहले लोगों में झिझक थी। दूसरी लहर के बाद लोग खुद आगे आने लगे। अब तो सेंटरों पर इतनी भीड़ आ रही है कि हमें जूझना पड़ रहा है। सर सुंदरलाल अस्पताल, बीएचयू के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. केके गुप्ता व ट्रामा सेंटर के इंजार्च प्रो. सौरभ सिंह ने भी अपने अनुभव बताए।

पीएम ने 1918 में आई महामारी और 2001 में कच्छ में आए भूकंप का जिक्र किया। कहा-1918 में मानवता को महामारी का सामना करना पड़ा। लोग भूख से भी मरे। यह अच्छी तरह प्रलेखित था। यही वजह है कि सरकार ने पहली लहर में शुरू से ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और राशन मुहैया कराना सुनिश्चित किया। आने वाले समय में भी महामारी की चुनौती बनी रहेगी। हमें स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान देना होगा।

काशी ठहरती नहीं, रुद्राक्ष के विना अधूरा था शृंगार : पीएम

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे



रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जागरण आर्काईव

मोदी ने कहा-'मेरे बनारस के रोम-रोम में संस्कृति की धारा बहती है। सात सालों में कई विकास योजनाओं से काशी का शृंगार हो रहा था, लेकिन यह रुद्राक्ष के बिना अधूरा था।' उन्होंने संस्कृत के दो श्लोकों का उद्धरण भी दिया। बोले, पुराणों में कहा गया है- ''तत्र अश्रु बिंदुतो जाता, महारुद्राक्ष वृक्षाकाः। मम आज्ञया महासेन, सर्वेषाम् हित काम्यया।।''

अर्थात, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है।

उन्होंने संस्कृत के श्लोक पढ़कर व्याख्या भी की। भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है- 'सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम् च मे वपुः।'

अर्थात, काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। काशी तो साक्षात् शिव ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी जब किसी को अंगीकार करती है तब पूरे रस से सराबोर कर देती है और यह नगरी कभी ठहरती नहीं है।

केंद्र से ओबीसी का वास्तविक आंकड़ा दिलाएं फड़नवीस

राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाविकास अघाड़ी सरकार के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस से केंद्र सरकार से ओबीसी का वास्तविक आंकड़ा लाने का अनुरोध किया है। दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का राजनीतिक आरक्षण बहाल किए जाने के मुद्दे पर चर्चा की। दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल्स में छगन भुजबल व फड़नवीस पड़ोसी हैं। गुरुवार सुबह नागरिक आपूर्ति मंत्री भुजबल अपने रामटेक बंगले समीप स्थित फड़नवीस के सागर बंगले पर पहुंचे और उनसे ओबीसी का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। भुजबल के अनुसार, उन्होंने फड़नवीस से कहा कि वह केंद्र से महाराष्ट्र के ओबीसी का वास्तविक आंकड़ा ले आएं ताकि राज्य सरकार उसके आधार पर ओबीसी समुदाय का राजनीतिक आरक्षण बहाल कर सके। फड़नवीस ने कहा कि ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बहाल कराने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने भुजबल से इस मामले में ओबीसी समुदाय की अगुआई करने को कहा है। मुझसे जो भी मदद हो सकेगी मैं करूंगा।

उधर, देवेंद्र फड़नवीस ने विस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा बदलाव किए जाने की संभावना पर तीखी टिप्पणी की है। कहा कि जब सरकार के पास बहुमत है, तो उसे प्रत्यक्ष मतदान के जरिये विस अध्यक्ष का चुनाव कराने में क्या परेशानी है? फरवरी में नाना पटोले के त्यागपत्र सौंपने के बाद से विस अध्यक्ष का पद खाली है। चर्चा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार प्रत्यक्ष मतदान के जरिये अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया में बदलाव करने जा रही है।

न्यूज गैलरी

सरकार बनी तो होंगे दो उपमुख्यमंत्री : सुखबीर

चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एलान किया है कि पंजाब में शिअद-बसपा गठबंधन की सरकार बनने पर एक नहीं बल्कि दो उपमुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि एक उपमुख्यमंत्री हिंदू सवर्ण वर्ग से और दूसरा दलित वर्ग से होगा। इससे पहले उन्होंने केवल एक दलित उप मुख्यमंत्री बनाने का एलान किया था। सुखबीर ने कहा कि शिअद-बसपा गठबंधन की सरकार ही सही मायने में पंजाबी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करेगी।। (राब्यू)

गोधरा नगरपालिका पर फिर काबिज हुई भाजपा

अहमदाबाद : गुजरात के गोधरा की स्थानीय राजनीति में गुरुवार को हुए उठापटक ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। नगरपालिका में कल तक विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा ने निर्दलीय पार्षदों की मदद से एआइएमआइएम को बेदखल कर एक बार फिर सत्ता पर कब्जा जमा लिया। एआइएमआइएम के समर्थन से नगरपालिका की बागडोर संभाल रहे संजय सोनी खुद छह पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। पंचमहाल जिले की चर्चित गोधरा नगरपालिका में मार्च 2021 में आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) सात निर्दलीय पार्षदों की मदद से सत्ता पर काबिज हो गई थी। (राब्यू)

लोजपा में पारस गुट ने सात राज्यों में बनाए अध्यक्ष

पटना : लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) में पारस गुट ने सात प्रदेशों में पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। सांसद प्रिंस राज को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इन्हें नियुक्त किया है। विकास रंजन को झारखंड, ललित नारायण चौधरी को उप्र, रवि गरुड़ को महाराष्ट्र, वीरेंद्र कुमार बैंग को ओडिशा, रूपमकर को त्रिपुरा व अमित नरेश राठी को दादरा नगर हवेली व दमनदीव का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रीप्रकाश सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। (राब्यू)

सुवेंदु के करीबी को राहत, अभी गिरफ्तारी नहीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कांथी नगरपालिका भवन से तिरपाल चोरी मामले में नया मोड़ आ गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विस में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के करीबी चंचल नंदी को राहत दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि नंदी की अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अदालत ने राज्य सरकार को नंदी के खिलाफ आरोप की जानकारी देने को कहा है।

नंदी कांथी नगरपालिका के भवन के गोदाम से लाखों रुपये के तिरपाल की चोरी के मामले में आरोपित हैं। मामले में एक अन्य आरोपित सुवेंदु के छोटे भाई और कांथी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सौमेंदु अधिकारी हैं। तिरपाल चोरी के मामले में फंसने के बाद नंदी ने अदालत में आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें सुवेंदु का करीबी होने के कारण फंसाया जा रहा है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी देने की भी अपील की थी। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने गुरुवार को निर्देश दिया कि चंचल को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

'बतौर पीएम और सांसद वाराणसी को मोदी ने केवल भाषण दिया'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ रणदीप सुरजेवाला ने कई ट्वीट के जरिए सवाल उठाए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब वाराणसी में कई विकास कार्यों को हरी झंडी दिखा रहे थे, ठीक उसी समय कांग्रेस ने 11 सवालों की झड़ी लगाते हुए प्रधानमंत्री के साथ-साथ वाराणसी के सांसद के रूप में भी नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गंगा में 2013-14 के मुकाबले अब और ज्यादा नाले गिरते हैं। बाबा विश्वनाथ कारीडोर के नाम पर दर्जनों पौराणिक मंदिर तुड़वा दिए और अब रुद्राक्ष केंद्र को प्राइवेट कंपनी के हाथों में देकर उन आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी जो पहले कम खर्च में शादी ब्याह का आयोजन किया करते थे।

एक के बाद कई ट्वीट के जरिए रणदीप ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी के वाराणसी आने से पहले गंगा में 32 गंदे नाले गिरा करते थे, अब 34 गिर रहे हैं। एसटीपी कभी चलता है कभी नहीं। कभी काशी को क्योटो बनाने की बात की गई थी, लेकिन एक बारिश में जल भराव हो जाता है। पांच लाख परिवारों को रोजगार देने वाला बनारसी साड़ी उद्योग बंद होने की कगार पर है। कोरोना काल में राजन मिश्रा ने आक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया तो छन्नूलाल मिश्रा को अंतिम संस्कार के लिए बिटिया का शव नहीं मिला।

रणदीप ने प्रधानमंत्री से आगे पूछा कि जो दो गांव जयापुर और नगेपुर को उन्होंने गोद लिया था, वे बदहाल क्यों हैं। रणदीप ने कहा कि वाराणसी की पहचान है गंगा का अर्धचंद्राकार स्वरूप। लेकिन व्यावसायिक कारणों से उसे खराब कर दिया गया। रणदीप ने सवाल उठाया कि काशी और पूर्वांचल का विकास और रोजगार का इंतजार कब खत्म होगा। काशी को भाषण नहीं सुशासन चाहिए। लेकिन मोदी सात साल में बतौर प्रधानमंत्री और सांसद ये दोनों चीजें उपलब्ध नहीं करा पाए।

उप्र में गठबंधन की संभावना तलाश रही कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सियासी सरगर्मी

▸ सोनिया गांधी और प्रियंका से कमल नाथ की मुलाकात में हुई इस पर चर्चा

▸ सपा समेत अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन के विकल्पों पर विचार



कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में दशकों से कमजोर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की चुनौती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन की संभावनाएं तलाशने को लेकर कांग्रेस में सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। समझा जाता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई मुलाकात में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समेत अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन के विकल्पों पर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में दशकों से कमजोर संगठनात्मक ढांचे की चुनौती से रूबरू हो रही कांग्रेस के लिए सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखना आसान नहीं हो रहा। ऐसे में सूबे के चुनाव के साथ अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी राजनीति को ट्रैक पर कायम रखने के लिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना तलाशने की कोशिश करेगी।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस संगठन में बदलावों की हो रही चर्चा के बीच कमल नाथ की हाईकमान से उत्तर प्रदेश में गठबंधन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। बताया जाता है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन के हिमायती हैं। प्रशांत किशोर ने बीते दिनों पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई अपनी लंबी चर्चा के दौरान सूबे में गठबंधन की पहल करने की सलाह दी थी।

सोनिया गांधी और कमल नाथ की मुलाकात के दौरान प्रियंका की मौजूदगी भी इस बात का संकेत है कि सपा के साथ गठबंधन की संभावना तलाशने पर पार्टी में गंभीरता से विचार शुरू हो गया है। हालांकि, सूबे में सपा और कांग्रेस के बीच हुए चुनावी गठबंधन की विफलता दोनों पार्टियों की राह में बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की चुनौती इसलिए भी ज्यादा बड़ी है कि प्रियंका खुद सूबे में पार्टी की चुनावी रणनीति की कमान संभाल रही हैं। वैसे सियासी चर्चा यह भी है कि प्रशांत किशोर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी यह संदेश दिया है कि 2024 में भाजपा को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव विपक्षी दलों के लिए बेहद निर्णायक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी राजनीतिक वास्तविकता की अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

कमल नाथ की पार्टी नेतृत्व से हुई चर्चा के संकेतों से साफ है कि वे सपा, रालोद व अन्य दलों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन के प्रयासों पर पहल कर सकते हैं।

तृणमूल ने आयोग से की बंगाल में जल्द उपचुनाव कराने की मांग

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक छह सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और राज्य में रिक्त सात विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव कराने की मांग की। बता दें, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को छह माह के भीतर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना अनिवार्य है। इस अवधि में दो माह से अधिक का समय बीत चुका है और अब ममता के पास चार माह का समय ही शेष है।

तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन की अगुआई में प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में डेरेक के अलावा सांसद सौगत राय, काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, कल्याण बनर्जी व सुखेंदु शेखर राय शामिल थे। आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, हमने आयोग से अपील की है कि बंगाल में लंबित सभी उपचुनाव विधानसभा चुनाव के छह महीने के अंदर आयोजित कराए जाएं। हमें उम्मीद है कि हमारी चर्चा सफल रहेगी।

उधर, सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर है और उनके पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के कई वार्ड कोरोना शून्य हो चुके हैं, बावजूद इसके उपचुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि सभी सीटों पर भाजपा की हार तय है। आयोग को सातों सीटों पर उपचुनाव तुरंत करवाना चाहिए क्योंकि संविधान के प्रविधानों के अनुसार, चुनाव होने के छह महीने के अंदर उपचुनाव करवा लेना चाहिए।

हरीश रावत बोले- सिद्धू होंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष

जागरण टीम, नई दिल्ली

▸ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को इस बारे में किया फोन

▸ कमल नाथ, अश्वनी कुमार व प्रताप बाजवा ने भी जताया एतराज

▸ वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया पर सोनिया ने रावत को तलब किया

पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की अंदरूनी जंग खत्म करने के लिए तय सियासी फार्मूले से पर्दा हटते ही कांग्रेस में हलचल मच गई। गुरुवार को कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही तो कैप्टन सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह संदेश दिया कि यह सही फैसला नहीं है। इसके बाद दोनों खेमों में जोर आजमाइश व दबाव की सियासत तेज हो गई है। शाम को दोनों खेमों की बैठकें हुईं।

हरीश रावत ने गुरुवार सुबह नई दिल्ली में बातचीत के दौरान सूबे की सियासत में कैप्टन-सिद्धू का संघर्ष लगभग खत्म हो जाने का एलान किया। कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाईकमान के बीच हुई चर्चा के बाद समाधान का रास्ता निकल गया है। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव से जुड़े सवाल पर रावत ने कहा कि सुलह का फार्मूला इस विकल्प के आस-पास ही रखा गया है। रावत ने इशारों में साफ कर दिया कि सिद्धू प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभालेंगे। उन्होंने यह भी साफ कहा कि कैप्टन पिछले साढ़े चार साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं और बेशक कांग्रेस उनकी अगुआई में ही 2022 के चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कैप्टन और सिद्धू मिलकर चुनाव में पार्टी की जीत की आधारशिला रखेंगे।

जैसे ही रावत का यह एलान मीडिया में आया, कांग्रेस में तीखी प्रतिक्रिया हुई। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी गांधी को फोन कर आपत्ति जताई। राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा के अलावा वरिष्ठ नेता कमल नाथ और पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्वनी कुमार ने भी एतराज जताया। वरिष्ठ नेताओं की इस प्रतिक्रिया के बाद सोनिया गांधी ने प्रदेश प्रभारी हरीश रावत को 10 जनपथ बुलाया। इसके बाद रावत ने स्पष्ट किया कि उन्होंने नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बनाने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि फैसला इसी के इर्द-गिर्द हो सकता है। सिद्धू का नाम उन्होंने नहीं लिया। यह माना जा रहा था कि गुरुवार को पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से यह एलान कर दिया जाएगा कि सिद्धू ही अध्यक्ष होंगे लेकिन रावत के बयान पर हलचल मची को देखते हुए हाईकमान ने एलान नहीं किया।

उलझन में हाइकमान, रावत कर सकते हैं कैप्टन से मुलाकात : एक बार फिर हाईकमान अध्यक्ष को लेकर उलझन में पड़ गया है। सूत्रों का कहना है कि अगर सिद्धू को ही अध्यक्ष बनाया जाना है तो कैप्टन को विश्वास में लेने के लिए हरीश रावत एक-दो दिन में उनसे मुलाकात कर सकते हैं।

कैप्टन और सिद्धू ने की अलग-अलग बैठकें : पार्टी की ओर से अध्यक्ष बनाए जाने का एलान न होने पर सिद्धू ने एक बार फिर दबाव की राजनीति करते हुए शाम को चार मंत्रियों व छह विधायकों से मुलाकात की। सिद्धू ने मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के आवास पर कैप्टन विरोधी खेमे के अन्य मंत्रियों तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखबिंदर सिंह सरकारिया व चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा विधायक परगट सिंह, कुलबीर जीरा, बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा व कुशलदीप ढिल्लों के साथ बैठक की। वहीं, कैप्टन खेमा भी सक्रिय हो गया है। देर शाम कैप्टन ने भी अपने फार्म हाउस में सांसद जसबीर सिंह डिंपा, गुरजीत औजला और विधायकों में रमिंदर आंवला, फतेहजंग बाजवा आदि के साथ बैठक की। सुबह कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा और अरुणा चौधरी भी कैप्टन से मिले थे।

बदलती सियासत

ओवैसी की बढ़ती ललकार, मुस्लिम मतों के नए हिस्सेदार !

बिहार की तरह मुस्लिम बहुल सीटों पर बिगाड़ सकते हैं विपक्ष के समीकरण, विस चुनाव में सौ सीटों पर ताल से बढ़ेगी सपा, बसपा व कांग्रेस की चुनौती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

शतरंज की बिसात पर ही ऊंट तिरछा नहीं चलता, चाहे-अनचाहे राजनीति के मैदान में भी ऐसी स्थिति बन जाती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मोर्चा सजाने के लिए उतरे आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) के अध्यक्ष असदउद्दीन ओवैसी खड़े तो भाजपा के सामने नजर आते हैं, लेकिन तिरछी मार विपक्षी खेमे पर पड़ सकती है। पश्चिम के साथ ही सपा के प्रभाव वाले पूर्वांचल में ओवैसी की आहट से सूबे के सियासी समीकरण अंगड़ाई लेते नजर आ रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून और जबरन मतांतरण के खिलाफ बने कानून के बाद 2022 में हो रहे विधानसभा चुनाव में ओवैसी 19 फीसद मुस्लिम मतों के मजबूत हिस्सेदार बन सकते हैं।

भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल अपनी-अपनी रणनीति बना रहे हैं। सपा यादव-मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत रखते हुए नया वोट समेटने के लिए प्रयासरत है। बसपा दलित के साथ मुस्लिम को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटी है तो कांग्रेस की नजर भी अल्पसंख्यक मतों में हिस्सेदारी पर है। चर्चा है कि 19 फीसद मुस्लिम मत यदि एकतरफा किसी एक दल के पाले में गया तो कई सीटों पर सत्ताधारी भाजपा के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है। इसी बीच ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए ताल ठोंक कर मुस्लिम मतों के बिखराव की संभावना प्रबल कर दी है। एआइएमआइएम ने किस्मत तो 2017 के विधानसभा चुनाव में आजमाई थी, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं। 2017 में 38 सीटों पर लड़ी एआइएमआइएम के प्रत्याशियों की 37 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 13 सीटों पर वह चौथे स्थान पर थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबले खड़े हुए विपक्षी महागठबंधन का खेल कई सीटों पर बिगाड़ते हुए पांच सीटें जीतने में ओवैसी कामयाब रहे।

अब यूपी में वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर द्वारा बनाए गए जनभागीदारी मंच के साथ छोटे दलों को साथ जोड़ने चले हैं। इस गठबंधन का भविष्य अभी संशय में है, लेकिन ओवैसी ने इस बार सौ सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। पिछली बार सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस करने वाली एआइएमआइएम ने अबकी बार पूर्वांचल की ओर भी कदम बढ़ा दिए हैं। सभी जगह अपने कार्यालय खोल रहे हैं। दरअसल, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया, संतकबीरनगर, चंदौली, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़ आदि ऐसी सीटें हैं, जहां पिछली बार भाजपा के मुकाबले सपा मजबूत स्थिति में नजर आई। अब ओवैसी जितनी भी बढ़त लेंगे, उसका सीधा असर मुख्य विपक्षी सपा पर पड़ सकता है।

जनसंख्या खुद घट रही है तो फिर पालिसी क्यों : ओवैसी

कई जगहों से होते हुए संभल पहुंचे ओवैसी ने कहा कि जब जनसंख्या दर स्वयं ही लगातार घट रही है तो इस पर कानून बनाने की क्या जरूरत है। क्यों थोपने की पालिसी को अपनाया जा रहा है। यह सब युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले गाजियाबाद के मसूरी में उनको सुनने आई भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी और कई लोग चोटिल हुए। ओवैसी को कार्यक्रम स्थल से बिना भाषण दिए लौटना पड़ा। अमरोहा की तरफ जाते हुए ब्रजघाट में ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम वर्ग आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद के बहकावे में न आएं। ओवैसी ने भारतीय जनजागृति पार्टी के प्रमुख और भागवत प्रवक्ता संत युवराज से उनके कार्यालय में मुलाकात की।

मप्र विस में सदस्य नहीं बोल पाएंगे पप्पू, फेंकू और बंटाधार जैसे शब्द

नईदुनिया, भोपाल

▸ सदस्यों के लिए सचिवालय तैयार कर रहा है असंसदीय शब्दों की सूची

मध्य प्रदेश विधानसभा में अब सदस्य पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, झूठा व मूर्ख सहित अन्य शब्दों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई असंसदीय शब्दों की सूची विधानसभा सचिवालय तैयार कर रहा है। नौ अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सदस्यों को यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी। उनसे अपेक्षा रहेगी कि इनका इस्तेमाल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नहीं करें।

विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि लोकसभा सचिवालय सहित अन्य विधानसभाओं से ऐसे शब्दों की सूची मंगाई है, जिनका उपयोग नहीं करने की अपेक्षा सदस्यों से की गई है। इसके साथ-साथ सदन की कार्यवाही के दौरान जिन शब्दों को समय-समय पर विलोपित किया गया है, उन्हें शामिल करते हुए मार्गदर्शिका तैयार की जा रही है। कोशिश यही है कि विधानसभा सत्र के पहले यह सदस्यों को वितरित कर दी जाए। बताया जा रहा है कि इसमें नालायक, बेवकूफ सहित अन्य शब्दों को भी शामिल किया है।

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि सदन की मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की होती है। हमारा आचरण सदन में ऐसा होना चाहिए, जो दूसरों के लिए उदाहरण हो। कई बार आवेग में सदन में ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है, जिन्हें कार्यवाही से विलोपित करना पड़ता है। ऐसे शब्दों का उपयोग सदस्य न करें, इसके लिए मार्गदर्शिका तैयार कराई जा रही है।

2020 जुलाई-दिसंबर की अवधि में भारत सरकार की ओर से ट्विटर अकाउंट की सर्वाधिक सूचना मांगी गई। दुनियाभर में किए गए इस तरह के अनुरोधों में भारत की हिस्सेदारी 25 फीसद है।

पीएम मोदी आज देश को देंगे सबसे बड़े एक्वेरियम की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के साथ-साथ पूरे देश को कई सौगात देंगे। शाम चार बजे वर्चुअल माध्यम से वह देश के पहले अत्याधुनिक सुविधाओं वाले गांधीनगर कैपिटल स्टेशन व उसके ऊपर बने फाइव स्टार होटल, अहमदाबाद स्थित साइंस सिटी में निर्मित अनूठी एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी व नेचर पार्क तथा वडनगर रेलवे स्टेशन समेत कुल 1,100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आइए जानते हैं अनूठी एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी व नेचर पार्क के बारे में...



साइंस सिटी, अहमदाबाद में बना नेचर पार्क। एएनआइ

साइंस सिटी में घूमने के लिए वेबसाइट व एप के जरिये एडवांस बुकिंग की जा सकेगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका सपना देखा और इससे विज्ञान, तकनीक, जैव सृष्टि व पर्यावरण के बेजोड़ नमूनों को जोड़ते गए। पर्यटकों के लिए यहां का दौरा यादगार होगा।
-विजय नेहरा, सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, गुजरात)

नेचर पार्क

- 14 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है इस पार्क का निर्माण
- 20 एकड़ में फैले पार्क में दुर्लभ पशुओं की जीवंत प्रतिमाएं रोमांचित कर देंगी
- 10 जोनों (एशिया, अमेरिका व अफ्रीका आदि) के जंगली जीव-जंतुओं की जीवंत प्रतिक्रतियां होंगी उपलब्ध
- मैमथ, टेरर बर्ड, सेबर टूथ लायन, स्लाथ बेर, करोड़ों की संख्या में खटमल के झुंड व मधुमक्खियों के छत्ते की प्रतिकृतियां कर देंगी अचंभित
- फाग गार्डेन, चेस गार्डेन, सेल्फी प्वाइंट, स्कल्पचर पार्क देंगे अनूठा अनुभव
- बच्चों के मनोरंजन के लिए भूलभुलैया भी किया गया है तैयार

एक्वाटिक गैलरी

264 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है एक्वाटिक पार्क का निर्माण

68 बड़े टैंकों वाले देश के सबसे बड़े एक्वेरियम में समुद्री जीवन से हो सकेंगे रू-ब-रू

188 प्रजाति की मछलियां व समुद्री जीव देखने को मिलेंगे इस एक्वेरियम में

11,600 कुल समुद्री जीवों की अटखेलियां करेंगी रोमांचित

28 मीटर लंबी पानी के भीतर स्थित सुरंग के जरिये लोगों को समुद्री जीवों को करीब से देखने का मौका मिलेगा

5 डी थियेटर के जरिये समुद्र के गर्भ में होने वाली गतिविधियों से होगा परिचय

रोबोटिक गैलरी

127 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है गैलरी का निर्माण

11,000 वर्ग मीटर में फैली है यह रोबोटिक गैलरी

79 प्रकार के रोबोट और उनके काम को देखने का अवसर मिलेगा

200 रोबोट पर्यटकों का विविध तरीकों से मनोरंजन व गाइड करेंगे

- कहीं खेलते तो कहीं खाना पकाते, कहीं स्पेस तो कहीं डिफेंस का काम करते नजर आएंगे ये रोबोट
- ह्यूमनोइड रोबोट आपको बिल्कुल आदमी की तरह लगेंगे और वे मनुष्यों से बातचीत भी कर सकेंगे

(इनपुट : अहमदाबाद से शत्रुघ्न शर्मा व प्रेट्र)

गुलाम कश्मीर को भी परिसीमन के दायरे में लाने की उठने लगी आवाज

नवीन नवाज, श्रीनगर

- सांकेतिक ही सही, परिसीमन की प्रक्रिया को एलओसी के पार लेकर जाना होगा
- गुलाम कश्मीर को वापस हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना जरूरी

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के गठन से पहले जारी परिसीमन की प्रक्रिया के बीच गुलाम कश्मीर को भी परिसीमन के दायरे में लाने की आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान पर गुलाम कश्मीर को लौटाने के लिए दबाव बनाने और दुनिया को यह बताने के लिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर रखा है, बेशक सांकेतिक ही सही, परिसीमन की प्रक्रिया को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार गुलाम कश्मीर में लेकर जाना होगा। गुलाम कश्मीर से खदेड़े गए हजारों की तादाद में गैर मुस्लिमों को उनके मूल क्षेत्र के आधार पर जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में प्रतिनिधित्व देना होगा। यह मांग जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में आकर बसे गुलाम कश्मीर के विस्थापितों ने उठाना शुरू कर दी है।

गुलाम कश्मीर की खाली 24 सीटों पर हो चुनाव : डिफेंस इस्टेट विभाग से सेवानिवृत्त विनोद कुमार दत्ता ने कहा, मैं गुलाम कश्मीर के कोटली मीरपुर से यहां आया हूं। हम जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं, बावजूद इसके हमें विस में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अब गुलाम कश्मीर को भी परिसीमन के दायरे में लाना चाहिए।

प्रत्येक सीट पर गुलाम कश्मीर के विस्थापित ही करें मतदान : गुलाम कश्मीर के विस्थापितों के लिए संघर्षरत एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुन्नी ने कहा कि जब संसद में गुलाम कश्मीर को वापस लेने का प्रस्ताव पारित है तो फिर उसे परिसीमन की प्रक्रिया से क्यों बाहर रखा जाएगा। वहां परिसीमन आयोग के जाने की जरूरत नहीं है, आप सांकेतिक तौर पर यह काम कर सकते हैं। इसके अलावा वहां से आए विस्थापित गुलाम कश्मीर के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और कसबे से जुड़े हैं। इसलिए इनकी आबादी को ध्यान में रखते हुए यह काम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गुलाम कश्मीर की प्रत्येक सीट पर गुलाम कश्मीर के विस्थापित ही मतदान करें। इससे जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में मीरपुर, कोटली, बाग, मुजफ्फराबाद, नीलम, शारदा, दोमेल की चर्चा हुआ करेगी।

विदेश में बसे विस्थापितों को भी दें वोट का अधिकार : जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष अजात जम्वाल ने कहा कि गुलाम कश्मीर में एक बड़ा तबका पाकिस्तान से आजादी चाहता है और जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बनना चाहता है। इस तबके से जुड़े कई लोग पाकिस्तानी उत्पीड़न से तंग आकर यूरोप, अमेरिका में बसे हैं। हम उन्हें भी गुलाम कश्मीर की आरक्षित सीटों पर पोस्टल बैलेट का अधिकार दे सकते हैं। इससे पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दे पर कमजोर होगा।

हमने आयोग के समक्ष उठाया है मुद्दा : भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बीते दिनों जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए परिसीमन आयोग से मुलाकात के दौरान हमने गुलाम कश्मीर का मुद्दा उठाया था। हमने कहा कि गुलाम कश्मीर की 24 आरक्षित सीटों में से 35 फीसद को खोल देना चाहिए। इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ गुलाम कश्मीर के विस्थापित, जो देश विदेश में बसे हैं, मतदान का अधिकार होना चाहिए।

13 लाख है गुलाम कश्मीर के विस्थापितों की संख्या

गुलाम कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से पलायन कर आए हिंदू व सिख समुदाय की आबादी इस समय करीब 13 लाख है और इनमें से अधिकांश जम्मू संभाग में ही रहते हैं। इनके अलावा दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और विदेश में भी बड़ी संख्या में गुलाम कश्मीर के विस्थापित बसे हुए हैं।

पुनर्गठन अधिनियम में परिसीमन की पक्रिया से वाहर है गुलाम कश्मीर

परिसीमन आयोग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि गुलाम कश्मीर के कोटे की 24 सीटें खाली रहेंगी, इन पर चुनाव नही होगा। इन आरक्षित सीटों को जम्मू-कश्मीर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बसे गुलाम कश्मीर के विस्थापितों के लिए नहीं खोला जा सकता।

ऐसा है गुलाम कश्मीर

गुलाम कश्मीर 13,297 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें गिलगित, बाल्टिस्तान और पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया जम्मू-कश्मीर का हिस्सा शामिल नहीं है। गुलाम कश्मीर में 10 जिले हैं और इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है।

माल ढुलाई के लिए अलग से बनेगा ड्रोन कारिडोर

सरकार का बड़ा कदम ▶ व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सरकार ने जारी किया ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा

नियमों को सरल करने का प्रयास, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल की भी होगी स्थापना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर सरकार ड्रोन से जुड़े कई नए नियम लाने जा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को नागरिक विमानन मंत्रालय की तरफ से जनता से परामर्श के लिए ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा जारी किया गया। पांच अगस्त तक इस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। मसौदे के मुताबिक, ड्रोन से माल ढुलाई के लिए अलग से ड्रोन कारिडोर बनाया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल बनाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित मसौदे में सरकार ने ड्रोन संबंधी नियमों को सरल करने का प्रयास किया है ताकि ड्रोन का संचालन आसान हो सके और उसका अधिक से अधिक कारोबारी इस्तेमाल हो सके। मसौदे के मुताबिक, ग्रीन जोन में 400 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए किसी प्रकार की इजाजत की आवश्यकता नहीं होगी। माइक्रो ड्रोन के गैर-व्यापारिक इस्तेमाल के लिए किसी पायलट लाइसेंस की दरकार नहीं होगी। भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। डिजिटल स्काई प्लेटफार्म को व्यापार अनुकूल बनाने के लिए एकल खिड़की आनलाइन प्रणाली के तौर पर विकसित किया जाएगा। ड्रोन और ड्रोन के कलपुर्जों का कारोबार विदेश व्यापार महानिदेशालय की देखरेख में किया जाएगा। ड्रोन संबंधी पंजीकरण या लाइसेंस लेने से पहले सिक्यूरिटी क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं होगी। अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्वानुमति और रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।



ड्रोन से सुरक्षा। फाइल फोटो

जम्मू-कश्मीर में ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी पूरी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया

ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर तैयार हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पक्की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में जम्मू स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है। यह सिस्टम ड्रोन की रेडियो फ्रिक्वेंसी को जाम कर देता है। इस बीच, एयरफोर्स स्टेशन के पास बुधवार रात को एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। अलबत्ता, इसकी आधिकारिक तौर पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा जम्मू जिले के अखनूर में सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, जिसे सेना के जवानों ने फायरिंग कर भगा दिया।

जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को तड़के दो ड्रोन हमले हुए थे। ढाई किलो आरडीएक्स के दो बमों से एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया गया था। इसमें दो सुरक्षाकर्मी जख्मी भी हुए थे। इस घटना के बाद जम्मू शहर में सैन्य शिविरों समेत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन मंडराने के कई मामले सामने आए। सेना, वायुसेना व सुरक्षाबल इस समय ड्रोन की चुनौती का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं।

ड्रोन हमले की साजिश बढ़ी, सुरक्षाबल सचेत: वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में ड्रोन गतिविधियां अधिक बढ़ गई हैं। हालांकि, खुफिया एजेंसियों ने पहले ही सुरक्षाबलों को सचेत कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर ड्रोन हमले की साजिश रची है।

गुलाम कश्मीर में ड्रोन हमलों का प्रशिक्षण : गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी सेना व उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ की मदद से 28 से अधिक आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। इनमें आतंकियों को ड्रोन उड़ानें व उनके जरिये हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आशंका है कि आतंकियों ने स्वतंत्रता दिवस पर ड्रोन की मदद से ही हमले की साजिश रची है।

रावत वोले, दुश्मन की हर साजिश को करें नाकाम

जागरण संवाददाता, राजौरी : चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को राजौरी-पुंछ में नियंत्रण रेखा का दौरा कर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने जवानों और अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। सुबह जम्मू से राजौरी तकनीकी हवाई पट्टी पर पहुंचे रावत 25 डिवीजन के मुख्यालय में पहुंचे। उन्होंने सेना के उच्च अधिकारियों के साथ सरहद पर मौजूदा हालात पर चर्चा की और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। रावत ने कहा,पूरी तरह से चौकस रहें और सीमा पार की चाल को नाकाम करें।

जम्मू की कोट भलवाल जेल से हथियार, फोन और सिम बरामद

जागरण संवाददाता, जम्मू

देश की अति संवेदनशील व कड़ी सुरक्षा वाली कोट भलवाल जेल में चल रहे 'खेल' का पुलिस ने पर्दाफाश किया। जेल में गुरुवार तड़के जम्मू-कश्मीर पुलिस की खुफिया विंग सीआइडी काउंटर इंटेलीजेंस ने सीआरपीएफ और घरोटा पुलिस की मदद से छापा मारा। तलाशी अभियान में जेल की बैरकों से चाकू, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और मोबाइल फोन की बैटरी बरामद हुई है। इससे जेल प्रशासन की व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मोबाइल फोन को जांच के लिए साइबर सेल को सौंपा जाएगा। ताकि फोन और पेन ड्राइव को डि-कोड कर उसमें रखे गए डाटा की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। सूत्रों की मानें तो जेल में बंद आतंकियों ने छापेमारी के दौरान कुछ सिमकार्ड तोड़ कर फेंक दिए, जिनकी तलाश में सुरक्षाकर्मी जुटे हैं। बता दें कि कोट भलवाल जेल में मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भी रखा जा चुका है। फिलहाल यहां कुख्यात विदेशी आतंकियों समेत कश्मीर के अलगाववादी भी बंद है।

डायरी और मोबाइल फोन नंबर भी मिले : जेल में छापे के दौरान सुरक्षाकर्मियों को एक बैरक में से एक डायरी मिली, जिसमें उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इसके अलावा आठ छोटे पेज मिले जिन पर मोबाइल फोन नंबर लिखे हुए है।

तड़के पांच बजे शुरू हुई बड़ी कार्रवाई : कोट भलवाल जेल को गुरुवार तड़के जम्मू पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग के जवानों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और घरोटा पुलिस ने घेर लिया। तलाशी अभियान में एक सौ से अधिक जवानों ने भाग लिया। चूंकि कोट भलवाल जेल का क्षेत्रफल काफी अधिक है। इसलिए इतने अधिक सुरक्षाबलों की अभियान में जरूरत पड़ी। शाम चार बजे तक तलाशी अभियान चलता रहा।

आतंकियों के सीमापार बात करने से नहीं किया जा रहा इन्कार : कोट भलवाल जेल में बंद आतंकियों द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग करना सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध मानी जा रही है। पुलिस सूत्रों की मानें तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा रहा कि आतंकी जेल में बैठ सीमापार अपने आकाओं से दिशा निर्देश लिया करते थे। ताकि जम्मू-कश्मीर में आतंक की आग को भड़का कर रखा जा सके।

पहले भी विवादों में रह चुकी है कोट भलवाल जेल : तीन मई को कोट भलवाल जेल में छापेमारी कर सीआइडी और सीआइ विंग ने वहां से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए थे।

2023 समाप्त होने के पहले भव्य मंदिर में होगा रामलला का दर्शन

जासं, अयोध्या

समयबद्ध कार्ययोजना
- रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दो दिवसीय बैठक में कई फैसले
- मंदिर सहित 70 एकड़ का संपूर्ण रामजन्मभूमि परिसर होगा इको फ्रेंडली

श्रद्धालु 2023 समाप्त होने के पूर्व ही भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस लक्ष्य को पाने के लिए निर्माण की समयबद्ध कार्ययोजना बनाई है। इस योजना का ब्लूप्रिंट रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की सर्किट हाउस में हुई बैठक में तैयार किया गया। तय योजना के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य 2023 तक और संपूर्ण परिसर का विकास 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

सर्किट हाउस में चली दो दिवसीय बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने मीडिया को बताया कि राम मंदिर सहित संपूर्ण 70 एकड़ परिसर इको फ्रेंडली होगा। परिसर का अपशिष्ट पानी शेष रामनगरी के लिए समस्या न बने, इसके लिए सीवर ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। परिसर में अधिकाधिक वृक्षों को भी संरक्षित किया जाएगा, ताकि आक्सीजन लेवल और तापमान ठीक-ठाक रहे। इस दौरान निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर और अन्य सामग्री का भी आकलन किया गया। परकोटा के निर्माण में जोधपुर के चार लाख घनफीट, प्लिंथ के निर्माण में ग्रेनाइट एवं मिर्जापुर के चार लाख घन फीट तथा मंदिर निर्माण में बंसी पहाड़पुर के तीन लाख 60 हजार घन फीट पत्थर प्रयुक्त होंगे। पानी के बहाव से बचाव के लिए उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में रिटेनिंग वाल बनाई जाएगी, जिसकी गहराई 12 मीटर होगी। बुजुर्ग एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दो लिफ्ट लगाई जाएंगी। निर्माण की प्रक्रिया में सीमेंट के कम से कम उपयोग पर भी बैठक में चर्चा की गई और सीमेंट की जगह फ्लाई एश के उपयोग की योजना तय की गई। ईंट के कम से कम प्रयोग की योजना पर भी विचार किया गया और ईंट की जगह पत्थर के उपयोग को सहमति दी गई।

मकराना के संगमरमर से बनेगा चौखट

मंदिर के दरवाजों की चौखट मकराना के सफेद संगमरमर से बनेगी। हालांकि खिड़कियों की चौखट के लिए बंसी पहाड़पुर के लाल बलुआ पत्थर को ही उपयोगी माना गया।

झारखंड में मतांतरण करा रहे केरल, हैदराबाद और बेंगलुरू के पादरी

संजय कुमार, रांची

- आदिवासी समाज के भोलेपन, गरीबी और बीमारी का उठा रहे हैं फायदा

झारखंड में मतांतरण का खेल वर्षों से चल रहा है। रघुवर सरकार ने कानून बनाकर इस पर थोड़ी सख्ती की, लेकिन कोरोना काल में इसमें फिर तेजी आ गई है। केरल, हैदराबाद, बेंगलुरू और चेन्नई सहित दक्षिण भारत के सैकड़ों पादरी फिलहाल यहां सक्रिय हैं। इन लोगों ने कोरोना काल में सेवा के नाम पर लोगों की मदद कर अवैध मतांतरण के काम में तेजी लाने का काम किया। खूंटी, सिमडेगा, गुमला आदि जिलों के कई गांव ऐसे हैं जहां के अधिकतर परिवार मतांतरित हो चुके हैं। कई गांवों में भोले-भाले आदिवासियों की जमीन स्कूल खोलने और गोदाम बनाने आदि के नाम पर लेकर चर्च खोल दिए हैं। कई जगहों पर तो इंदिरा आवास को भी चर्च बना दिया है।

आदिवासियों को भरमाने के लिए उनके देवता सिंगबोंगा का नाम भी चर्च के बाहर शिलापट्ट पर लिखकर लगा दिया गया है। सुदूर गांवों में भी केरल के विलिवर्स और पेंटेकास्टल चर्च, हैदराबाद के विश्ववानी चर्च बनाए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया मुंडा ने कहा कि झारखंड में 2017 में कानून बनने के बाद भी अवैध मतांतरण का खेल चल रहा है। इस काम में लगे पादरियों से जब बपतिस्मा का प्रमाणपत्र मांगा जाता है तो नहीं दिखाते हैं क्योंकि उस प्रमाणपत्र में लिखा रहता है कि आपको किस पादरी ने किस तिथि को किस चर्च में ईसाई बनाया है। उसे दिखाने के बाद पता चल जाएगा कि कब उसने अपना धर्म बदला है।

मतांतरण के बाद भी हिंदू नाम नाम रख रहे : राष्ट्रीय आदिवासी मंच के झारखंड प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष सन्नी टोप्पो ने कहा कि मिशनरी के लोग मतांतरण कराने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते रहते हैं। पादरी बनने के बाद नाम भी हिंदू रख रहे हैं। रांची के पिस्कानगड़ी के गोसाई टोली गांव के गंदरू टोप्पो ने पादरी बनने के बाद अपना नाम भी बदलकर पिंकू रख लिया है। सन्नी ने कहा कि मतांतरण को बढ़ावा देने में कई गांव के जनप्रतिनिधि भी लगे हैं। पिछले दिनों रांची जिला में लदा गांव के 15 से 20 लोहरा परिवार के लोग ईसाई बन चुके हैं। कर्रा प्रखंड के कनसिल्ली गांव में तो तीन परिवार ऐसे हैं जिनकी जमीन लेकर चर्च बना दिया गया है। परिवार झोपड़ी में रहता है। खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड अंतर्गत पंडरिया नवाटोली गांव के 50 परिवार मतांतरित हो चुके हैं।

पहले दिया शादी का भरोसा, फिर मतांतरण के लिए बनाया दवाव

नईदुनिया, रतलाम : मध्य प्रदेश के रतलाम में शादीशुदा युवक ने कालेज छात्रा को पहले शादी करने का भरोसा दिया और उसके बाद मतांतरण का दबाव बनाया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित उस्मान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस थाने में दर्ज मामले के अनुसार अनुसूचित जाति की 21 वर्षीय युवती को उस्मान ने 14 मार्च, 2020 को जन्मतिथि के बहाने एक जूस सेंटर पर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इस दौरान उसके फोटो भी खींच लिए थे। मना करने पर आरोपित फोटो वायरल करने की धमकी देता था। आठ जुलाई, 2021 को उस्मान ने युवती से शादी करने का कहकर टाइप किए कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। लिव इन रिलेशनशिप देख हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

नया इतिहास

हल्दीघाटी में लगाई गईं विवादास्पद पट्टिकाएं चालीस साल बाद हटाई जाएंगी, इंदिरा गांधी के दौरे के दौरान लगाई गई पट्टिकाओं में दी गई महाराणा प्रताप के पीछे हटने की बात

'हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप नहीं, अकबर हटा था पीछे'

सुभाष शर्मा, उदयपुर

हल्दीघाटी में लगी उन सभी विवादास्पद पट्टिकाओं (बोर्ड) को हटाया जाएगा, जिसमें महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दीघाटी के युद्ध में कदम पीछे खींचे जाने की गलत जानकारी दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की ओर से नई जानकारी के साथ पट्टिकाएं लगवाई जाएंगी। इसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि हल्दीघाटी का युद्ध निर्णायक रहा था। इसमें मुगल शासक अकबर की सेना को कदम पीछे हटाने पड़े थे। यानी हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप की जीत और अकबर की हार हुई थी।

एएसआइ जोधपुर सर्किल के अधीक्षक बिपिन चंद्र नेगी ने बताया कि रक्ततलाई और बादशाही बाग में हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित कई शिलापट्ट लगे हैं। इनको राजस्थान पर्यटन निगम की ओर से करीब चालीस साल पहले लगाया गया था। इन सभी पट्टिकाओं को हटाने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि, इस ओर कदम उठाने से पहले इससे जुड़े सही तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछली सदी के सातवें दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हल्दीघाटी का दौरा किया था तब राजस्थान पर्यटन निगम की पट्टिकाओं में लिखा गया था कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा था।

इतिहासकार ने पकड़ी गलती: हल्दीघाटी का युद्ध निर्णायक था। इसको लेकर उदयपुर के इतिहासकार प्रो. चंद्रशेखर शर्मा ने शोध के जरिये प्रमाणित किया है। उनके शोध के मुताबिक हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी रहे थे। अपने तर्क के रूप में वह कहते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून, 1576 को शुरू हुआ था, जबकि पर्यटन निगम की ओर से लगवाई गई पट्टिकाओं में 21 जून का जिक्र है। इससे ही साबित होता है कि उनकी ओर से दी गई जानकारी गलत है।

अब तक गलत पढ़ाया जा रहा, सुधार की जरूरत

इतिहास की पुस्तकों में हल्दीघाटी का जिक्र है, लेकिन इसे गलत ही पढ़ाया जाता रहा है। इस मामले में सुधार के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के नेता एकमत हैं। उदयपुर के प्रभारी एवं अशोक गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि इतिहास से छेड़छाड़ करने वाली पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचने नहीं देंगे। महाराणा प्रताप के वंशज एवं पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का कहना है कि अपमान बर्दाश्त से बाहर है। राजसमंद की सांसद दीयाकुमारी का कहना है कि इतिहासकारों ने स्कूली पाठ्यक्रम में छेड़छाड़ कर हल्दीघाटी ही नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप का भी अपमान किया है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इतिहास की सच्चाई सामने लाने तथा बच्चों को सही पढ़ाए जाने की बात कहते हैं। उक्त सभी नेताओं का एकस्वर में कहना है कि लोगों को दी जा रही गलत जानकारी में सुधार की जरूरत है।

दीया कुमारी और राजपूत संगठनों ने की थी पहल

राजसमंद की सांसद दीया कुमारी ने पट्टिकाओं की गलत जानकारी की ओर ध्यान खींचा था। इसको लेकर गत 19 जून, 2021 को वह पहले केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मिली थीं और बाद में उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलकर यह मुद्दा उठाया था। राजसमंद की विधायक दीप्ती माहेश्वरी और सूबे के राजपूत संगठनों ने भी इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को भेजे पत्र में एएसआइ को उचित कदम उठाने के लिए आदेश जारी किए जाने का आग्रह किया था। इसी मामले में मेघवाल ने एएसआइ को कार्रवाई के लिए आदेश दिए थे।

झारखंड में 15 लाख का इनामी नक्सली ढेर

जागरण टीम, रांची

पिछले दो दिनों से गुमला के जंगल में विस्फोट कर एक ग्रामीण व सुरक्षा बल के श्वान की जान लेने वाले 15 लाख के इनामी नक्सली बुद्धेश्वर उरांव को पुलिस और सुरक्षा बलों ने गुरुवार को मार गिराया। गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र स्थित केरागनी जंगल में गुरुवार सुबह पुलिस ने नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। बुद्धेश्वर उरांव नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का रीजनल कमेटी सदस्य था। वह माओवादियों के कोयल शंख जोन का सचिव भी था। बुद्धेश्वर पर हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, रंगदारी, आगजनी, पुलिस पार्टी पर हमला व अन्य नक्सली घटनाओं से संबंधित कुल 109 मामले विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। इनमें गुमला में 81, सिमडेगा में 16, लोहरदगा में चार, लातेहार में छह व गढ़वा में दो कांड दर्ज हैं। वह गुमला जिले के गुमला थाना क्षेत्र के ही खटंगा पाकरटोली का रहने वाला था।

छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर, हथियार वरामद

नईदुनिया, दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में ढोलकाल की पहाड़ियों में गुरुवार देरशाम दंतेवाड़ा से निकली डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें तीन नक्सलियों को मार गिराया गया। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में एक लाख का इनामी बिरजू कैकम मिलिशिया प्लाटून कमांडर, जग्गू कैकम और अजय ओयामी शामिल हैं।

कोरोना काल में घरेलू विमान यात्रियों को बरतनी होगी सावधानी

देश में कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इसे देखते हुए राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर कई तरह की छूट देने की घोषणा कर दी है। कई जगह लाकडाउन में छूट के साथ ही विमान से आने वाले घरेलू यात्रियों के लिए भी सख्ती में कमी की गई है। हाल में जारी इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि किसी राज्य में पहुंचने पर किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

- **दिल्ली :** दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विमान से आने वाले यात्रियों को येलो, एंबर, आरेंज और रेड चार श्रेणियों में बांटकर छूट का अलग-अलग पैमाना तय किया है। पांच फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले प्रदेशों से आने वालों को रेड में रखा गया है। कोरोना के नए म्यूटेंट वाले प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को वैक्सीन के दोनों डोज का प्रमाणपत्र या 72 घंटे के अंदर की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, दोनों में किसी के भी ना होने पर 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी होगा।



- **महाराष्ट्र :** कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके यात्रियों को महाराष्ट्र पहुंचने पर निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रविधान इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि महाराष्ट्र से बहुत से लोग दिल्ली में कारोबार के उद्देश्य से जाते हैं और उसी दिन लौट आते हैं। ऐसे में उनके लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट पाना संभव नहीं हो पाता है।
- **हिमाचल प्रदेश :** राज्य में प्रवेश के लिए यात्रियों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
- **आंध्र प्रदेश :** यात्रियों को निगेटिव रिपोर्ट से छूट, हालांकि थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड एंटीजन टेस्ट एयरपोर्ट पर होता रहेगा। साथ ही यात्रियों को राज्य सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
- **असम :** निगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं, थर्मल स्क्रीनिंग और रैपिड एंटीजन टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाता रहेगा। यात्रियों को सात दिन के लिए खुद को क्वारंटाइन भी करना होगा।
- **कर्नाटक :** महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। कहा गया है कि निगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों को ही बोर्डिंग पास दिया जाएगा।
- **गोवा :** सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। राज्य सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को बिना निगेटिव रिपोर्ट प्रवेश की सिफारिश की है।
- **बंगाल :** सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। (मीडिया इनपुट)

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती दे रहे मंडाविया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कवायद
- पिछले हफ्ते घोषित 23 हजार करोड़ के पैकेज की तैयारियों की समीक्षा की



मंत्री मांडविया की चिंता। फाइल फोटो

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कोरोना की तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए जुट गए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने पिछले हफ्ते घोषित दूसरे पैकेज को लागू करने की तैयारियों का समीक्षा की। मंडाविया ने राज्य सरकार को पैकेज के तहत मिलने वाली राशि की खर्च का पूरा ब्योरा जल्द-से-जल्द भेजने को कहा है, ताकि उन्हें तत्काल धन आवंटित किया जा सके।

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मनसुख मंडाविया ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए जरूरी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में मुख्य तौर पर जिला और ब्लाक स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे की कमियों की समीक्षा की गई और उन्हें तीसरी लहर से निपटने लायक बनाने के लिए जरूरी कदमों पर विचार किया गया। मंडाविया ने दूसरे पैकेज के तहत जिला और ब्लाक स्तर पर जरूरी दवाओं, आक्सीजन, अस्पताल और बिस्तरों की उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को राज्यों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मंडाविया ने जिला स्तर के अस्पताल को हब बनाते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ व वेलनेस सेंटरों को स्पोक प्रणाली (पहिए की तीलियों की तरह) से जोड़े जाने पर बल दिया। ताकि जिले में निचले स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जा सके। ग्रामीण इलाकों में मेकशिफ्ट हास्पिटल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।

राज्यों को 40.31 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज मुहैया कराई : केंद्र

बचाव का टीका ▸ राज्यों को जल्द ही 83 लाख से अधिक कोरोनारोधी टीके मिलेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 40.31 करोड़ से अधिक कोरोनारोधी टीके की डोज दी जा चुकी हैं। इनमें से 1.92 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त डोज राज्यों और निजी अस्पतालों के पास बची हुई हैं। राज्यों को इनके अलावा 83,85,790 और डोज जल्द ही मुहैया करा दिए जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार अब तक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 40.31 करोड़ (40,31,74,380) से अधिक डोज दी गई हैं। देश में टीकाकरण कार्यक्रम का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। नए चरण में, केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 फीसद टीकों की खरीदकर राज्यों को मुफ्त में आपूर्ति करेगी।

सुबह आठ बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामल	41,806
कुल मामले	3,09,87,880
सक्रिय मामले	4,32,041
मौतें (24 घंटे में)	581
कुल मौतें	4,11,989
ठीक होने की दर	97.28 फीसद
मृत्यु दर	1.39 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.15 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.21 फीसद
जांचें (बुध.)	19,43,488
कुल जांचें (बुध.)	43,80,11,958

खुशफहमी न पालें, लापरवाही से फिर बढ़ सकते कोरोना के मामले

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों के साथ देश के अनेक हिस्सों में, खासतौर पर हिल स्टेशनों पर कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले को उठाया और महामारी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कदम उठाने की जरूरत बताई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि इस समय खुशफहमी पालने से कोरोना के मामले फिर से बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि देश के अनेक भागों, विशेष रूप से हिल स्टेशनों, सार्वजनिक परिवहन और बाजारों में कोविड नियमों का उल्लंघन होते देखा गया है। यह कहने की जरूरत नहीं कि इस समय पर इतनी खुशफहमी संक्रमण के मामलों में एक बार और इजाफा कर सकती है। भूषण ने कहा कि जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करने की जरूरत है।

पुडुचेरी में कोरोना से पीड़ित 20 बच्चे अस्पताल में भर्ती

पुडुचेरी, प्रेट्र : पुडुचेरी में गुरुवार को कोरोना से पीड़ित 20 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के निदेशक एस मोहन कुमार ने बताया कि इन बच्चों को कादिरकमम स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। इन बच्चों के बारे अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं।

50 हजार आदिवासी गांवों में टीकाकरण अभियान होगा तेज

- गलतफहमियां और मिथक दूर करने को किए जाएंगे विशेष प्रयास
- 309 जिलों के पचास लाख लोगों तक पहुंचने की तैयारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच कोरोनारोधी टीकाकरण तेज करने के लिए गुरुवार को एक अभियान शुरू किया जिसके तहत नेताओं और स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल करके टीकों के बारे में मिथकों, गलतफहमियों और डर को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य करीब 50 लाख आदिवासियों और वन वासियों के बीच टीकाकरण को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के तहत 309 जिलों में 50,000 से अधिक गांव आएंगे।

आदिवासी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाला ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन (टीआरआइएफईडी) इस अभियान को लागू कर रहा है जो छत्तीसगढ़ में बस्तर और मध्य प्रदेश में मांडला से बुधवार को शुरू हुआ। वह संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष (यूनीसेफ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ मिलकर इस अभियान को लागू करेगा। अधिकारियों के मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य करीब 50 लाख आदिवासियों और वन वासियों के बीच टीकाकरण को लेकर जागरूकता पैदा करना है। इस अभियान के तहत 309 जिलों में 50,000 से अधिक गांव आएंगे।

आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह अभियान अनुसूचित जनजातियों के साथ मजबूत संबंध बनाने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के संबंध में कई मिथक और भ्रम हैं। यह अभियान इन बाधाओं को हटाने पर ध्यान केंद्रित करता है। हमें संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ानी है। एक अधिकारी ने कहा कि हमें सही संदेश भेजने की आवश्यकता है कि टीका गंभीर बीमारियों और मौत होने से बचाता है। कई लोगों को लगता है कि टीके से ताकत कम हो जाती है जिससे उनकी आजीविका पर असर पड़ सकता है या उन्हें टीका लगवाने के बाद शराब से दूर रहना होगा। कुछ लोग तो कोरोना की मौजूदगी को ही नकारते हैं। अधिकारी ने कहा कि आदिवासी लोगों का स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों और पारंपरिक नेताओं पर अधिक भरोसा होता है, उनकी मदद से ही मिथक तोड़ेंगे।

केरल में पांच और लोगों को जीका संक्रमण

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में जीका वायरस के क्लस्टर मिलने की चिंताओं के बीच पांच और लोगों को इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें चार महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 28 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जार्ज ने गुरुवार को बताया कि नए मामलों में से दो अनायारा इलाके से हैं, जहां तीन किलोमीटर के क्षेत्रफल में जीका के कलस्टर की पहचान की गई है। अन्य मामले ईस्ट फोर्ट, कुन्नुकुझी व पैट्टोम से आए हैं। सभी नमूनों की जांच आलप्पुझा स्थित नेशनल वायरोलाजी इंस्टीट्यूट में हुई है। मंत्री ने कहा कि निगरानी के क्रम में चार नमूने निजी अस्पताल की तरफ से भेजे गए थे, जबकि एक स्वास्थ्य विभाग की ओर से। हालांकि, उन्होंने बैठक के बाद कहा कि राज्य में फिलहाल जीका वायरस के आठ सक्रिय मामले हैं, इनमें से तीन गर्भवती महिलाएं हैं। गर्भवती महिलाओं को खास सतर्कता बरतनी चाहिए।

उत्तराखंड में घुसने पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे कांवड़ यात्री

जागरण संवाददाता, देहरादून

- सरकार के कांवड़ यात्रा रद करने के फैसले पर अमल के लिए बनाई रणनीति
- डीजीपी ने जिला पुलिस कप्तानों को सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के लिए निर्देश

उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा रद करने के फैसले पर अमल के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कांवड़ यात्री उत्तराखंड की सीमा में घुसता है तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। सीमाओं पर चौकसी बरतने के साथ ही आसपास के रेलवे और बस स्टेशनों पर पुलिस टीम तैनात रहेगी। यहां पहुंचने वाले कांवड़ यात्रियों को शटल सेवा या अन्य माध्यमों से उत्तराखंड की सीमा के पार छोड़ा जाएगा।

गुरुवार को पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के साथ डीजीपी अशोक कुमार ने बैठक कर कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में न आने देने के लिए रणनीति तैयार की। उन्होंने हरिद्वार, देहरादून, टिहरी व पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी को कांवड़ इंफोर्समेंट टीम का गठन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कांवड़ यात्री उत्तराखंड की सीमा में दिखाई दें तो उन्हें बस या अन्य माध्यम से वापस भिजवा दें। ट्रेन से आने वाले कांवड़ यात्रियों को रोकने के लिए हरिद्वार और अन्य रेलवे स्टेशनों पर रोक लिया जाए। इन्हें भी बस या दूसरे संसाधनों से वापस भेज दें।

डीजीपी ने गढ़वाल रेंज के डीआइजी को निर्देश दिए कि हरिद्वार जिले के सीमावर्ती थानों की पुलिस के साथ जल्द बैठक करें। इसमें सीमावर्ती राज्यों के पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को बुलाएं।

आयुर्वेद ने एलोपैथ के मुकाबले बेहतर लड़ी लड़ाई

कुमार संजय, लखनऊ

कोरोना के इलाज में आयुर्वेद एलोपैथ के मुकाबले अधिक कारगर साबित हुआ। 120 कोरोना के मरीजों पर शोध के बाद यह साबित किया है लोकबंधु राज नारायण अस्पताल के आयुर्वेद और एलोपैथ के विशेषज्ञों की टीम ने।

कोरोना संक्रमित इन मरीजों को तीन वर्गों में बांट कर शोध किया गया। ए, बी और सी समूह में 40-40 मरीजों को रखा गया। ए और बी समूह के मरीजों को विशेष आयुर्वेदिक दवाएं दी गईं और सी समूह के रोगियों को एलोपैथिक दवाएं। दवाएं देने के बाद उनमें 10 दिनों के अंदर लक्षणों में आराम और कोरोना निगेटिव होने में लगने वाले समय का अध्ययन किया गया। शोध में लोकबंधु अस्पताल व नेशनल हेल्थ मिशन आयुष के चिकित्सकों ने भी भाग लिया। यह शोध जर्नल आफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। शोध में बुखार, गले में खराश,सांस की तकलीफ, नाक बहना आदि लक्षण वाले मरीजों को शामिल किया गया।

इन्होंने किया शोध

लोकबंधु अस्पताल के पंचकर्म विशेषज्ञ डा. आदिल रईस, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. अमिता यादव, डा. महेंद्र यादव, चिकित्सा अधीक्षक डा.पीएन अहिरवार, नेशनल हेल्थ मिशन के डा. हिमांशु आर्य, डा. रामजी वर्मा, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ आयुर्वेद के डा. अबसार अहमद, कम्युनिटी मेडिसिन कैरियर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस के डा. आर गालिब और डीजी हेल्थ डा. डीएस नेगी।

किस वर्ग के मरीजों को क्या दीं दवाएं

समूह ए : व्याघ्रांदि कषाय 50 एमएल दो बार, पिपली पाउडर 50 ग्राम सुबह और शाम खाली पेट, 500 मिली ग्राम, दो बार समशमणि वटी।

समूह बी : दो ग्राम शुंठी दो बार, रसोना पेस्ट एक ग्राम एक बार।

समूह सी : विटामिन सी 500 मिली ग्राम दो बार, 500 मिलीग्राम पैरासिटामाल।

शोध परिणाम

ग्रुप सी की तुलना में ग्रुप ए और बी में पहले वायरल क्लीयरेंस (कोरोना निगेटिव) के साथ जल्दी रिकवरी देखी गई थी। ग्रुप बी और सी की तुलना में ग्रुप ए में बुखार, खांसी, गले में खराश और चिड़चिड़ापन में अधिकतम राहत देखी गई। समूह सी के कुछ रोगियों में उचित स्वाद और गंध का नुकसान अधिक था।

चित्तौड़गढ़ किले के कीर्तिस्तंभ को आकाशीय बिजली से नुकसान



भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने गुरुवार को कीर्ति स्तंभ पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। जागरण

संवाद सूत्र, उदयपुर

राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की तो जान गई ही, चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ तथा भीलवाड़ा के जैन मंदिर को नुकसान भी पहुंचा है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने कीर्ति स्तंभ का चालीस किलो वजनी पत्थर टूटकर गिरने की पुष्टि की है।

चित्तौड़गढ़ किले में मौजूद कीर्ति स्तंभ के उत्तरी दिशा में बीच के माले में लगी बड़ी प्रतिमा के नीचे सहारे के लिए लगा पत्थर आकाशीय बिजली गिरने से टूट गया है। किले के संरक्षण सहायक आरएल जितरवाल ने बताया कि नुकसान की सूचना जोधपुर मंडल मुख्यालय को भेज दी गई है।

आकाशीय बिजली गिरने से कीर्ति स्तंभ के पास बगीचे में लगे पीपल के दो पेड़ भी काले पड़ गए और वहां एक गढ्ढा बन गया है। उधर, भीलवाड़ा के आजादनगर में मार्बल से बने चंद्रशेखर जैन मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही मंदिर की दीवार में दरार पड़ गई है। स्तंभ पर तीसरी बार बिजली गिरी है।

40 करोड़ की सालाना आय होती है आमेर किले से पर्यटन विभाग को

35-40 हजार रुपये खर्च में लग सकता है तड़ित चालक

इसलिए लगाए जाते हैं तड़ित चालक

आकाशीय बिजली का प्रभाव कम करने के लिए इमारत अथवा स्मारक से छह मीटर ऊंचाई पर तड़ित चालक लगाए जाते हैं। आमेर किले के नीचे एक छोटा तड़ित चालक लगा हुआ है, जो बिजली का प्रभाव कम करने में बहुत ज्यादा कारगर नहीं है। तड़ित चालक तांबे की बनी ऐसी स्टिक (छड़) होती है, जो ऊंची इमारतों पर बिजली गिरने की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है।

कई बार बैठकों में उच्च अधिकारियों का इस ओर ध्यान दिलाया गया है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है।
-पंकज धीरेंद्र, आमेर किले के अधीक्षक

...तो आमेर किले में नहीं जाती 12 की जान

जयपुर के आमेर किले में वाच टावर पर तीन दिन पहले आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत होने के साथ ही 10 लोग घायल हो गए थे। अब सामने आया कि इन मौतों के लिए काफी हद तक सरकारी सिस्टम भी जिम्मेदार है। दरअसल, आमेर किला प्रशासन और विशेषज्ञ करीब नौ साल से लगातार राज्य सरकार को पत्र लिखकर यहां तड़ित चालक लगाने की मांग कर रहे थे।

लाल किला हिंसा पर एलजी ने नकारा दिल्ली सरकार का वकीलों का पैनल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर लाल किले सहित कई जगहों पर हिंसा व तोड़फोड़ की थी। आरोपित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में पुलिस व राज्य का पक्ष रखने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित वकीलों के पैनल को उपराज्यपाल (एलजी) ने खारिज कर दिया है। एलजी ने दिल्ली पुलिस की ओर से सुझाए गए वकीलों के पैनल पर कैबिनेट की मुहर लगाने पर फैसला लेने को कहा है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस अपने वकीलों का पैनल नियुक्त कराना चाहती है। वकीलों का एक पैनल बनाकर अनुमोदन के लिए दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को भेजा था।

राजनीति से अछूता नहीं रहा है कृषि कानून विरोधी आंदोलन

संजय निधि, सोनीपत

कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा आंदोलन को राजनीति से दूर रखने की बात कही जाती है, लेकिन आंदोलन राजनीति से अछूता नहीं है। राजनीतिक बात करने पर गुरनाम चढूनी पर की गई निलंबन की कार्रवाई पर चढूनी के समर्थक सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि अकसर राजनीतिक बात करने वाले भाकियू नेता राकेश टिकैत पर अब तक मोर्चा ने एक बार भी कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उनको लेकर कोई बयान ही दिया है। बता दें कि चढूनी ने मिशन पंजाब के तहत चुनाव में किसान संगठनों को उतरने की सलाह दी थी। इसे उन्होंने अपना विचार बताया था और इस पर वह अब भी कायम हैं।

22 जुलाई से हर दिन संसद जाएंगे 200 किसान : टिकैत

जासं, ऊधम सिंह नगर : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में किसान आठ माह से आंदोलन पर हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार किसानों की मांग सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके लिए 22 जुलाई से हर रोज 200 किसानों का एक जत्था संसद जाएगा। सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। गुरुवार को सितारगंज पहुंच टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार किसानों के हौसले नहीं तोड़ सकती। सरकार को एक दिन कानून वापस लेना ही पड़ेगा। संसद जाकर किसान दबाव बनाएंगे।

पश्चिम चंपारण में संदिग्ध परिस्थितियों में आठ की मौत

जासं, पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत देउरवा पंचायत में बीते दो दिनों में संदिग्ध परिस्थितियों में आठ लोगों की मौत की खबर है। कई लोग बीमार हैं। सभी निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, मृतकों में देउरवा के बिकाऊ मियां, लतीफ साह, रामवृक्ष चौधरी, भगवान पंडा, जोगिया देवराज के नईम हजाम व सुरेश साह, बगही देवराज के राबुल मियां और गौनाहा देवराज के झुन्ना मियां शामिल हैं। इस संबंध में पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा है कि लौरिया प्रखंड की देउरवा पंचायत के अलग-अलग गांवों में दो लोगों की मौत की सूचना है। वहां मेडिकल टीम भेजकर जांच कराई जा रही है। चर्चा है कि दो दिन पूर्व देउरवा गांव की एक दुकान पर सभी जुटे थे।

गैस कांड पर तेलुगु फिल्म की भोपाल में शूटिंग शुरू

सुशील पांडेय, भोपाल

- थाप्पिनचुकोलेर फिल्म में गैस का हथियार के रूप में इस्तेमाल दिखाया जाएगा
- विदेशी आतंकी और रॉ के इर्द-गिर्द बुनी गई कहानी दर्शकों को सचेत भी करेगी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला फिर से चल पड़ा है। अभी चार फिल्मों की शूटिंग अलग-अलग लोकेशन पर चल रही है। इनमें भोपाल की तीन दिसंबर, 1984 की भीषण गैस त्रासदी पर आधारित तेलुगू फिल्म थाप्पिनचुकोलेर की शूटिंग प्रमुख है, जो पुराने शहर के बाद मंडीदीप में चल रही है। इसमें एक आतंकी गैस कांड को वारदात के रूप में दोहराना चाहता है।

'थाप्पिनचुकोलेर' का मतलब है कोई नहीं बच सकता। यह थ्रिलर फिल्म एक विदेशी आतंकी पर आधारित है, जो भोपाल गैस कांड हादसे का कारण बनी जहरीली गैस का इस्तेमाल कर बड़ी संख्या में लोगों को मारने का षड्यंत्र रचता है। इसके लिए वह भेष बदलकर विदेश से भोपाल आता है, लेकिन इसकी भनक देश की खुफिया एजेंसी 'रॉ' को लग जाती है। गैस कांड की बरसी के कुछ दिन पूर्व भोपाल पहुंचे आतंकी समेत 14 लोगों को 'रॉ' के अधिकारी क्वारंटाइन कर लेते हैं लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि इन 14 लोगों में से आतंकी कौन है। साजिशकर्ता का पता लगाने के लिए 'रॉ' एजेंट इन सभी की गतिविधियों पर नजर रखने लगते हैं। गैस कांड की बरसी पर यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास लोग गैसकांड के मृतकों को श्रद्धांजलि देने जमा होते हैं, तभी ड्रोन की मदद से जहरीली गैस से भरी टंकी को खोलने की साजिश करता है।

किसान की तीन बेटियां एकसाथ बनीं आरएएस अधिकारी

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर



अंशु सहारण की फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया



रितु सहारण की फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया



सुमन सहारण की फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया

राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के भैरूसरी गांव की तीन सगी बहनों का एकसाथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) में चयन हुआ है। तीनों बहनों ने एक साथ आरएएस अधिकारी बनकर इतिहास रचा है। किसान की तीनों बेटियों ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति और अच्छी परवरिश की जाए तो बेटियां बोझ नहीं होती हैं। इनकी दो बड़ी बहनें पहले से आरएएस अधिकारी हैं। बेटियों की इस उपलब्धि की चर्चा हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में हैं।

आरएएस में चयनित हुई तीनों बहनों सुमन, अंशु और रितु सहारण ने साल, 2018 में आरएएस की परीक्षा दी थी, जिसका दो दिन पहले परिणाम आया है। बेटियों की इस कामयाबी के कारण पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। दो दिन से जश्न मनाया जा रहा है। मिठाई बांटी जा रही है। अपनी बेटियों की कामयाबी से खुश पिता सहदेव सहारण और मां मीरा का कहना है कि मैंने बेटियों को शुरू से ही अच्छी शिक्षा देने पर बल दिया था। बचपन से ही उन्हें बड़ा अधिकारी बनने को लेकर प्ररित किया था। उन्होंने बताया कि मेरी दो बड़ी बेटियों में एक रोमा विकास अधिकारी है, वहीं दूसरी मंजू सहकारिता विभाग में इंस्पेक्टर है। मैं बड़ा खुशसीब हूं।

पिता बोले-बेटों की चाहत रखने वालों के लिए सबक: पांचों बेटियों के अधिकारी बनने के बाद उनके पिता सहदेव कहते हैं कि बेटों की चाहत रखने वालों को अब सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने बेटियों को कभी अभिशाप नहीं समझा, बल्कि उन्हें हीरे की तरह निखारा। उनकी हर बात पर ध्यान दिया। मैंने जब बेटियों को पढ़ाया तो समाज के लोगों ने ताना दिया कि बेटियों को इतना पढ़ाकर क्या करोगे।

सरकारी स्कूल में की पढ़ाई

तीनों बहनों सुमन,अंशु और रितु ने बताया कि उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसके बाद अलग-अलग स्कूलों में भर्ती हुई। तीनों में अंशु ने ओबीसी गर्ल्स में 31, रितु ने 96 और सुमन ने 98वीं रैंक हासिल की है। अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को देते हुए तीनों बहनें बोली, अब हम समाज की सेवा करने के साथ ही बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देंगे।

प्रेरणा बनीं बड़ी बेटियों ने की मदद

सहदेव ने कहा कि मेरी दो बड़ी बेटियों में एक रोमा का साल, 2011 और दूसरी मंजू का 2012 में आरएएस में चयन हुआ तो छोटी बहनों को भी उनसे प्रेरणा मिली। दोनों बड़ी बहनें भी पढ़ाई को लेकर तीनों की लगातार मदद करती थीं।

तीनों बहनें बोलीं-लक्ष्य तय कर तैयारी की

सुमन,अंशु और रितु का कहना है कि दो बड़ी बहनों का आरएएस में चयन होने के बाद हमने भी लक्ष्य तय कर अधिकारी बनने को लेकर तैयारी शुरू की थी।

मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध से कई बैंकों पर दबाव

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा मास्टरकार्ड को नया ग्राहक बनाने से रोक दिए जाने के बाद कई बैंकों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। इनमें वे बैंक ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिनके कार्ड कारोबार का बड़ा हिस्सा मास्टरकार्ड पर आधारित है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा का कहना है कि आरबीएल बैंक, यस बैंक और बजाज फिनसर्व को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका पूरा क्रेडिट कार्ड कारोबार मास्टरकार्ड आधारित है। (आइएएनएस)

रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज को वर्ष 2024 तक विस्तार देना क्रांतिकारी निर्णय है। इससे उद्योगों को निवेश प्रस्ताव के मूल्यांकन में मदद मिलेगी।

— दीपाली गोयनका, एमडी, वेलस्पन इंडिया



सेंसेक्स	53,158.85	▲	254.75
निफ्टी	15,924.20	▲	70.25
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 47,443	▲	₹ 177
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 68,277	▲	₹ 83
डॉलर	₹ 74.54	▼	₹ 0.05
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 74.24		

बेबीवियर सेग्मेंट में उतरा खादी

जाब्यू, नई दिल्ली : अब बच्चे भी खादी के कपड़े पहन सकेंगे। एमएसएमई मंत्रालय के अधीन काम करने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) ने बच्चों के लिए खादी के बेबीवियर लांच किए है। केवीआइसी ने हैंडमेड पेपर से बनी चप्पल भी लांच की है, जो 'यूज एंड थ्रो' श्रेणी की होगी। गुरुवार को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इन दोनों उत्पाद को लांच किया। दोनों ही उत्पादों की बिक्री शुरू हो गई है और खादी ग्रामोद्योग इसकी आनलाइन बिक्री भी कर रहा है। केवीआइसी के मुताबिक नवजात से लेकर दो वर्ष तक के बच्चों के लिए बेबी वियर लांच किया गया है। इनमें फ्राक, झबला, नैपीज शामिल हैं। इनकी कीमत 599 रुपये रखी गई है।

केवीआइसी ने हैंडमेड पेपर से बनी चप्पल की कीमत 50 रुपये निर्धारित की है। इस चप्पल का उपयोग पांच-छह दिनों तक किया जा सकता है। इसे अधिकतम डेढ़ किमी तक पहन कर चला जा सकता है। होटल और अस्पताल जैसी जगहों को ध्यान में रखकर यह हैंडमेड चप्पल बनाई गई है।

पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत की उम्मीद, क्रूड में दिखी नरमी

सस्ते आयात के लिए कई देशों से भारत की हो रही बातचीत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गुरुवार को देश की जनता को पेट्रोल व डीजल के खुदरा मूल्यों में एक और वृद्धि की मार झेलनी पड़ी है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे संकेतों के हिसाब से हफ्ते-दस दिनों में कीमतों में नरमी आ सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में तकरीबन छह माह की लगातार वृद्धि के बाद अब कमी आ रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में क्रूड 78 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था जो अब घट कर 73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। तेल कंपनियों का कहना है अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर पेट्रोल-डीजल पर 12-15 दिनों में दिखता है।

दूसरी तरफ, दो प्रमुख तेल उत्पादक देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में तेल उत्पादन को लेकर सहमति बनने के बाद माना जा रहा है कि अब क्रूड की कीमतों में कुछ समय तक स्थिरता का माहौल रहेगा। दोनों देशों में सहमति से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ेगा जिससे कीमतों पर लगाम लग सकेगी। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में अगले छह माह तक क्रूड की कीमत के 72 डॉलर के करीब स्थिर रहने का अनुमान लगाया है। अगर ऐसा होता है तो देश में पेट्रोल व डीजल की कीमत में करीब दो रुपये प्रति लीटर की कमी की सूरत बन रही है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बढ़ी हुई कीमत व इससे भारत को हो रही परेशानी को लेकर तेल आपूर्तिकर्ता देशों से बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने कुवैत व यूएई के ऊर्जा मंत्रियों से बात की है। इन दोनों देशों से भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। भारत अपनी जरूरत का 85 फीसद क्रूड आयात करता है।



गुरुवार को भी बढ़ा पेट्रोल और डीजल का दाम • फाइल फोटो

पेट्रोल का दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा : गुरुवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे और डीजल में 15 पैसे की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल अब 101.54 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल के दाम में इस वर्ष चार मई से अब तक 40 बार बढ़ोतरी हो चुकी है।

आइटी और फाइनेंस स्टाक्स में मजबूती से सेंसेक्स नए रिकार्ड पर

मुंबई, प्रेट्र : आइटी व फाइनेंशियल सेक्टर के स्टाक्स में निवेशकों की अच्छी दिलचस्पी की वजह से गुरुवार को बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक नई रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 254.75 अंक यानी 0.48 फीसद मजबूत होकर रिकार्ड 53,158.85 अंक पर बंद हुआ। इंट्रा-डे में यह 53,266.12 के रिकार्ड उच्च स्तर तक पहुंचा था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 70.25 अंक यानी 0.44 फीसद की तेजी के साथ 15,924.20 के नए रिकार्ड पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में पांच फीसद से अधिक की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में एचसीएल टेक रही। एलएंडटी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइटीसी और टाटा स्टील में भी अच्छी तेजी रही।

दूसरी तरफ, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, टाइटन और सन फार्मा समेत अन्य शेयर नुकसान में रहे।

केंद्र ने राज्यों को दी 75,000 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति

राहत

- केंद्र ने एक ही बार में लगभग आधी क्षतिपूर्ति का किया भुगतान
- शेष रकम का भुगतान इस वर्ष सितंबर के बाद से किया जाएगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को गुरुवार को 75,000 करोड़ रुपये जारी किए। यह रकम चालू वित्त वर्ष (2021-22) में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में जारी होने वाली कुल रकम की लगभग आधी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 28 मई को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में क्षतिपूर्ति के लिए इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि केंद्र सरकार फिर से राज्यों की तरफ से 1.59 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। यह व्यवस्था बीते वित्त वर्ष में केंद्र एवं राज्यों की सहमति से अपनाई गई थी। इसके तहत बीते वित्त वर्ष में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में 1.10 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 1.59 लाख करोड़ रुपये में से 75,000 करोड़ रुपये गुरुवार को जारी किए गए। शेष रकम इस वर्ष सितंबर के बाद जारी की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से राज्यों पर भी वित्तीय दबाव है, जिससे निपटने में मदद के लिए एक बार में 75,000 करोड़ जारी करने का फैसला किया गया। इससे राज्यों को हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा को बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। जानकारों का कहना है केंद्र की तरफ से महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अब राज्य सरकारें भी महंगाई भत्ते बढ़ाएंगी, जिसके लिए उन्हें रकम की जरूरत होगी।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में दिए जाने वाले 1.59 लाख करोड़ रुपये सेस कलेक्शन के आधार पर क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने वाले एक लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त होंगे। इस प्रकार राज्यों को चालू वित्त वर्ष में 2.59 लाख करोड़ दिए जाएंगे।

पेंशनरों को वाट्सएप के जरिये भी मिल सकेगी पेंशन पर्ची

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा है कि बैंक खाते में रकम आने पर वे एसएमएस और ईमेल के अलावा वाट्सएप जैसे एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर पेंशनधारकों को उनकी पेंशन पर्ची भेज सकते हैं। एक आधिकारिक आदेश के अनुसार पेंशनधारकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।

पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बैंक अब एसएमएस और ईमेल के अलावा वाट्सएप आदि इंटरनेट मीडिया एप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले महीने पेंशन देने वाले बैंकों के केंद्रीय पेंशन वितरण केंद्रों (सीपीपीसी) की एक बैठक हुई, जिसमें पेंशनधारकों की मासिक पेंशन पर चर्चा हुई। बैंक इस कल्याणकारी उपाय को शुरू करने को लेकर काफी प्रभावित थे, क्योंकि पेंशनरों को आयकर, महंगाई राहत भुगतान और अन्य मामलों में इस सूचना की जरूरत पड़ती है। बैंकों ने इस विचार का स्वागत किया और यह सूचना मुहैया कराने की इच्छा जताई।

भारत के हिस्से की मछली पकड़ने वाले देशों पर केंद्र सरकार सख्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चीन समेत कई विकसित देश भारत के हिस्से की भी मछली समंदर से पकड़ रहे हैं। ये विकसित देश मछली पालन पर अधिक सब्सिडी देते हैं जिससे विकासशील देशों का मछली पालन उद्योग प्रभावित हो रहा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विकसित देशों द्वारा दी जा रही अधिक सब्सिडी पर कड़ा एतराज जताया है। मछली पालन की सब्सिडी समझौता से जुड़ी वार्ता पर डब्ल्यूटीओ की तरफ से बुलाई गई बैठक में शुक्रवार को वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस समझौते को जल्द अंतिम रूप देना चाहता है। उन्होंने बैठक में कहा कि मछली पालन पर कई देशों की अतार्किक सब्सिडी से भारत के मछली पालन उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। कई अन्य देशों द्वारा भारत के हिस्से की मछली पकड़ने से भी मछुआरों का जीवन-यापन प्रभावित हो रहा है।



पीयूष गोयल • फाइल फोटो

ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 10 प्रमुख देश अपने मछली पालन उद्योग को भारी सब्सिडी देते हैं और उन देशों के मछुआरे दूसरे विकासशील देशों की समुद्री सीमा में आकर मछली पकड़ते हैं। मछली पालन पर भारी सब्सिडी देने वालों में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस, स्पेन, ताइवान, नार्वे, थाइलैंड जैसे देश शामिल हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में इन देशों ने मछली पालन उद्योग की सब्सिडी के मद में 15.3 अरब डालर यानी लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए।

गोयल ने कहा कि 30 वर्ष पहले कृषि क्षेत्र में सब्सिडी को लेकर किए गए समझौते की गलती को नहीं दोहराना चाहिए जिसके तहत कुछ विकसित देशों को असमान रूप से सब्सिडी देने की इजाजत मिल गई थी। उन्होंने कहा कि मछली पालन उद्योग को अधिक सब्सिडी देने वाले देशों को सब्सिडी की रकम और पकड़ी जाने वाली मछली की मात्रा, इन दोनों को घटाने की जरूरत है।

इकोनामी में अभी बनी रहेगी मांग की समस्या : आरबीआइ

9.5 फीसद की ग्रोथ होने के बावजूद इकोनामी में कई कमजोरी रहेगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश की इकोनामी में तेजी से सुधार हो रहा है और तेजी से वैक्सीनेशन होने के बाद स्थिति और बेहतर हो सकती है। लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों के हालात की वजह से मांग पर जो असर पड़ा है उसमें सुधार आने में वक्त लगेगा। यह बात आरबीआइ ने गुरुवार को जारी इकोनामी पर मासिक रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में 9.5 फीसद की ग्रोथ रेट हासिल करने के संकेतों के बावजूद देश की इकोनामी में कई तरह की कमजोरियां हैं, जो बनी रहेंगी। खासतौर पर मांग की स्थिति में बेहतरी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में अच्छा संकेत यह है कि इसमें महंगाई की स्थिति को लेकर बहुत चिंता नहीं जताई गई है। मई-जून, 2021 में महंगाई की दर के निर्धारित स्तर से ऊपर रहने को रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट में खास तवज्जो नहीं दी है। बैंक ने वर्ष के अंत तक इसे छह फीसद से नीचे आने की बात कही है। रिपोर्ट में यह भी संकेत है कि ऊंची महंगाई के बावजूद केंद्रीय बैंक अभी ब्याज दरों को बढ़ाने का समर्थन नहीं करेगा।

केंद्रीय बैंक की यह रिपोर्ट देश में मांग की स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डालती है। टीकाकरण में वृद्धि होने की वजह से आने वाले दिनों में आर्थिक गतिविधियों के और बढ़ने के आसार हैं। लेकिन मांग कब तक तेज होगी, इसको लेकर अभी अनिश्चितता है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकों का वित्तीय स्वास्थ्य पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुआ है।

गूगल ने भारत में शुरू किया दूसरा क्लाउड रीजन

नई दिल्ली, प्रेट्र : गूगल क्लाउड इंडिया ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में अपना नया क्लाउड रीजन शुरू किया है। इस रीजन से गूगल को देश में सार्वजनिक क्षेत्र के और पूरे एशिया-प्रशांत में अन्य ग्राहकों की सेवा करने में मदद मिलेगी। यह क्लाउड रीजन भारत में गूगल का ऐसा दूसरा सेटअप है। वैसे, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि इस पर उसने कितना पूंजी निवेश किया। भारत में गूगल का पहला क्लाउड रीजन वर्ष 2017 में मुंबई से लाइव हुआ था। इसमें तीन उपलब्धता जोन थे। दिल्ली-एनसीआर के क्लाउड रीजन में भी इतने ही उपलब्धता जोन हैं।

गूगल का एशिया-प्रशांत में 10वां और विश्व स्तर पर 26वां सेटअप है। क्लाउड रीजन ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहां कोई कंपनी अपने ग्राहकों को यह सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरा तंत्र विकसित करती है।

सरकार ने एलआइसी के लिए सलाहकारों से मांगे आवेदन

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी के प्रारंभिक पब्लिक आफर (आइपीओ) के बारे में सहायता और परामर्श देने के लिए मर्चेंट बैंकरों तथा विधि सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की गई हैं। निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने निविदाएं आमंत्रित करते हुए कहा कि इसके भारतीय बाजार में अब तक का सबसे बड़ा आइपीओ साबित होने की उम्मीद है। आइपीओ की सफलता के लिए जरूरी है कि खुदरा निवेशकों के साथ-साथ घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों की इसमें भरपूर साझेदारी हो।

हिस्सेदारी बिक्री मे सहायता और परामर्श के लिए विभाग अधिकतम 10 मर्चेंट बैंकरों और एक कानूनी सलाहकार कंपनी की नियुक्ति करेगा। मर्चेंट बैंकरों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि पांच अगस्त और कानूनी सलाहकार कंपनी के लिए छह अगस्त है। दीपम ने कहा है कि मर्चेंट बैंकर को आइपीओ के लिए ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया की जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। विभाग ने सेबी में पंजीकृत ऐसे मर्चेंट बैंकरों से आवेदन मांगे हैं जिनके पास वैध सर्टिफिकेट हो। बैंकर कंसोर्टियम के माध्यम से भी बोली दाखिल कर सकते हैं। उनके पास आइपीओ का अनुभव होना चाहिए, जो सरकार को इस प्रक्रिया में सलाह दे सकें।

पिछले सप्ताह कैबिनेट ने आइपीओ को मंजूरी दे दी थी। इसका आकार, मूल्य निर्धारण और उचित समय जैसे पहलुओं का फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

नए सिरे से होगी ट्रकों के फर्जीवाड़े मामले की जांच

देहरादून : दूसरे राज्य से फर्जी एनओसी पर उत्तराखंड लाए गए 40 ट्रकों के पंजीकरण के मामले में अब नए सिरे से जांच होगी। पहली जांच रिपोर्ट का अपर्याप्त मानते हुए आयुक्त परिवहन दीपेंद्र चौधरी ने इसकी फिर से जांच करने का निर्णय लिया है। जल्द इसके आदेश जारी हो जाएंगे। (राब्यू)

बैंक में लूट, कैशियर की समझदारी से दो करोड़ बचे

पलवल : एक्सिस बैंक में 95 लाख 57 हजार की लूट जिस वक्त हुई इस वक्त बैंक में कुल तीन करोड़ रुपये कैश मौजूद था। जल्दबाजी में लुटेरे बैंक से 95 लाख 57 हजार ही अपने साथ ले जा पाए। बैंक में मौजूद कैशियर की समझदारी के कारण लूट के दौरान बैंक से दो करोड़ रुपये लुटने से बच गए। (संस)

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विरुद्ध मुकदमा

अयोध्या : सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के विरुद्ध गुरुवार को दीवानी मुकदमा दायर किया गया है। यह मुकदमा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष दुबे ने वादमित्र की हैसियत से दायर किया है, जिसमें रामकोट स्थित फकीरेराम मंदिर व संपत्ति की बिक्री को चुनौती दी गई है। (जासं)

परमवीर सिंह की जांच करेगी एसीबी

मुंबई : मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच एसीबी करेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राज्य सरकार से जांच की अनुमति मांगी है। (राब्यू)

बंदियों की रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आठ जुलाई को जमानत प्रदान किए जाने के बावजूद उप्र सरकार द्वारा 13 बंदियों को रिहा करने में देरी पर स्वतः संज्ञान लिया है। आगरा केंद्रीय कारागार में बंद ये कैदी नाबालिग थे। (प्रेट)

जासूसी मामले में आगरा कैंट से सेना का लांस नायक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के आरोप में मंगलवार को राजस्थान के पोखरण से रसद ठेकेदार हबीबुर्र रहमान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को आगरा कैंट में तैनात सेना के एक लांस नायक को भी गिरफ्तार कर लिया है। लांस नायक परमजीत सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह गिरफ्तारी पोखरण में सेना को रसद, दूध, मीट व सब्जियां आपूर्ति करने वाले ठेकेदार हबीबुर्र रहमान से पूछताछ के बाद की गई है। दोनों को तीस हजारी कोर्ट स्थित ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशकर दस दिनों के रिमांड पर लिया गया है।

पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि जासूसी मामले में इन दोनों से सेना के कई अधिकारियों व कर्मचारियों के जुड़े होने की जानकारी मिली है। जल्द ही तीन-चार अन्य सैन्यकर्मियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच प्रवीर रंजन के मुताबिक परमजीत के मोबाइल से संवेदनशील डाटा मिला है। दो साल पहले उसकी तैनाती जैसलमेर के पोखरण स्थित सेना के कैंप में रसद आपूर्ति विभाग में थी। उसके आर्डर पर ही बीकानेर निवासी हबीबुर्र रहमान सेना को रसद, दूध, मीट व सब्जियां आपूर्ति करता था। ऐसे में दोनों में जान पहचान हो गई। इसी दौरान हबीबुर्र रहमान ने परमजीत को सेना से जुड़े संवेदनशील दस्तावेज मुहैया कराने के लिए राजी कर लिया था। इसके बाद परमजीत का तबादला जब आगरा कैंट में अतिसंवेदनशील एस्टेब्लिशमेंट विभाग में क्लर्क के तौर पर हुआ तब हबीबुर्र के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। इसके बाद से देश की सुरक्षा व सेना से जुड़े अतिसंवेदनशील गोपनीय दस्तावेज आसानी से मिलने लगे। इन्हें उसने सीधे आइएसआइ अथवा हैंडलरों व पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया।



जासूसी के आरोप में गिरफ्तार लांस नायक परमजीत। सौ पुलिस



हबीबुर्र रहमान। सौ पुलिस

हवाला के जरिये पाकिस्तान से आता था पैसा: संवदेनशील दस्तावेज मुहैया कराने के लिए हबीबुर्र रहमान परमजीत को मोटी रकम देता था। उसके पास पाकिस्तान से हवाला के जरिये पैसा आता था।

वाट्सएप व टेलीग्राम के जरिये मुहैया कराता था दस्तावेज: जांच से पता चला कि हबीबुर्र को परमजीत वाट्सएप व टेलीग्राम के जरिये दस्तावेज मुहैया करता था, जिसे वह आइएसआइ व हैंडलरों को भेज देता था।

एमपी के दो तस्करों ने चार महीने में पंजाब पहुंचाए 400 पिस्तौल

नवीन राजपूत, अमृतसर: मध्य प्रदेश के बडवानी जिले से पकड़े गए दो तस्कर विजय ठाकुर और जीवन पिछले चार महीने में पंजाब के गैंगस्टरों को चार सौ से ज्यादा हथियार सप्लाई कर चुके हैं। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि है कि वह पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जयपाल भुल्लर, बिल्ला मंडियाला और राजस्थान के लारेंस बिशनोई गैंग को 50 से 55 हजार रुपये में पिस्तौल बेचते थे। यही नहीं अगर कोई हथियार रखने का शौकीन पिस्तौल मांगता तो उससे इसकी कीमत 75 से 80 हजार रुपये वसूली जाती थी। मध्य प्रदेश से लेकर अमृतसर तक के रास्ते में हुई पूछताछ में आरोपित विजय ठाकुर ने स्वीकार किया है कि अमृतसर, मजीठा और तरनतारन में उसके चार गुर्गे रहते हैं। इसकी जानकारी मिलते ही काउंटर इंटेलीजेंस (सीआइ) की टीम ने स्थानीय पुलिस की सहायता से वहां दबिश दी, लेकिन आरोपित फरार हैं। उन्होंने अमृतसर के किन लोगों को यह हथियार सप्लाई किए थे।

आतंकी मिनहाज के कई और साथी एटीएस के निशाने पर

आतंक के तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद माड्यूल के आतंकी मिनहाज के तीन सक्रिय साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब उसके कुछ अन्य साथियों की तलाश तेज की गई है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने मिनहाज को पिस्टल दिलाने में खास भूमिका निभाने वाले शकील, मु. मुस्तकीम व मु. मुईद को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया। एटीएस की विशेष अदालत ने तीनों को 29 जुलाई तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। एटीएस ने तीनों की पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए अर्जी कोर्ट में दाखिल की है, जिस पर शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई होगी। एटीएस को मिनहाज को असलहा मुहैया कराने वाले तस्कर के बारे में भी ठोस जानकारी मिली है। जल्द उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। अलकायदा के इन दोनों आतंकियों मिनहाज व मसीरुद्दीन को पिछले दिनों एटीएस ने दुबग्गा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उनसे भारी मात्रा में गोला-बारूद, प्रेशर कुकर बम, पिस्टल आदि बरामद हुए थे। पुलिस व केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने दोनों से पूछताछ की है। इंटरनेट मीडिया के जरिये भी मिनहाज के संपर्क में कई युवक थे। असलहा व विस्फोटक जुटाने के बाद यह माड्यूल कई शहरों में आतंकी घटनाएं करने का षड्यंत्र रच रहा था। इसके लिए अलग-अलग शहर के युवकों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जानी थीं।

सूत्रों का कहना है कि मिनहाज के मोबाइल फोन का कुछ डाटा रिकवर कर लिया गया है। उसके जरिये भी एटीएस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। एटीएस अब शकील, मु. मुस्तकीम व मु.मुईद से भी नए सिरे से पूछताछ किए जाने का इंतजार कर रही है। तीनों का मिनहाज व मसीरुद्दीन से अलग-अलग सामना कराया जाएगा। मसीरुद्दीन ने मुस्तकीम के अलावा कुछ अन्य युवकों को भी मिनहाज से जोड़ा था। लखनऊ के निवासी कुछ अन्य संदिग्ध युवकों की गतिविधियों की छानबीन कराई जा रही है।

बंगाल से जेएमबी का एक और आतंकी गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के एक और आतंकवादी को बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि लालू सेन उर्फ राहुल सेन या राहुल कुमार को बंगाल पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने उत्तर 24 परगना जिले के बारासात नगर निगम स्थित उसके घर से बुधवार रात गिरफ्तार किया। इसके अलावा एसटीएफ ने उत्तर 24 परगना जिले से भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद जब्त कर तीन अन्य को भी गिरफ्तार किया है। लालू सेन गिरफ्तार किए गए जेएमबी के तीन आतंकवादियों का करीबी है। इनसे 10 किलोग्राम विस्फोटक, 20 राउंड गोलियां और 40,000 रुपये नकद बरामद किए गए।

नशा तस्करों, गैंगस्टरों और आतंकियों का गठजोड़ बेनकाब

आतंकी बबला सहित आठ गिरफ्तार

जासं, तरनतारन : खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ) के आतंकी गुरसेवक सिंह बबला के घर में रेड कर पुलिस ने गैंगस्टरों, नशा तस्करों व उनको पनाह देने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस मामले में तरनतारन के गांव माड़ी कंबोके से आतंकी बबला सहित तीन, गांव हरिके से एक तस्कर और पंचकूला से तीन गैंगस्टरों और एक पनाहगार को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से कुल चार पिस्टल, दो राइफलें, 30 कारतूस, एक किलो 550 ग्राम हेरोइन व 22 लाख की ड्रग मनी बरामद की है। पहला मौका है कि तरनतारन पुलिस ने आतंकियों, नशा तस्करों व गैंगस्टरों के गठजोड़ को बेनकाब किया हो।

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी पर दुष्कर्म का केस

जागरण संवाददाता, लखनऊ : शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर उनके चालक की पत्नी ने डरा धमका कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के आदेश पर रिजवी के खिलाफ सआदतगंज कोतवाली में गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज की गई।

इंस्पेक्टर सआदतगंज ब्रजेश यादव ने बताया कि वसीम रिजवी के चालक की पत्नी ने बीते 22 जून को अधिवक्ताओं के साथ थाने आईं थीं। उन्होंने तहरीर देकर बताया था कि कई साल से उनके पति शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के यहां गाड़ी चला रहे थे। वसीम रिजवी अक्सर यतीमखाने में ही रहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने पति को भी यतीमखाने के पास ही सर्वेंट क्वार्टर दे दिया था। उसके बाद वह भी परिवार के साथ उसी क्वार्टर में रहती है।

तीस घंटे बाद अपहृत चिकित्सक मुक्त, युवती समेत दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा

एत्माद्दौला क्षेत्र से अपहृत वरिष्ठ चिकित्सक उमाकांत गुप्ता को 30 घंटे बाद पुलिस ने धौलपुर क्षेत्र में चंबल के बीहड़ से मुक्त करा लिया। पुलिस का दबाव बढ़ने पर बदमाश डाक्टर को छोड़कर भाग गए थे। वारदात में शामिल युवती और एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। दस्यु केशव गुर्जर के गुर्गे बदन सिंह ने साथियों के साथ पांच करोड़ की फिरौती वसूलने को हनी ट्रैप में फंसाकर इस वारदात को अंजाम दिया था।



अपहृत चिकित्सक उमाकान्त गुप्ता। सौजन्य : स्वजन

ट्रांसयमुना कालोनी फेस-2 निवासी 60 वर्षीय डा. उमाकांत गुप्ता मंगलवार शाम 7.30 बजे घर से निकले थे। रात 11 बजे तक वापस न आने पर स्वजन ने देर रात एत्माद्दौला थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। चिकित्सक के मोबाइल की अंतिम लोकेशन 8.30 बजे सैंया क्षेत्र में मिली। इसके बाद एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद के नेतृत्व में पुलिस टीम धौलपुर पहुंच गई। गुरुवार को प्रेसवार्ता में एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने बताया कि चिकित्सक की बलेनो कार धौलपुर में मिली थी। पुलिस ने निभोरा (आगरा) निवासी पवन को पकड़ा।

पुलिस टीम को दो-दो लाख रुपये का पुरस्कार

चिकित्सक की सकुशल रिहाई पर लखनऊ से पुलिस टीम को बधाई दी गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी मुकुल गोयल ने पुलिस टीम को दो-दो लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

दिल्ली की फ्लाइट से पहले एयर टिकट रद करवा हड़प लिया 13 लाख का रिफंड

जागरण संवाददाता, लुधियाना : दिल्ली के रहने वाले दंपती ने इंटरनेशनल एयर टिकट रद करवाकर लुधियाना की एक फर्म के 13 लाख रुपये रिफंड हड़प लिए। शातिर फ्लाइट से पहले टिकट कैंसल करवाकर रिफंड ले लेते थे। फर्म के मालिक हरमंदर सिंह की शिकायत पर थाना माडल टाउन की पुलिस ने दिल्ली के शकरपुर स्थित पांडव नगर के युवराज बजाज उर्फ राहुल बजाज और पत्नी रितु बजाज के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

जांच अधिकारी एएसआइ भीषम देव ने बताया कि शिकायतकर्ता हरमंदर सिंह माडल टाउन एक्सटेंशन का रहने वाला है। उसने 18 सितंबर 2019 को उसने पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि वह कैरियर कालेज एब्रोड नाम से कारोबार करता है। वर्ष 2017 में वह आरोपित दंपती उसके संपर्क में आया। पेमेंट वह उन्हें बैंक के माध्यम से भेजता था। रितु बजाज स्टेट बैंक आफ इंडिया की कर्मचारी हैं और उसे भी पेमेंट भेजता था।

दैनिक जागरण
प्रेम हर बोझ को हल्का कर देता है

सुप्रीम कोर्ट का सही सवाल

राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सही सवाल किया कि आखिर अंग्रेजों का बनाया हुआ यह कानून आजादी के 75 साल बाद भी क्यों जारी है? इस कानून पर अमल होते रहने पर इसलिए भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अंग्रेज शासकों ने इसे आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था। आखिर ऐसा कानून स्वतंत्र भारत में क्यों अस्तित्व में होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल तिलक और गांधी जैसे नेताओं के खिलाफ किया गया हो? समस्या केवल यह नहीं है कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून अभी भी अमल में लाया जा रहा है, बल्कि यह भी है कि अक्सर इसका इस्तेमाल उन मामलों में किया जाता है, जो मुश्किल से राजद्रोह के दायरे में आते हैं। आखिर किसी मामले में अनुचित बयान देने या फिर आपत्तिजनक लिखने वालों के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई करने का क्या मतलब? ऐसा किया जाना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है। इस पर हैरत नहीं कि जब बेतुके-वाहियात बयान देने वालों पर राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई होती है तो ऐसे ही स्वर सामने आते हैं कि लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है अथवा अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा बैठाया जा रहा है। यह सही है कि लोगों को राजनीतिक-सामाजिक विमर्श में आपत्तिजनक बातें करने से बचना चाहिए, लेकिन यदि कोई संयम-शालीनता का परिचय न दे तो फिर उसके खिलाफ राजद्रोह के तहत कार्रवाई करना ठीक नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ किसी अन्य कानून के तहत कार्रवाई तो समझ आती है, लेकिन उन्हें राजद्रोही करार देने का कोई औचित्य नहीं। कथनी और करनी में अंतर होता है। इस अंतर को समझा जाना चाहिए।

यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट राजद्रोह संबंधी कानून की वैधानिकता परखने जा रहा है। कुछ देर से ही सही, यह काम किया ही जाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि कुछ लोग वास्तव में ऐसे कृत्य करते हैं, जो राजद्रोह के दायरे में आते हैं। ऐसे लोग केवल देश के खिलाफ बोलते-लिखते ही नहीं हैं, बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने वाले काम भी करते हैं। कई बार तो वे कानून एवं व्यवस्था अथवा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं या फिर देश के लिए गंभीर खतरा बने तत्वों की हरसंभव सहायता करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो प्रभावी कार्रवाई होनी ही चाहिए। स्पष्ट है कि वास्तव में राजद्रोही आचरण करने वालों के खिलाफ ठोस कानून की जो आवश्यकता है, वह भारतीय दंड संहिता में होनी ही चाहिए। इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि अंग्रेजों के बनाए ऐसे और कौन से कानून हैं, जिनकी समीक्षा आवश्यक है।

स्कूल खोलना कितना उचित

हरियाणा में विद्यालय खोलने को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दोनों के अपने-अपने तर्क हैं। प्रदेश सरकार कह रही है 16 जुलाई से कक्षा नौ से कक्षा बारह वाले विद्यालय प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन किसी बच्चे का स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। यदि अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय भेजना चाहें तो भेजें, न भेजने चाहें तो न भेजें, जो बच्चे विद्यालय नहीं भी आएंगे, उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। दूसरी तरफ प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा कह रही हैं कि अभी एक भी बच्चे को कोरोना प्रतिरोधक वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसी स्थिति में विद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ होती हैं तो कोरोना संक्रमण एक बार पुनः अपना घातक दुष्प्रभाव दिखा सकता है। यह बात भी तर्कसंगत है। यह भी विचारणीय है कि कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थी सामान्य तौर पर 18 वर्ष से कम वय के होते हैं और अभी उन्हें वैक्सीन लगाई ही नहीं जा रही है।

हरियाणा सरकार कक्षा नौ से बारह तक के विद्यालयों में कक्षाएं आरंभ कर रही है तो विपक्ष इसके विरोध में है

18 से अधिक वय वालों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। बच्चों को जो वैक्सीन दी जानी है, उस पर अभी काम चल रहा है। स्पष्ट है कि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन बन नहीं जाती है, उनका वैक्सीनेशन संभव नहीं है। इसलिए यदि वे विद्यालयों में जाते हैं तो उनके बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि छह फीट की शारीरिक दूरी बनी रहे। वे मास्क लगाकर विद्यालय जाएं और हर घंटे उनके हाथ धोने की व्यवस्था हो। उनकी-कुर्सी मेज सुबह शाम सैनिटाइज की जाए। क्या यह संभव हो पाएगा? शायद नहीं। शारीरिक दूरी बनाकर उनके बैठने की व्यवस्था तो कदापि नहीं, क्योंकि विद्यालयों के कक्ष इतने बड़े हैं ही नहीं। रही बात मास्क और सैनिटाइजेशन की तो जब वयस्क इसका ध्यान नहीं रख पा रहे तो बच्चों से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है? सरकार भी इसे समझती है, इसीलिए उसने बच्चों को विद्यालय भेजने की बात अभिभावकों की इच्छा पर डाल दी है, लेकिन अच्छा तो यह होगा कि जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन न हो जाए, आनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था जारी रखी जाए।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों की एकल प्रवेश परीक्षा



प्रो. निरंजन कुमार

इस साल बारहवीं की परीक्षाओं के रद होने पर सीयूसीईटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत और भी बढ़ गई है

एक अर्से से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मुद्दा चर्चा में है। समझा जा रहा है कि अकादमिक वर्ष 2021-22 में देश के सभी 49 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीयूसीईटी) कराया जाएगा, पर कोरोना संकट के कारण स्थिति अभी अस्पष्ट है। हालांकि सीयूसीईटी को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। वैसे विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत वर्ष 2010 में ही हो गई थी। पिछले वर्ष भी 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और चार राज्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश इसी तरीके से हुआ था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने की अनुशंसा है। सीयूसीईटी के पीछे अवधारणा यह है कि विद्यार्थियों को अलग-अलग परीक्षाओं के जंजाल से मुक्ति दिलाई जाए। याद कीजिए, किसी समय मेडिकल-इंजीनियरिंग की कितने तरह की प्रवेश-परीक्षाएं होती थीं। परीक्षा देते-देते छात्र पस्त हो जाते थे। कई बार तो विभिन्न संस्थानों की परीक्षाओं की तिथियों में टकराव हो जाता था और छात्रों के सामने किसी परीक्षा को छोड़ने की नौबत आ जाती थी। इसीलिए भारत सरकार ने पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग सहित 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में भी विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट शुरू करा दिया। फिर बीए, बीएससी और बीकॉम आदि स्नातक या विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्रों को इतने सारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के जंजाल से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया। उसने जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय समेत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल प्रवेश परीक्षा की अनुशंसा की।

सीयूसीईटी का मुख्य विरोध वैचारिक कारणों से है। चूंकि मोदी सरकार छात्रहित में सीयूसीईटी को विस्तार देना चाहती है तो मोदी विरोध की मानसिकता सीयूसीईटी के विरोध में परिणत हो जाती है। याद रहे कि मनमोहन सरकार के समय भी उनके प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार सीएनआर राव ने अनेक परीक्षाओं के तनाव एवं बोझ से लदे विद्यार्थियों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने उच्च शिक्षा में प्रगति के लिए मनमोहन सिंह को सौंपी-अनिवार्य कदमः एक सूची' नामक रिपोर्ट में उच्च शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में अमेरिकी मॉडल जैसी एक राष्ट्रीय परीक्षा कराने पर जोर दिया था।

निःसंदेह उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में एकल प्रवेश परीक्षा अत्यावश्यक है। इससे छात्रों को अनेक परीक्षाओं से मुक्ति और एक ही परीक्षा से अनेक विश्वविद्यालयों में प्रवेश का विकल्प मिल सकेगा। सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। इसी तरह देश के दूर-दराज इलाकों जैसे पूर्वोत्तर या सुदूर दक्षिण के छात्र कई परेशानियों से बच जाएंगे। एकल प्रवेश परीक्षा लड़कियों के मामले में तो और भी उपयोगी साबित होगी। 12वीं के अंकों के बजाय एकल प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश इसलिए भी उचित है कि देश में सीबीएसई बोर्ड के अतिरिक्त सीआइएससीई बोर्ड और विभिन्न राज्यों के अपने-अपने बोर्ड हैं। सभी बोर्डों में अंक देने की अलग-अलग प्रणाली है। ऐसे में 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश देने से उन राज्यों के अनेक प्रतिभाशाली छात्र प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं, जहां अपेक्षाकृत कम अंक मिलते हैं अथवा बहुत कम छात्रों को 90 प्रतिशत अंक मिलते हैं। यह न केवल उन छात्रों के साथ अन्याय है, बल्कि इससे समाज-राष्ट्र की भी हानि होती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में उल्लिखित समानता के अधिकारों का भी हनन है। इस साल 12वीं की परीक्षाओं के रद होने पर सीयूसीईटी की जरूरत और भी बढ़ गई है। लगभग सभी बोर्डों ने अंक आवंटित करने के लिए अपना एक फॉर्मूला जारी किया है, जिससे अंकों में एक समतुल्यता नहीं होगी। यह एक ऐसा तथ्य है, जिससे सभी अवगत हैं।



अवधेश राजपूत

अलग-अलग परीक्षा की जगह सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एकल परीक्षा होने से संसाधनों की बचत भी होगी। हर विश्वविद्यालय इतना साधन संपन्न और सक्षम नहीं कि वह पूरे देश में पर्याप्त केंद्रों पर परीक्षा ले सके। कई विश्वविद्यालयों के परीक्षा केंद्र एक दर्जन शहरों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। इससे छात्रों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों को भी हानि होती है। वे पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को आकर्षित नहीं कर पाते। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ही एक विरला विश्वविद्यालय है, जिसकी सवा सौ शहरों में प्रवेश-परीक्षा होती है। जेएनयू की गुणवत्ता का एक प्रमुख कारण है, पूरे देश के प्रतिभाशाली छात्रों का वहां आगमन।

सीयूसीईटी के खिलाफ एक अन्य तर्क है कि इससे स्ट्रीम बदलना मुमकिन नहीं। बारहवीं में विज्ञान पढ़ने वाला, स्नातक स्तर पर कला-मानविकी पढ़ना चाहे तो संभव नहीं होगा, लेकिन इस समस्या का समाधान कठिन नहीं। विज्ञान-विषय से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो छात्र मानविकी-समाज विज्ञान पढ़ना चाहें, उनके डेढ़-दो प्रतिशत अंक कमकर उनकी मेरिट मानविकी-समाज विज्ञान के लिए बनाई जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी यह व्यवस्था लागू है। विरोधियों का एक अन्य तर्क है कि सीयूसीईटी से कोचिंग वाले छात्रों का दबदबा होगा, कमजोर वर्ग अथवा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र कोचिंग के अभाव में पिछड़ जाएंगे। इस समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी के जमाने में कठिन नहीं। एकल प्रवेश परीक्षा से करोड़ों रुपये की जो बचत होगी, उसके कुछ हिस्से से ही एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ-साथ लड़कियों और अन्य वंचित वर्ग के लिए तीन-चार महीने की गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कोचिंग ऑनलाइन तरीके से दी जाए। कोई छात्र किसी कारणवश परीक्षा देने से वंचित न रह जाए, इसके लिए जेईई और नीट की ही तरह सीयूसीईटी भी तीन से चार बार कराई जाए।

कोरोना काल में अगर जेईई और नीट की परीक्षा हो सकती है तो सीयूसीईटी क्यों नहीं? नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अपील है कि शिक्षा संबंधित किसी भी नीतिगत निर्णय में तीन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए-राष्ट्र-समाज हित, व्यक्ति अर्थात छात्र-हित और ज्ञान का हित। सीयूसीईटी राष्ट्र, छात्र और ज्ञान, तीनों के ही हित में है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

सबके हित में है समान नागरिक संहिता



प्रो. हरवंश दीक्षित

कम से कम अब तो हमारे नीति-नियंताओं को शाहबानो प्रकरण के दु:स्वप्न से उबर ही जाना चाहिए

अदालत ने एक बार फिर सरकार से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का आग्रह किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे मौजूदा वक्त की जरूरत बताया है, ताकि हमारा समाज और अधिक समरस हो सके और उसमें एकजुटता बढ़ सके। संविधान का अनुच्छेद 44 सबसे अधिक दुष्प्रचारित हिस्सों में से एक है। इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसमें देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई है। सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह पंथ, क्षेत्र, भाषा आदि बंटवारा करने वाले आधारों की परवाह किए बगैर सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए। ऐसी व्यवस्था बनाए, जो मानवीय गरिमा का सम्मान करती हो, उसे सुरक्षा बोध दे और सभ्य समाज के मानकों पर खरी उतरे।

दुर्भाग्यवश अनुच्छेद 44 की इस पवित्र मंशा को आगे बढ़ाने के बजाय हमने अपनी फितरत के मुताबिक एक हौवा खड़ा कर दिया। उस पर तार्किक बहस करने के बजाय उसे सांप्रदायिक रूप देकर अछूत बना दिया। सुप्रीम कोर्ट का आग्रह बेकार गया। इस मामले में तो हम लोकशाही की महान परंपराओं से भी मुंह चुराने लगते हैं। इस विषय पर स्वस्थ बहस करने के बजाय इसके प्रस्तावकों की लानत-मलानत करने लगते हैं और उसे तब तक जारी रखते हैं जब तक सामने वाला थक हार कर बैठ न जाए।

संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि विवाह और भरण पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी उपासना पद्धति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध इंसानियत से है। निःसंतान व्यक्ति यदि किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है या उससे उसे सुरक्षा बोध का अहसास होता है तो आखिर इससे किसी उपासना पद्धति की अवमानना कैसे हो सकती है? यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने के बाद उसे दरबदर भटकने के बजाय गुजारे-भत्ते की व्यवस्था की जाती है तो इसमें मजहब कहां से आड़े आता है? महिला-पुरुष के वैवाहिक संबंधों में यदि समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदगी नहीं, अपितु गर्व होना चाहिए।

आजादी के बाद हिंदू विधि में व्यापक परिवर्तन किए गए। पहले, पुरुष एक से अधिक शादियां कर सकता था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पति-पत्नी को विवाह विच्छेद करके सम्मानपूर्वक एक-दूसरे से अलग रहने का अधिकार दिया गया। महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें भरण पोषण का अधिकार दिया गया। पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार देने की परंपरा की शुरुआत हुई। संतान को गोद लेने के मामलों में भी पति के एकाधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। हिंदू कानून में किए गए सुधारों में पारंपरिक विधि की जगह मानवाधिकारों और समानता के सिद्धांतों को तरजीह दी गई, पर वोट बैंक खिसकने के स्वार्थी सोच के कारण दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं हो सका। उन्हें बेहतर होने के मौके से लगातार वंचित रखा गया। संविधान का अनुच्छेद 44 और अदालतों के कई निर्देश भी इस सोच पर बेअसर रहे।



दिल्ली हाई कोर्ट ने भी समान संहिता की पैरवी की है। फाइल

आधुनिक सोच का लाभ केवल हिंदुओं तक ही सीमित न रहे और वह दूसरे मतावलंबियों को भी हासिल हो, इसके लिए अदालतें लगातार कोशिश करती रही हैं। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो (1985) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि यह अत्यंत खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में तय की गई राज्य की जिम्मेदारी अब निर्जीव शब्द समूहों का संग्रह मात्र बनकर रह गई है। सरकारी उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा था कि मुस्लिम समाज को इस मामले में पहल करने की जरूरत है, ताकि प्रगति की दौड़ में वे दूसरों से पीछे न रहें। हैरानी की बात यह है कि शाहबानो के जिस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से इस दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया, उसके दुष्प्रचार ने सबसे अधिक चोट समान नागरिक संहिता की पहल को पहुंचाई।

शाहबानो प्रकरण के बाद सरला मुदगल (1995) तथा लिली थामस (2000) जैसे कई प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक कानून के नहीं होने के दोषों को उजागर करते हुए इसका तुरंत क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। वैवाहिक मामलों में वैयक्तिक विधि के दुरुपयोग से विचलित होकर अदालत ने कहा कि अब तो इसका दुरुपयोग कानून को धोखा देने के लिए होने लगा है। जब वैवाहिक साथी से छुटकारा पाना हो तो कुछ समय के लिए अपना मजहब बदलकर दूसरी शादी कर ली, क्योंकि दूसरे मजहब से जुड़े कानून में उसे मान्यता दी गई है। उसके बाद अपनी मर्जी से तलाक देकर उस महिला से छुटकारा पा लिया, क्योंकि उस मजहब का कानून इसकी इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट और दूसरे विद्वानों ने इस कमी की ओर बार-बार इशारा किया, लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ढाक के वही तीन पात रहे, क्योंकि वे शाहबानो प्रकरण से सहमे हुए थे। इसके पहले अन्य विद्वानों ने भी इसकी वकालत की है। न्यायमूर्ति मुहम्मद करीम छागला ने मोतीलाल नेहरू व्याख्यानमाला में, प्रोफेसर ताहिर महमूद ने अपनी पुस्तक 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' (1977) में तथा न्यायमूर्ति एमयू बेग ने 'इंपैक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म' (1973) में भी संविधान के अनुच्छेद 44 को अमली जामा पहनाने का आह्वान किया, किंतु शाहबानो प्रकरण के दुःस्वप्न से अभी भी कोई उबरने को तैयार नहीं है। समाज के व्यापक हितों के मद्देनजर पंथनिरपेक्ष हितचिंतकों को आगे बढ़कर इस दिशा में पहल करने जरूरत है, ताकि हम एक प्रगतिशील समाज के रूप में एकजुट हो सकें।

(लेखक विधि मामलों के जानकार एंव उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समय बोध

कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय है, अमुक कार्य भविष्य में कभी कर लेंगे। इसी भ्रांति में जीते अनेक मनचाहे कार्य लटक जाते हैं और बुढ़ापा पसर जाता है। अबूझ अस्मिता है समय। किसी का कटता नहीं, किसी के पास होता नहीं। जीवन में जो चाहा, जैसा चाहा, वह मिला या नहीं, इस पर निर्भर है कि क्या खाने, सोने, दैनंदिन आवश्यक कार्य निपटाने से इतर आपका कोई बड़ा लक्ष्य है? यदि हां तो क्या उसे पाने के लिए आपने आवश्यक समय दिया?

जब तक जीवन है, विघ्नकारी व्यक्तियों और परिस्थितियों से आमना-सामना भी होता रहेगा। कटु क्षणों को चित्त में धारण करेंगे तो समय बोझिल होकर वर्तमान के सुख-चैन हर लेगा। जिन अप्रिय प्रसंगों पर आपका नियंत्रण नहीं उनमें उलझ कर समय नष्ट करेंगे तो प्राकृतिक सहजता खो बैठेंगे। कुछ अभिनव, सार्थक करने का उत्साह नहीं जुटा पाएंगे। आप उदासीन, निराश रहने लगेंगे। आप अलग-थलग पड़ जाएंगे। समय की गति को रोकना या शिथिल करना मनुष्य के वश में नहीं है। जीवनयात्रा के दुष्कर क्षणों को अपरिहार्य मानते हुए, जो भी वर्तमान में बेहतर उपलब्ध है उसमें रस लेने, सहेजने में समय लगाएं। कालचक्र एक ही स्थिति में नहीं रहता, सरकते रहना इसकी नियति है। वह समय न रहा तो यह भी नहीं रहेगा। हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं है, अतीत की अरुचिकर परिस्थितियों की चिंता या उनके विश्लेषण में समय न गंवाएं। प्रसन्नचित्त रहने का अभ्यास निरंतर करते रहें। खिला मुस्कुराता चेहरा किसी के हृदय तक पहुंचने का अचूक साधन है।

समय के प्रति सजग प्रबुद्ध व्यक्तियों ने इसको नष्ट नहीं होने दिया। ऊंचाइयों तक वही पहुंचे जिन्होंने समय का सदुपयोग अपने कौशल तराशने में किया। निर्णय आपको लेना है। समय की आंधी में गुम हो जाएं या ऐसे कार्य करें जिनके सुखद प्रतिफल स्वयं को और भावी पीढ़ी को मिलें।

हरीश बड़थ्वाल

बेहतर होंगे आधी आबादी के हालात

डा. मोनिका शर्मा

जनसंख्या वृद्धि से जुड़े सभी पहलू महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण से भी जुड़े हुए हैं

आबादी पर नियंत्रण का कदम संसाधनों पर बढ़ते दबाव को कम करने के साथ ही पोषण एवं स्वास्थ्य के मामले में सामाजिक-पारिवारिक जीवन की खुशहाली से भी जुड़ा है। विशेषकर यह स्त्रियों के लिए सेहत सहेजने और स्तरीय जीवन की बुनियाद बनाने वाला है। दरअसल जनसंख्या वृद्धि से जुड़े सभी पहलू महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण से भी जुड़े हैं। ऐसे में जिस देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, वहां औरतों के हालात परेशानियों से भरे होते हैं। महिलाएं स्वास्थ्य खोने से लेकर प्रसव की जटिलताओं में जान गंवाने तक हर मोर्चे पर बार-बार मां बनने के जोखिम को झेलती हैं। आज संसार भर में बढ़ती आबादी को मानवाधिकारों से जुड़ा विषय समझा जा रहा है, क्योंकि अनगिनत लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों के बिना जीवनयापन करने की स्थितियां बनी हुई हैं।

जनसंख्या वृद्धि से भविष्य में परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों की शिक्षा और सेहत भी प्रभावित होती हैं। गांव हो या शहर, ज्यादा बच्चों की देखभाल के दबाव में अपनी काबिलियत और क्षमता के मुताबिक काम कर रहीं महिलाओं का काम छूट जाता है। अधिकतर कमजोर तबके से आने वाले बड़े परिवारों के आर्थिक हालात और बिगड़ जाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी आधारभूत सुविधाएं भी न जुटा पाने वाले घरों में बच्चों की संख्या का बढ़ना, शिशु मृत्यु दर, बच्चों की असुरक्षा और कुपोषण जैसी बातें औरतों को भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी पीड़ा पहुंचाती हैं। दूर दराज के इलाकों में तो सेहतमंद और सुरक्षित मातृत्व के लिए गर्भावस्था में सही संभाल और प्रसव के बाद उचित देखभाल से जुड़ी सजगता और समझ की स्थितियां आज भी नहीं बन पाई हैं। नतीजतन गर्भावस्था के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं संक्रमण, बाधित प्रसव, एनीमिया, आयोडीन की कमी और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं का शिकार होती हैं। गरीब परिवारों के पास तो स्वास्थ्य केंद्रों तक सकुशल पहुंचने की सुविधा तक नहीं होती। ऐसे में बार-बार प्रसव की जटिलताओं का सामना करने की बात हो या जच्चा-बच्चा के उचित पोषण और देखभाल की कमी, महिलाएं अपना स्वास्थ्य खो रही हैं और बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं।

कुछ समय पहले आई राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि पांच वर्ष तक के 35 फीसद बच्चे नाटे कद के हैं, 17 फीसद कमजोर हैं, 33 फीसद का वजन कम है और 11 फीसद भयंकर कुपोषित हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक गर्भवती महिलाओं के खान-पान और सेहत की खैरियत से जुड़े सभी कारक मां और बच्चे दोनों की सेहत पर भी असर डालते हैं। यकीनन शिक्षा, जागरूकता और परिवार नियोजन के बिंदुओं पर सही ढंग से काम किया जाए तो आबादी कम होगी और स्त्रियां स्वस्थ एवं सशक्त बनेंगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खोजने होंगे स्थायी समाधान

'सुधार की मांग करती शिक्षा-परीक्षा' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में तरुण गुप्त ने बच्चों के भविष्य को लेकर जो चिंता व्यक्त की है वह न्यायोचित है। पिछले डेढ़ साल से देश में प्राथमिक और उच्च शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने का काम करती हैं। दुख की बात है कि कोरोना की भयावहता के कारण इन कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे बिना कुछ ज्ञान हासिल किए प्रमोट किए जा रहे हैं, जिसके दुष्प्रभाव हमें आगामी वर्षों में देखने को मिल सकते हैं। कहने को तो स्कूल आनलाइन क्लासेज लेकर बच्चों का कोर्स पूरा करा रहे हैं, लेकिन उनको न तो मौलिक अनुभव मिल पा रहा है और न ही अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर। ऐसे में उन अभिभावकों की चिंता भी स्वाभाविक है, जो अपने बच्चों को आनलाइन प्लेटफार्म और अन्य माध्यमों से पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन परिणाम मनमुताबिक नहीं मिल पा रहा। कोरोना महामारी के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है और बच्चों की शिक्षा को प्रभावित होने से बचाने की तरकीब किसी को नहीं सूझ रही है। अब जब कोरोना हमारे परिवेश में लंबे समय तक टिकने वाला है तो हम ऐसे ही हाथ में हाथ रखे और कोरोना के जाने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वैक्सीन लगने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना फिर दोबारा नहीं आएगा। ऐसे में सरकार और शिक्षाविदों को बच्चों के भविष्य को लेकर ठोस और दूरगामी योजना बनानी चाहिए जिससे ग्रामीण इलाकों और औसत दर्जे के छात्रों के हितों को भी साधा जा सके। यदि महामारी के दौरान सिर्फ आनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है तो इसे प्रभावशाली और सर्वसुलभ बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह केवल स्कूलों के फीस लेने का जरिया बनकर न रह जाए। मौजूदा हालात में अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले छात्रों को सरकार से भरोसा मिलना चाहिए कि उनकी प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। सरकार को सक्रियता से प्रभावी नीतियां बनाकर उन्हें धरातल पर उतारना होगा तभी हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे।

शिवम सिंह, बबेरू, बांदा

मेलबाक्स

तालिबान की दकियानूसी सोच

अमेरिकी फौज के हटते ही अफगानिस्तान में पुनः तालिबान की ताकत बढ़ गई है। तालिबानी लड़ाकों ने यहां पर 142 से ज्यादा जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है। जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी यहां की महिलाओं को हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबानियों की दकियानूसी सोच की वजह से महिलाओं को नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। ना तो लड़कियों को स्कूल जाने का अधिकार है और ना ही सार्वजनिक जगहों पर जाने की आजादी। अफगानिस्तान जैसे देशों में महिलाएं नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दुनिया के अन्य देशों सहित मानव अधिकार आयोग जैसी तमाम संस्थाओं को तालिबानी संगठनों पर शिकंजा कस कर महिलाओं को आजाद कराने के प्रयास करने चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला गांव

जान से न हो खिलवाड़

यह पत्र संपादकीय पेज पर प्रकाशित लेख कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के संदर्भ में है। उत्तराखंड सरकार ने पहले चार धाम यात्रा रद की और अब कांवड़ यात्रा को भी रद कर दिया है। सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा में लाखों लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से उत्तराखंड पहुंचते हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी कांवड़ यात्रा तुरंत रद कर देनी चाहिए। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम की दिशा में अच्छा काम किया हो, लेकिन किसी भी हाल में तीसरी लहर को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़मुक्तेश्वर में कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की है, लेकिन लाखों लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराना मुश्किल है। सरकार को लोगों की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि स्वास्थ्य को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद कर दिए जाएं।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए [illegible] द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

106 किलोमीटर लंबी है जम्मू कश्मीर की अफगानिस्तान के साथ सटी अंतरराष्ट्रीय भौगोलिक सीमा। लिहाजा भारत के लिए अफगानिस्तान की महत्ता काफी बढ़ जाती है।

आजकल



विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की चिंताएं

अमेरिका द्वारा अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से निकालने के निर्णय के बाद तालिबान ने जिस तरह वहां प्रांतों और जिलों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया है, उससे महाशक्तियों के साथ ही क्षेत्रीय शक्तियों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। तालिबानी अफगानिस्तान में इस्लामिक जिहाद, गृह युद्ध, क्षेत्रीय अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए भारत ने अपने 50 राजनयिकों को वहां से बाहर निकाल लिया है। तालिबान चाहता है कि अफगान सुरक्षाकर्मी उसकी समक्ष पूरी तरह से आत्मसमर्पण करें। कुल मिलाकर एशिया में एक व्यापक क्षेत्र के सामने यह एक नई चुनौती उभरकर सामने आई है



लगभग दो दशकों के बाद अफगानिस्तान में एक बार फिर बढ़ रहा तालिबान का वर्चस्व। इंटरनेट मीडिया

एक ऐसे समय में जब तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के भूक्षेत्र के 85 प्रतिशत हिस्से पर अपने नियंत्रण का दावा किया जा रहा है, तब यह बात साफ हो गई है कि तालिबान जल्द से जल्द अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन तंत्र की स्थापना के लिए आमादा है। ऐसे में भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। भारतीय नेतृत्व को दिख रहा है कि एक नॉन स्टेट एक्टर (आतंकी संगठन) स्टेट एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। तालिबान चाहता है कि वह अफगानिस्तान में 1996 से 2001 के दौर जैसा ही शासन करे और उसे दुनिया के देशों से अंतरराष्ट्रीय मान्यता और पहचान मिले ताकि वह अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार और उसके सैनिकों को एक झटके में उखाड़ फेंक अपने हिसाब से वहां का शासन चलाए। लेकिन भारत ने हाल ही में दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के कांटैक्ट ग्रुप की बैठक में तालिबान पर अपना मत स्पष्ट किया है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा है कि भारत सहित दुनिया भर के देश हिंसा और बल प्रयोग के आधार पर किसी के द्वारा सत्ता पर कब्जे के विरुद्ध हैं और ऐसी गतिविधियां वैध नहीं हैं।

भारत ने दुशांबे में एससीओ की मीटिंग में इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि काबुल के पड़ोसी आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खतरे का सामना न करें। भारत का पक्ष अभी भी यही है कि एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकीकृत, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान का निर्माण प्राथमिकता के तौर पर होना चाहिए। जिस तरह से पिछले कुछ माह में तालिबान की आक्रामकता अपने इस्लामिक एजेंडे को लेकर बढ़ी है, उससे भारत समेत दुनिया के कई देश चिंतित हो गए हैं। जो भी देश तालिबान के मंसूबों से आशंकाओं से भर उठे हैं, उन्हें ईरान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तालिबान के नियंत्रण क्षेत्रों से चिंता महसूस हो रही है। तालिबान ने ईरान और अफगानिस्तान बार्डर पर इस्लाम कलां हो या तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित तोरघुंडी जिला हो, अफगानिस्तान का ताखर या हेरात हो, सभी को अपने कब्जे में कर लिया है। इस्लाम कलां सीमा चौकी ईरान और अफगानिस्तान के बीच होने वाले व्यापार का केंद्र भी है। यहां से अफगान सरकार को हर माह लगभग दो करोड़ डॉलर का राजस्व मिलता है, तोरघुंडी भी इसी तरह तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार की अहम कड़ी है। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्व में स्थित है। इस इलाके में भी तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है।

तालिबान जिस तरह मध्य एशिया के देशों और ईरान के सीमा शहरों को कब्जे में ले रहा है, वह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। बात चाहे चाबहार बंदरगाह, तापी गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट की सुरक्षा की हो या फिर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे के निर्माण की, अगर तालिबान ने भारत, ईरान, अफगानिस्तान को क्षेत्रीय स्थिरता नहीं दी तो समस्या बढ़ जाएगी। तालिबान के बढ़ते प्रभाव से हिंदू अल्पसंख्यकों, भारतीय नागरिकों, बौद्धों, हजारा शियाओं पर हमले बढ़ जाएंगे।

यहां अहम सवाल यह खड़ा होता है कि भारत ने जिस अफगान सुरक्षा बल को लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया, उसका आधुनिकीकरण किया, उसे वायु सुरक्षा प्रणाली दी, क्या वह अफगान सैन्य बल तालिबान से निपटने में सक्षम है या नहीं। तालिबान ने हाल ही में अफगान सुरक्षा बलों को अपने सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कह दिया और सूचना यह भी आई कि आत्मसमर्पण के बाद कई अफगान सैनिकों को तालिबान द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है। यह कितनी विडंबनापूर्ण बात है कि किसी देश का एक वर्ग अपने ही नागरिकों के सफाए पर तुला है।

तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने की स्थिति में एक बात तो तय है कि वैश्विक आतंकवाद से निपटने में देशों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तालिबान वैश्विक शांति के लिए खतरा इसलिए बनता रहेगा, क्योंकि जब जब अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक, आधुनिक अधिकारों वाला, महिला सशक्तीकरण वाला सभ्य देश बनाने का प्रयास पश्चिमी देशों द्वारा किया जाएगा और जैसे ही ये इस्लामिक मूल्यों के खिलाफ पाया जाएगा, तब तब यह बात तालिबान को सहन नहीं होगी।

वहीं इन सभी घटनाक्रमों में चीन की बात करें तो चीन की चिंता अपने मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत को लेकर है। इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। चीन को अंदेशा है कि काबुल की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद मुस्लिम चरमपंथी वाखान गलियारे से होते हुए शिनजियांग में घुसपैठ कर सकते हैं। लिहाजा चीन की दिलचस्पी अब अफगानिस्तान में स्थिरता लाने और शासन करने में है।

अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी रहे हैं कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के साथ जंग लड़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान समेत तमाम आतंकी संगठनों के लड़ाके भी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन में देखे गए हैं। यहां इस भौगोलिक सच्चाई का भी ध्यान रखना भारतीय नेतृत्व के लिए अधिक जरूरी हो गया है कि जम्मू कश्मीर की अफगानिस्तान के साथ 106 किमी लंबी सीमा लगती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान की भू-सामरिक स्थिति भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही इसके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का वाखन गलियारा है जिसमें चीन इस समय काफी रुचि ले रहा है। चीन, तालिबान और पाकिस्तानी आतंकियों के भारत विरोध के नाम पर यहां किसी गठजोड़ की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिये अनुच्छेद 370 के समापन को अंजाम दिया और अपने नए नक्शे में मीरपुर और मुजफ्फराबाद जैसे क्षेत्रों को भारत की भू-सीमा में दर्शाया है, वह बात चीन, पाकिस्तान और तालिबान सहित आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देशों को नागवार गुजरी है। ऐसे में तालिबान पाकिस्तान के साथ एक एकीकृत इस्लामिक एजेंडे के साथ कश्मीर में अशांति पैदा करने का प्रयास करेगा, लिहाजा भारत को सतर्क रहना होगा।

इस्लामिक शासन स्थापना की वैधता का सवाल

भारत ने कुछ समय पहले अफगानिस्तान के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जेरांज डेलारम राजमार्ग निर्माण में सहयोग दिया था, जिसे ईरान के चाबहार बंदरगाह मिलाक मार्ग से जोड़ दिया गया था। चाबहार मिलाक जेरांज डेलारम राजमार्ग अफगान कृषि उत्पादों और अन्य निर्यातों के लिए भारतीय बाजार को खोल देगा। इन सब मार्गों, राजमार्गों की सुरक्षा की चिंता स्वाभाविक है। देखना यह होगा कि भारत ने अफगानिस्तान के जिस गारलैंड हाइवे के विकास में योगदान दिया और जो अफगानिस्तान के सभी शहरों से जुड़ा है, अगर उस पर तालिबान का नियंत्रण होता है, उसके झंडे वहां फहराए पाए जाते हैं तो इसका भारत और ईरान के अफगानिस्तान के साथ व्यापार वाणिज्य पर क्या असर पड़ता है।

क्या तालिबान तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को लिंक करने हेतु विचार किए गए 'एशियन इंटरनेशनल रेलवे कारिडोर प्रोजेक्ट' को अबाधित रूप से चलने देगा। जिज्ञासा इस बात की भी उत्पन्न होती है कि जिस हेरात प्रांत के पांच जिलों पर तालिबान कथित रूप से कब्जा कर चुका है, क्या वह मजारे शरीफ-हेरात रेलवे लिंक का निर्माण होने देगा। भविष्य के गर्भ में यह भी छिपा है कि तालिबान को 'हार्ट आफ एशिया कान्फ्रेंस' की उन वार्ताओं में कितनी दिलचस्पी होगी जिनमें अफगानिस्तान के विकास के लिए, क्षेत्रीय एकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क दिए जाते रहे हैं।

आशंका इस बात की भी है कि तालिबान के मजबूत होने के बाद इस्लामी चरमपंथी काकेसस क्षेत्र और रूस के चेचन्या प्रांत तक फैल जाएंगे। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री ने हाल ही में रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और दोनों ने सामूहिक स्तर पर कहा है कि तालिबान को क्षेत्रीय स्थिरता और अफगान शांति सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में उन सभी क्षेत्रीय शक्तियों से कूटनीतिक स्तर पर मिलकर उनसे वार्ता में लगें हैं जिनकी सुरक्षा व्यवस्था पर तालिबान प्रभाव डाल सकता है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ मुलाकात की है। भारतीय विदेश मंत्री ने तेहरान में नव-निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात कर उन्हें अफगानिस्तान तालिबान मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया। ठीक इसी समय तेहरान में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां मौजूद था। लेकिन भारत ने ईरान से द्विपक्षीय स्तर पर ही वार्ता की थी। शिया बहुल ईरान ने वैसे तो कभी तालिबान का खुला समर्थन नहीं किया है, लेकिन उसने कभी-कभी सुन्नी चरमपंथी संगठन तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता की मेजबानी की है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान पूरे अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन की स्थापना के लिए एक के बाद एक जिलों को अपने नियंत्रण में लेता जा रहा है, वहीं अपने इस्लामिक शासन की स्थापना की वैधता के लिए तालिबान के प्रतिनिधि कुछ प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ वार्ता भी कर रहे हैं। हालांकि अब पहले वाला तालिबान नहीं रह गया है, अपने प्रभाव क्षेत्र और इस्लामिक गौरव की पुनः बहाली के लिए वह हठधर्मिता छोड़कर सक्रिय हुआ है। पहले तालिबान वार्ता नहीं करता था, उसे अपनी हिंसक गतिविधियों और ट्रांस इस्लामिक टेरर नेटवर्क के साथ गठजोड़ पर काफी भरोसा था, लेकिन जिस तरह से पिछले दो दशकों में दुनिया के प्रभावशाली देश और संगठन आतंकवाद निरोध के मुद्दे पर लामबंद हुए हैं, उससे तालिबान ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है।

खरी-खरी

प्रश्न के सामने उत्तर निरुत्तर है

डॉ. तीरथ सिंह खरबंदा

परीक्षा चाहे जो हो, सामान्यतः सभी लोग पहले सरल प्रश्न ही हल करना चाहते हैं। निकट भविष्य में हो सकता है कि परीक्षा का पैटर्न ही बदल दिया जाए तथा कठिन प्रश्न को सबसे पहले हल करना अनिवार्य कर दिया जाए। ऐसा करने के चक्कर में तब यह भी हो सकता है कि कइयों के परीक्षा परिणाम ही बिगड़ जाएं।

अक्सर प्रश्नों से कन्नी काटने वाले दूसरों से कठिन प्रश्न को पहले हल करने की उम्मीद करते हैं, किंतु जब उनसे प्रश्न पूछा जाए तो वे प्रश्न पूछने वाले की ही खबर लेने पर उतर आते हैं। वैसे भी आजकल प्रश्न मुखर हैं। लोकहित के हर प्रश्न के सामने उत्तर आज हाथ बांधे, मुंह में दही जमाए, निरुत्तर खड़ा है। कुछ लोग अपने आप में ही कठिन प्रश्न होते हैं, जिन्हें हल करते-करते आप प्रश्न में ही उलझ कर रह जाते हैं। वे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उस एक प्रश्न पर ही कई प्रश्न खड़े कर स्वयं उत्तर देने से बड़ी कुशलता से बच निकलते हैं। प्रजातंत्र के प्रश्न पर अक्सर वे बचकर निकलते रहे हैं। आजकल सबसे पहले प्रश्न की कमजोर नस को खोज निकाला जाता है और फिर मौका मिलते ही उसे दबाकर प्रश्न का स्थायी हल ढूंढा जाता है। यह सब अनेक क्षेत्रों में हो रहा है।

बहुधा ऐसे लोग गले पड़े प्रश्न को गले से पकड़ते हैं और फिर उसके गले पूरा उत्तर उतारकर ही उसे छोड़ते हैं। कुछ प्रश्नों के पीछे उत्तर दौड़ा दिए जाते हैं और दौड़ा-दौड़ा कर प्रश्नों को ही बुरी तरह थका दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई तो समय के साथ अपनी स्वाभाविक मौत मारे जाते हैं। कई मुश्किल प्रश्न ठीक-ठाक उत्तर का इंतजार करते सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं।

ढेर सारे सुविधाजनक प्रश्न आज भी मुंह में लॉलीपॉप चूसते सुविधा के पालने में झूलते नजर आते हैं या फिर कुर्सियों पर चढ़े, तने बैठे दिखाई देते हैं। जब-जब कोई जायज प्रश्न अकाल मौत मरता है, तो उसमें से कई प्रश्न एक साथ जन्म लेते हैं। इन सब बातों से बेखबर अक्सर वे हाथ-धोकर प्रश्न के पीछे पड़ जाते हैं। अकस्मात एक दिन वह आ पहुंचता है, जब वे चारों ओर से स्वयं को प्रश्नों से घिरा पाते हैं।

ट्वीट-ट्वीट

उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रोक दी गई है और मेरे विचार से उत्तर प्रदेश में भी यही करने की जरूरत है। दोनों ही राज्यों में तो भाजपा की ही सरकार है। इसमें प्रधानमंत्री को दखल देने की दरकार है।
अभिज्ञान प्रकाश@Abhigyan_AP

टीकाकरण के मोर्चे पर चौड़ी होती खाई विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए खतरा है। वैक्सीन ही इस संकट से निपटने का इकलौता विकल्प है। ये सभी को उपलब्ध होनी चाहिए और वह भी किफायती दरों पर। एकजुट होकर ही हम इस महामारी को खत्म कर सकते हैं।
एंतोनियो गुतेरस@antonioguterres

क्यूबा को पूंजीवादी देशों द्वारा विकसित वैक्सीन भी चाहिए और साथ ही साथ उसे मुक्त बाजार की लानत-मलानत भी करनी है।
डॉ. मोनिका@TrulyMonica

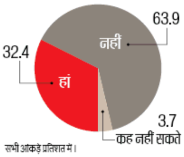


सभी राजनीतिक पार्टियां अपना-अपना जनाधार बढ़ाना चाहती हैं। कांग्रेस भी महाराष्ट्र में अपने बूते पर स्थानीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है ताकि जमीन पर मजबूत हो। इसमें गलत क्या है? दोनों सहयोगी दलों को कांग्रेस की इस रणनीति पर एतराज क्यों है? क्या कांग्रेस उनकी पिछलग्गू बनी रहे?
संजय निरुपम@sanjaynirupam

तालिबान एक आतंकी समूह है और अब वह बलपूर्वक अफगानिस्तान को वापस हथियाने में लगा है। यह सब उसे आइएसआइ और अन्य पाकिस्तानी एजेंसियों के सहयोग से ही संभव हो रहा है। क्रिस एलेक्जेंडर@calxandr

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या मौजूदा माहौल में कांवड़ यात्रा होनी चाहिए?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या गांधी परिवार से बाहर के नेता के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पार्टी की हालत सुधरेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

समधी-समधन हो चुके हैं दहेज के दास,
कहां आप करने लगे आरिफ जी उपवास!
आरिफ जी उपवास रास उनको न आए,
जिनको मोटा माल दुल्हनिया के संग भाए।
दोयम है इंसान प्राथमिक उनके हित धन,
कैसे समझें बात आपकी समधी-समधन!!
– ओमप्रकाश तिवारी



प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

नई औद्योगिक नीति से कितनी बढ़ेंगी नौकरियां

झारखंड की गठबंधन सरकार नए रोजगार सृजित करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। नई औद्योगिक नीति इसका ताजा उदाहरण है। राज्य में निवेश कैसे बढ़े? नए उद्योग कैसे आएं? कैसे ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के मौके बनें, इन सभी बातों की औद्योगिक नीति में चिंता की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वर्ष को नौकरियों का साल घोषित कर रखा है। उनकी इस सोच को अमली जामा पहनाने और धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में रिक्त करीब डेढ़ लाख पद भरने के साथ ही निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण के प्रविधान सहित तमाम अन्य तरह के जतन किए जा रहे हैं। यहां तक स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़े समूहों को आकर्षित करने के लिए कई उत्साहजनक सहूलियतें देने की घोषणा औद्योगिक नीति में की गई है, ताकि इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ें। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य की बाबूशाही इसे आगे कैसे बढ़ाती है। सारा दारोमदार उन्हीं पर है, क्योंकि पूर्व की सरकारों में हुई ऐसी कोशिशें बहुत सफल नहीं रही हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय में बनाई गई टेक्सटाइल पालिसी की देशभर में प्रशंसा हुई थी। कई बड़ी कंपनियां राज्य में आईं। कुछ ने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन सरकार बदलने के बाद पहले जैसी स्थितियां नहीं रहीं। इस दिशा में हेमंत सरकार ने अब कुछ ठोस निर्णय लिए हैं, जिनके चलते दोबारा कंपनियों का भरोसा जमा है। नई औद्योगिक नीति में सरकार की मंशा स्पष्ट हुई है। सभी को यह समझ में आ गया है कि राज्य को आगे ले जाना है तो निवेश लाना ही पड़ेगा और औद्योगिक नीति के जरिये सरकार इस दिशा में बढ़ती दिख रही है। अगले पांच वर्षों में एक लाख करोड़ के निवेश



राज्य की नई औद्योगिक नीति से नौकरियों के अवसर बढ़ने की संभावना है। प्रतीकात्मक

और पांच लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार देने के लक्ष्य के साथ बनी नीति अगले पांच वर्षों के लिए मान्य होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में नए विचारों को आगे बढ़ाने के साथ ही बड़े उद्योगों के लिए निवेश का बेहतरीन माहौल तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस बार उद्योग नीति की खास बात यह है कि इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जोड़ते हुए राज्य में डिस्टिलरी खोलने जैसे अवसर भी मुहैया कराए जा रहे हैं। उद्योग नीति महज उद्योगों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों की चिंता करती दिख रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों को आमंत्रित करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें निवेश की राशि का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न छूट के माध्यम से वापस लौटाया जाएगा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएगा।

नई नीति में राज्य सरकार ने पांच उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों का चयन किया है। इन क्षेत्रों में टेक्सटाइल और एपैरल्स हैं। आटोमोबाइल व आटो कंपोनेंट, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, फार्मा सेक्टर तथा इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र भी शामिल हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का भी चयन किया है। इनमें स्टार्ट अप, शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आइटी और बेवरेज शामिल किए गए हैं।

एमएसएमई को निवेश के हिसाब से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा, सभी सेक्टरों में महिलाओं और एससी और एसटी को अतिरिक्त पांच प्रतिशत सब्सिडी का लाभ देने का सरकार ने निर्णय लिया है। सभी निवेशकों को स्टांप ड्यूटी तथा निबंधन शुल्क में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी। नीति के तहत छोटे उद्योगों के लिए ब्याज पर भी राज्य सरकार पांच प्रतिशत वार्षिक सब्सिडी मुहैया कराएगी। विश्वस्तरीय शिक्षा मुहैया करानेवाले प्राइवेट संस्थानों को राज्य सरकार 12 करोड़ रुपये तक की छूट देगी। यह राज्य में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थान लाने के लिए अभिनव पहल है। ऐसा ही निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर लिया गया है। कोरोना महामारी के बाद लगभग सभी सरकारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ बड़े अस्पतालों को लुभाने के लिए मल्टी स्पेशियलिटी और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों को कुल लागत के हिसाब से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि अधिकतम 25 करोड़ रुपये तक हो सकती है। ऐसे अस्पतालों को ब्याज में हर वर्ष पांच प्रतिशत की राहत भी दी जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों के साथ-साथ नर्सिंग कालेज खोलने के लिए भी राज्य सरकार ने निर्माण लागत पर अधिकतम 25 फीसद राहत देने का निर्णय लिया है। यह राशि एक करोड़ रुपये तक जा सकती है। दूसरी ओर, इंजीनियरिंग कालेज और तकनीकी संस्थानों को 20 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। राज्य में डूब रहे उद्योगों के लिए पहली बार संपत्ति पुनर्निर्माण निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके माध्यम से रुग्ण उद्योगों को फिर से खड़ा होने में मदद की जाएगी। यह उद्योग नीति राज्य में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए विभिन्न कारकों को मजबूती के साथ अपना रही है।

मंथन



डा. सुशील कुमार सिंह
निदेशक, वाइएस रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

असहमति और अभिव्यक्ति का अधिकार

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्याय की अंतिम आवाज अदालत ही होती है। अभिव्यक्ति की क्या सीमा हो और असहमति का क्या स्तर हो, वर्तमान के अनेक संदर्भों में इस पर भी चिंतन और मनन होना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सत्ता संभालने के एक माह बाद जून 2014 में कहा था, 'अगर हम बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देंगे तो हमारा लोकतंत्र नहीं चलेगा।'

गौरतलब है कि लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बुनियादी मूल्य है और संविधान में इन्हें कहीं अधिक महत्व दिया गया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और जनता के लिए निहायत उदार दृष्टि से भरा है। इसी संविधान के भीतर अनुच्छेद 19(1)(क) में मूल अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निहित है जो न केवल लोक सशक्तीकरण का पर्याय है, बल्कि शासन व्यवस्था को लोकहित में समर्पित बनाए रखने का अनूठा काम भी करता है। अमर्त्य सेन की पुस्तक 'द आर्गुमेंटेटिव इंडियन' इसकी प्रासंगिकता को उजागर करती है। अभिव्यक्ति को असहमति से जोड़ना उतना ही समुचित है जितना सहमति से, जिसकी इजाजत संविधान भी देता है और औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में यही सब हासिल करने के लिए वर्षों संघर्ष किया गया।

सहमति और असहमति लोकतंत्र के दो खूबसूरत औजार हैं। इनमें से एक तभी बेहतर होता है जब दूसरा सक्रिय होता है और जब देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूती के साथ लोकहित की जद में अंतिम व्यक्ति भी शामिल होता है तो देश का नागरिक असहमति से सहमति की ओर स्वयं गमन कर लेता है। जाहिर है असहमतियों का दमन लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। एक सभ्य और सहिष्णु समाज के निर्माण के लिहाज से असहमतियों को भी स्थान मिलना चाहिए। हालिया परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ ने असहमतियों के दमन के संदर्भ में जो टिप्पणी की, वह न केवल लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने वाला है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी नया आसमान देने वाला है। अमेरिकन बार एसोसिएशन, सोसायटी फॉर इंडियन लॉ फर्म्स और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स द्वारा आयोजित भारत-अमेरिका कानूनी संबंधों पर साझा ग्रीष्मकालीन सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिक असहमतियों को दबाने के लिए आतंकवाद निरोधी कानूनों या आपराधिक अधिनियमों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र के भीतर असहमति इसकी विशेषता और महत्ता है और संसदीय प्रणाली को आदर्श से लबालब करना है तो असहमतियों को भी स्थान देना होगा। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें। यहां स्पष्ट कर दें कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। अभिव्यक्ति समेत कई मूल अधिकार नागरिकों को मिले हैं। किसी भी प्रसंग पर सहमत या असहमत होना उनका अधिकार है। मूल अधिकारों के दमन की स्थिति में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत लोगों को सर्वोच्च न्यायालय रक्षा कवच देता है।

भारत में कानून का शासन है और कानून के समक्ष सभी समान हैं। साथ ही, यहां के लोकतंत्र ने भी एक लंबा सफर तय किया है। लोकतंत्र में विचार हमेशा स्थिर रहें, ऐसा जरूरी नहीं है। शासन के कामकाज और स्थिति के अनुपात में नागरिकों के विचार में भी उथल-पुथल आता है। असहमति भी हो सकती है, मगर इसका तात्पर्य न तो अपराध है और न ही राजद्रोह है। देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कह चुका है कि सरकार से असहमत होना राष्ट्र से विरोध नहीं है। कानून का राज कायम करने के लिए यह जरूरी है कि लोकतंत्र की मर्यादा को अक्षुण्ण रखा जाए।

देश में अभिव्यक्ति की सीमा के संदर्भ में चिंतन होना चाहिए। वैसे संविधान के अनुच्छेद 19(2) में कुछ अभिव्यक्तियों में पाबंदी की बात है। मौजूदा समय में अभिव्यक्ति के कई आयाम देखे जा सकते हैं। आज जिस तरह से इंटरनेट मीडिया सुगमता से लोगों की पहुंच में है, वह अभिव्यक्ति की असीम ताकत बन गई है। इसकी अभिव्यक्ति की सीमा को लेकर कई बार सरकार भी असमंजस में रही है और इस पर आंशिक पाबंदी की खबरें भी सामने आती रही हैं। हालांकि अब तक इस दिशा में कुछ खास नहीं हुआ है। कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल भी किया है। मगर कई ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यायोचित असहमति जताई और उन्हें न्याय के पचड़े में डाल दिया गया। हालांकि यह सब पड़ताल का विषय है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ सिंह अर्नब गोस्वामी मामले में अपने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून सहित आपराधिक कानून, नागरिकों का असंतोष या उत्पीड़न को दबाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का हनन होना काफी ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो असहमतियां लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का ही एक संदर्भ है, बशर्ते इसके सहारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को मौका नहीं मिलना चाहिए। सरकारें आती और जाती रहेंगी, मगर लोकतंत्र कायम रहना चाहिए। संविधान के निहित मापदंड और न्याय व्यवस्था का विस्तार सघनता से बने रहना चाहिए। कानून की आड़ में असहमति का दम घोटना उचित नहीं है। बल्कि असहमति से प्रभावित होकर जन सशक्तीकरण व लोक कल्याण के हित में सुशासन की पहल को मजबूत करना चाहिए। यही राष्ट्र विकास का शस्त्र भी है और शास्त्र भी।



लोकतंत्र की खूबसूरती है असहमति। प्रतीकात्मक

31 फीसद शिक्षक मानते हैं विज्ञान शिक्षा को देश के लिए उपयुक्त। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सर्वेक्षण में 22 देशों व क्षेत्रों से 398 शिक्षकों को शामिल किया गया, जिनमें से अधिकतर ब्रिटेन (44 फीसद) और भारत (19 फीसद) से थे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 16 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

युवाओं को राहत देने वाला फैसला

उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य के युवा बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में युवाओं के भविष्य को लेकर चिंता भी साफ झलकी है। कोविड के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए समूह-ग के पदों पर होने वाली भर्ती में युवाओं को आयु सीमा में एक साल की छूट देने का सरकार का फैसला इसकी तस्दीक करता है। दरअसल युवा बेरोजगारों पर कोरोना की मार पड़ी है। नियमित शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस परिदृश्य के बीच सरकार से संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है और मौजूदा सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश की कमान संभालने के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भले ही परिचयात्मक रही हो, मगर तब भी इसमें बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में फैसले लिए गए। अब बुधवार को हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में भी युवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।

कोविड के कारण उपजी परिस्थितियों को देखते हुए समूह-ग के पदों पर भर्ती के लिए युवाओं को आयु सीमा में एक साल की छूट देने का धामी सरकार का फैसला तर्कसंगत है

दरअसल वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। कोविड के कारण ही लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और उसकी परिधि से बाहर के समूह-ग के पदों पर होने वाली चयन की प्रक्रिया लगातार बाधित हुई है। पिछले साल लाकडाउन के कारण बड़ी संख्या में युवा आवेदन करने से वंचित रह गए थे। इसे देखते हुए तब आयु सीमा में एक बार की छूट देते हुए आयु की गणना एक जनवरी 2020 के आधार पर किए जाने की मोहलत दी गई थी, लेकिन कोविड के कारण इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। यही नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान भी बंद हैं, जिससे युवाओं की तैयारी बाधित हुई है। ऐसे युवाओं की भी अच्छी-खासी संख्या है, जो नौकरी के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। अब प्रदेश सरकार ने इन युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। आयु सीमा में एक बार के लिए एक साल की छूट देते हुए आयु की गणना एक जनवरी 2021 के आधार पर करने का निर्णय लिया गया है। जाहिर है कि इससे उन युवाओं को राहत मिल गई है, जो आयु सीमा पार करने के कारण रोजगार के अवसर से वंचित हो रहे थे। साथ ही युवाओं के बीच से यह अपेक्षा भी की जा रही है कि प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में कुछ और राहत भी देगी। आज देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। सरकारों के तमाम प्रयास करने के बाद भी सबको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में धामी सरकार के फैसले से कुछ युवाओं को रोजगार मिल जाता है तो यह खुशी की बात होगी।

बंगाल

उपचुनाव को लेकर बेचैनी

बंगाल में विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद भी दो माह के भीतर सत्तारूढ़ दल में उपचुनाव को लेकर इतनी बेचैनी कभी नहीं दिखी थी। विधानसभा चुनाव में 213 सीटें जीतने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस पांच सीटों पर उपचुनाव और दो सीटों पर आम चुनाव शीघ्र कराने को लेकर बेचैन है। इसी का नतीजा है कि गुरुवार को तृणमूल के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली जाकर चुनाव आयोग के समक्ष जल्द उपचुनाव कराने की मांग रखी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस तो विधानसभा चुनाव में जीत गई और सरकार भी बना ली, लेकिन ममता बनर्जी स्वयं नंदीग्राम में चुनाव हार गईं। बावजूद इसके उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। ऐसे में अब उन्हें संविधान के मुताबिक चार नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना होगा।

बंगाल में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए उन्हें उपचुनाव में जीतना होगा। परंतु अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जब बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी था तो मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना के केसों में तेजी से इजाफे के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि 'गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा है। चुनाव में राजनीतिक दलों ने कोरोना प्रोटोकाल का जमकर उल्लंघन किया है और आयोग उन्हें रोकने में नाकाम रहा है। आयोग के चलते स्थिति इतनी विकराल हुई है और वह राजनीतिक दलों पर नकेल कसने में नाकाम रहा है।'


मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता को विधानसभा सदस्य चुना जाना जरूरी है। फाइल

ममता बनर्जी स्वयं नंदीग्राम में चुनाव हार गईं। बावजूद इसके उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। ऐसे में अब उन्हें संविधान के नियम के मुताबिक चार नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना होगा

इसके बाद कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी चुनाव अनिश्चितकाल के लिए रोक दिए हैं। उस समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार में सवाल कर रही थीं कि बंगाल में आठ चरणों में मतदान क्यों कराया गया? कोरोना के मामले बढ़ने के लिए आयोग और केंद्र सरकार दोषी है। अब जबकि ममता को छह माह के भीतर यानी चार नवंबर तक चुनाव जीतकर विधायक बनना ही होगा तो उपचुनाव कराने को लेकर परेशान हैं। सिर्फ सीएम ही नहीं, दो मंत्रियों को भी उपचुनाव जीतना होगा। तृणमूल को डर है कि कहीं एक बार फिर कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ गया तो मामला लटक जाएगा। इसीलिए उपचुनाव तत्काल संपन्न हो जाए।

झारखंड

मतांतरण की साजिश

झारखंड के भोले-भाले आदिवासी दशकों से ईसाई मिशनरियों के लिए मतांतरण के आसान लक्ष्य रहे हैं। गरीबी, बदहाली में जी रहे इन लोगों को बरगला कर और प्रलोभन देकर इन्हें धर्म बदलने को प्रेरित या मजबूर किया जाता रहा है। हाल के दिनों में कुछ कड़े नियम-कानून भी बने, जिसमें मतांतरण को अवैध घोषित करते हुए इसमें संलिप्त लोगों के लिए सजा के प्रविधान बनाए गए, लेकिन गुपचुप तरीके से मतांतरण की गतिविधियां लगातार चल ही रही हैं। भारतीय चिंतन और दर्शन में धर्म जीवन जीने की व्यवस्था है। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे संस्कारों को आगे बढ़ाने का स्वतः स्फूर्त उपक्रम है। ये नियम और संस्कार जीवन भर व्यक्ति के साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना नहीं चाहता, लेकिन लालच देकर इन्हें मजबूर किया जाता है।

गरीबों की मदद करने के एवज में धर्म बदलने की शर्त रखने वाले शायद यह नहीं समझते कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। एक दिन पहले ही साहिबगंज में 14 पहाड़िया जनजाति समुदाय के आदिवासियों ने ईसाई मत अपनाने के बाद सनातन मत में वापसी की। इन आदिवासियों ने बताया कि उन्हें लालच देकर और बड़े-बड़े सपने दिखाकर ईसाई बनाया गया था। खुद को जड़ों से उखड़ता हुआ महसूस करने के बाद ये सभी पुनः अपने मूल मत में लौट आए। हाशिये पर रह रहे लोगों को बहकावे में आकर दूसरे मत में जाने से रोकने के लिए इनकी जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना होगा, ताकि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतांतरण की चल रही साजिश के शिकार न बनें। सनातन परंपरा ने एक दौर वह भी देखा है जब समाज में निचले पायदान पर रह रहे लोग उपेक्षा से निराश होकर बौद्ध और अन्य मत अपना रहे थे। झारखंड के आदिवासियों को अपनी ओर मोड़ने के लिए बहुत पहले इस इलाके में ईसाई मिशनरियां सक्रिय हो गई थीं। अब तो कई अन्य मतों के लोग भी मतांतरण के अभियान में जुट गए हैं। मतांतरण की वजह से आदिवासी समाज दो खेमे में बंट चुका है, जिससे उनकी मूल पहचान नष्ट हो रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए गंभीर प्रयास करने के जरूरत है।


आदिवासियों के मतांतरण की प्रक्रिया को रोकना होगा। फाइल

गरीबों की मदद करने के बदले मतांतरण की शर्त रखना पाप की ही श्रेणी में आता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतांतरण की साजिश रचने वाले इसे ही अपना धर्म मानते हैं

पंजाब

चुनावी वादे पूरा करने की कवायद

पंजाब के दो लाख 85 हजार खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा करके राज्य सरकार ने एक और चुनावी कदम ही उठाया है। इससे पहले सरकार ने 5.64 लाख किसानों का 4,624 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था। इनमें अधिकतम सीमा दो लाख रुपये तक थी। इस बार क्योंकि कर्जमाफी भूमिहीन किसानों और खेत मजदूरों की है तो जाहिर है कि यह कम कर्ज लेने वाले लोग हैं इसलिए इनके बीस हजार रुपये तक के कर्ज माफ होंगे। वह कर्ज जो इन्होंने सहकारी समितियों वगैरह से ले रखे हैं। इस तरह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने एक चुनावी वादे को पूरा करने की कोशिश की है।

कांग्रेस ने वर्ष 2017 में यह वादा किया था। इसे सरकार पूरी तरह भुनाना भी चाहती है, इसीलिए इस राशि को बांटने के लिए राजीव गांधी की जन्मतिथि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री चेक बांटेंगे। ऐसे ही कार्यक्रम सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार पत्र देने के लिए आयोजित किए थे। वह भी एक चुनावी वादा था, लेकिन वाकई कितनों को उनकी काबिलियत के मुताबिक रोजगार मिला, कितनों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां मिलीं, यह अलग बात है। सरकार को यह गिनाने के लिए तो हो गया कि उसने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए इतने रोजगार दिए हैं। जाहिर है कि कैप्टन सरकार चुनावी रफ्तार पकड़ रही है। कहीं न कहीं अब उस पर यह दबाव तो है ही कि घोषणा पत्र में किए गए वादे चुनाव से पहले-पहले पूरा करे। बेअदबी जैसे मामलों में दोषियों को सजा दिला पाना तब तक कितना संभव हो पाएगा, यह तो कुछ कहा नहीं जा सकता, यह सरकार भी भली-भांति जानती है, इसलिए अन्य वादों पर अमल की कवायद तेज हो गई है। हाल ही में कांग्रेस के ही कई विधायकों, मंत्रियों और सांसदों ने खुलकर यह असंतोष भी जताया था कि चुनावी वादे पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह को दूर करने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से गठित कमेटी ने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को 18 सूत्रीय एजेंडे पर चुनाव से पहले काम करने को कहा था। इनमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ ही पूर्व सरकार के समय में हुए बिजली समझौतों को रद करने के अलावा छोटे किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी का विषय भी था जिसे सरकार ने पूरा करके किसानों की हमदर्द होने का संदेश देने की कोशिश की है।

कैप्टन सरकार चुनावी रफ्तार पकड़ रही है। कहीं न कहीं अब उस पर यह दबाव तो है ही कि घोषणा पत्र में किए गए वादे चुनाव से पहले-पहले पूरा करे

कर्ज के कारण किसानों की खुदकुशी के मामले खत्म नहीं हुए हैं इसलिए यह चुनावी मुद्दा बन सकता था। वैसे भी पिछले छह माह से किसान जिस तरह सभी के एजेंडे में हैं, उसे देखते हुए वोट बैंक को लुभाने की कोशिश भी यह है।

पंजाब में खेल मंत्री सोढ़ी ने दो बार लिया जमीन का मुआवजा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआइ जांच की मांग
- 1962 में सरकार ने सड़क बनाने के लिए किया था जमीन का अधिग्रहण

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की गई है। आरोप है कि उन्होंने गुरुहरसहाय में जमीन का दूसरी बार अधिग्रहण करवाकर उसका मुआवजा लिया है। गुरुवार को यह याचिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई, तो जस्टिस अरुण पल्ली निजी कारणों के चलते इस मामले की सुनवाई से अलग हो गए। अब इस मामले की सुनवाई उस बेंच के सामने होगी, जिसके सदस्य जस्टिस अरुण पल्ली न हों।

यह याचिका रूपनगर के रहने वाले दिनेश चड्ढा, सुरिंदर पाल सिंह और कमल सिंह ने दायर की है। उन्होंने सोढ़ी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग भी की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने वर्ष 1962 में फिरोजपुर से फाजिल्का के लिए सड़क बनाए जाने के लिए राणा गुरमीत सोढ़ी की गुरुहरसहाय में 12 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसका मुआवजा 1963 में दे दिया गया था। इसके बाद यह सड़क बन भी गई थी, लेकिन सोढ़ी ने वर्ष 2000 में इन सभी तथ्यों को छिपा कर निचली अदालत में याचिका दायर कर दी और वहां बताया कि सरकार ने बिना अधिग्रहण किए और बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन पर सड़क बना दी है। इसलिए उन्हें जमीन वापस दी जाए या उचित मुआवजा दिया जाए। 2007 में फैसला उनके पक्ष में आ गया।

हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने इस फैसले के खिलाफ दिखावे के तौर पर अपील की, जिस पर फैसला राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के पक्ष में आया। इसके बाद सरकार ने 2012 में दोबारा इसी जमीन का अधिग्रहण कर एक करोड़ 83 लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा जारी कर दिया। इस तरह एक ही जमीन का दो बार अधिग्रहण कर मुआवजा ले लिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सब कुछ राणा गुरमीत सोढ़ी ने अदालतों से सभी तथ्य छिपा कर किया।

यह मामला सामने आने के बाद सरकार पर दबाव बना तो सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच करवाई। इसमें यह सामने आया कि एक ही जमीन का दो बार अधिग्रहण कर मुआवजा लिया गया। इतना ही नहीं पंजाब सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट में हलफनामा भी दे दिया था। इसके बावजूद अभी तक सरकार ने अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा अब इस मामले की सीबीआइ से जांच करवाई जानी चाहिए।

सामाजिक जागरूकता से कोरोना की लहर को थामेगा संघ

जागरण संवाददाता, चित्रकूट

उप्र के चित्रकूट जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सतना जिला अंतर्गत दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआइ) के प्रकल्प आरोग्यधाम में चल रही मध्य क्षेत्र की बैठक के अंतिम दिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर को थामने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कार्ययोजना बना ली। इसके तहत सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाकर संपन्न लोगों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक गांव में प्रशिक्षित स्वयंसेवक में कम से कम एक महिला और एक पुरुष की सहभागिता जरूर रहेगी।

प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में सोमवार को समाप्त हुई संघ की चार दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में लिए गए निर्णयों पर अमल के लिए गुरुवार को मध्य क्षेत्र के पदाधिकारियों ने कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को सितंबर से गांवों में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने पर सहमति बनी। मध्य क्षेत्र (छत्तीसगढ़, महाकौशल, मध्य भारत और मालवा प्रांत) के संघ पदाधिकारियों ने सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य व क्षेत्र प्रचारक दीपक के मार्गदर्शन में तय किया कि कोरोना की लड़ाई में क्षेत्र के संपन्न लोगों को भी जोड़ा जाएगा, जो अपने स्तर से लोगों की मदद कर सकें। इसके अलावा प्रत्येक गांव में दो से तीन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें एक महिला व एक पुरुष अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे। इनको सरकार के सिस्टम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका होगी। संघ का मानना है कि यदि महामारी की तीसरी लहर आती है तो जमीनी स्तर तक सरकार के प्रबंधन को और मजबूत बनाने में प्रशिक्षित कार्यकर्ता मददगार होंगे। यह दूसरी लहर में भी देखने को मिल चुका है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से काफी नुकसान हुआ है। आगे ऐसे हालात बनते हैं तो गांव के प्रशिक्षित स्वयंसेवक मदद करेंगे। लोगों को सहभागी बनाने के लिए जिला स्तर पर संघ के पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं।

चित्रकूट में चिंतन

- अगस्त तक पूरा हो जाएगा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का काम
- गांव स्तर पर कोरोना को मात देने के लिए तैयार की गई योजना


कोरोना की लड़ाई में क्षेत्र के संपन्न लोगों को भी जोड़ेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।

अगस्त तक पूरा होगा प्रशिक्षण

कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए संघ ने निर्णय लिया है कि युवा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण अगस्त में पूरा कर लिया जाएगा। सितंबर में टोलियां गांव स्तर में पहुंचने लगेंगी। इस अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा।

चित्रकूट में संघ के बाद आज से फरीदाबाद में विश्व हिंदू परिषद का शुरू होगा मंथन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- अंतरराष्ट्रीय, केंद्रीय प्रबंधन समिति एवं प्रन्यासी मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में होंगे कई अहम निर्णय
- नए कार्याध्यक्ष, राम मंदिर निर्माण कोष पर उठे विवाद, जनसंख्या नियंत्रण कानून आदि पर होगी चर्चा

चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बाद अब शुक्रवार से फरीदाबाद में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का मंथन शुरू होगा। विहिप की अंतरराष्ट्रीय, केंद्रीय प्रबंधन समिति एवं प्रन्यासी मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

बैठक के पहले दिन विहिप की कोर टीम में उन विषयों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिन पर 17 व 18 जुलाई को होने वाले विभिन्न सत्र के दौरान चर्चा होनी है। इसके बाद 19 जुलाई को एक बार फिर कोर टीम दो दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन संबंधी दिशानिर्देश जारी करेगी। विहिप की इस बैठक में करीब 275 प्रतिनिधि अपेक्षित रहते हैं, मगर कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते फरीदाबाद मानव रचना विश्वविद्यालय के सभागार में सिर्फ 70 प्रतिनिधि ही हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्रीय व क्षेत्रीय प्रमुख पदाधिकारी होंगे। अन्य प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़ेंगे।

17 व 18 जुलाई को विहिप के नए कार्याध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण कोष पर उठे विवाद से लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए व जबरन मतांतरण के खिलाफ कानून बनाने के विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। विहिप इसी बैठक में अपने सालभर के एजेंडे को भी स्पष्ट करेगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे, कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय, संघ की तरफ से विहिप के पालक सुरेश भय्या जी जोशी, केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, संयुक्त महामंत्री डाक्टर सुरेंद्र जैन भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।

17 व 18 जुलाई को विहिप के नए कार्याध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी।

रामपुर के नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे की योजना पेश

जासं, रामपुर : रामपुर के नवाब खानदान की संपत्ति बंटवारे को लेकर जिला जज ने योजना पेश की। 172 पेज में तैयार योजना पर आपत्ति पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। 300 करोड़ की शत्रु संपत्ति मामले में अलग से फैसला होगा।

नवाब खानदान की रामपुर में 2,600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। लंबे समय से इसके बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। 31 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। जिला जज को दिसंबर, 2020 तक यह काम पूरा करना था, लेकिन कोरोना की वजह से अदालत लंबे समय तक बंद रही और बंटवारे की प्रक्रिया लटक गई। इसके बाद छह माह का समय और दिया गया। गुरुवार को जिला जज की अदालत में फिर सुनवाई हुई। उन्होंने वकीलों के सामने बंटवारा योजना पेश की। इस मामले में 11 पक्षकारों की वकालत कर रहे पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि बंटवारा योजना की प्रमाणित कापी लेने के बाद पता लगेगा कि किसके हिस्से में कौन सी संपत्ति आई है। उन्होंने कहा, रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खान की बेटी मेहरून्निसा बेगम भी इस मामले में पक्षकार है। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल अब्दुल रहीम खान की पत्नी मेहरून्निसा वर्तमान में अमेरिका में रह रहीं हैं। उनकी संपत्ति को भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति बताते हुए कोर्ट में जो प्रार्थना पत्र दिया था, उस पर बाद में फैसला होगा।

जागरण विशेष
सहेज लो हर बूंद
जल संरक्षण

'पानी बैंक' बनाकर ग्रामीण बुझा रहे 120 एकड़ धरती की प्यास

पहल : बदगई गांव में व्यर्थ बहने वाले बारिश के पानी को छोटे नाले तक दिशा देकर सहेजा गया, छाई हरियाली

मिथलेश देवांगन • नईदुनिया

छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के डोंगरगांव ब्लाक के ग्राम बदगई में ग्रामीणों ने 'पानी बैंक' बनाया है। सूखानाला और शिवनाथ नदी के बीच बसे इस गांव में एक छोटा नाला (सरार) है। 2010 में सिंचाई संकट से जूझ रहे कुछ ग्रामीणों ने बारिश के दिनों में व्यर्थ बहने वाले पानी को सरार तक दिशा दी। फिर खेतों से ओवरफ्लो होने वाले पानी के बहाव को भी इसी सरार में मोड़ दिया। इससे सरार में वर्षों पानी भरा रहता है।

भूगर्भ जलस्तर भी सुधरा: : इस पानी से करीब 120 एकड़ में खेतों की सिंचाई तो हो ही रही है, साथ ही आसपास का भूजल स्तर भी बढ़ गया है। पंप से आसानी से पानी लिया जा सकता है। ग्राम बगदई के निकट स्थित सूखानाला और शिवनाथ नदी कार्तिक पूर्णिमा के बाद से सूखने लगती थी। खेतों के बोरवेल बंद हो जाते थे। इस पर अपने खेतों की प्यास बुझाने के लिए ग्रामीणों ने सरार में स्थायी पानी बैंक बनाने की मुहिम छेड़ी। किसानों की सफलता देख तत्कालीन सरपंच मनोरमा दुबे और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी पहल की थी। इसके बाद धीरे-धीरे पूरा गांव जुड़ा और मनरेगा के तहत से तीन चेकडैम के लिए राशि भी मंजूर हो गई। प्रशासन ने भी सहयोग किया और 16.5 लाख रुपये लगाकर सरार में एक किलोमीटर के दायरे में तीन चेकडैम बनवा दिए। इसी साल मनरेगा से 10 लाख रुपये खर्च कर गहरीकरण कराया गया। जल संकट के चलते पानी की हर बूंद की कीमत समझने वाले बगदई के लोग अब पूरे साल पानी बैंक का न केवल उपयोग करते हैं, बल्कि साफ-सफाई, देखरेख और वहां की चौकीदारी भी करते हैं।

बारी-बारी से निभाते हैं जिम्मेदारी: सरार व चेकडैम की साल में दो बार सफाई कराई जाती है। ग्राम समिति ने ग्रामीणों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय कर रखी है। कोई पौधों की देखरेख करता है तो कोई सिंचाई की जिम्मेदारी निभाता है। सफाई व मरम्मत आदि के लिए भी सभी को दायित्व सौंपा गया है।


राजनांदगांव के ग्राम बदगई में ग्रामीणों द्वारा बनाया गया पानी बैंक • जागरण

पानी से गांव में आई उन्नति

बगदई गांव की आबादी करीब 1,400 है। इनमें से लगभग 80 किसानों के खेत सरार के आसपास ही हैं। सभी के पास बोरवेल है। वहां पानी की कभी कमी नहीं होती है। दूसरी तरफ गांव के दूसरे छोर पर खेती करने वाले किसानों के बोरवेल दिसंबर में ही जवाब देने लग जाते हैं। सरपंच भगदवती निर्मलकर ने बताया कि सरार के स्रोत से किसानों की उन्नति हुई है। कृषक धनराज ठाकुर बताते हैं कि पहले अपने खेतों में केवल एक ही फसल मुश्किल से ले पाते थे। मगर अब यहां 120 एकड़ की फसलों में हमेशा हरियाली रहती है। पास के आरी गांव का भी बड़ा हिस्सा यहीं के पानी के भरोसे रबी की फसल लेता है।



बगदई के ग्रामीणों ने उन गांवों के लिए बड़ा उदाहरण पेश किया है, जहां बारिश के दिनों में पानी गांव से होकर ही व्यर्थ बह जाता है। इस तरह की पहल में प्रशासन भी पूरी मदद करेगा।
–तारन प्रकाश सिन्हा, कलेक्टर

जल का जागरण

जल बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस तरह से इस अनमोल संसाधन की किल्लत बढ़ रही है, उसे देखते हुए हम सभी का फर्ज इसे सहेजने के प्रति बढ़ जाता है। इसी क्रम में दैनिक जागरण अपने जल संरक्षण सरोकार के तहत लोगों को जल सहेजने के लिए जागरूक कर रहा है।

स्कैन करें और पढ़ें 'सहेज लो, हर बूंद' अभियान की अन्य सामग्री।

मां-बाप नाजायज हो सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं : हाई कोर्ट

- दिवंगत लाइनमैन की दूसरी पत्नी के बेटे ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए किया था आवेदन, कंपनी ने कर दिया था इन्कार

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता नाजायज हो सकते हैं, लेकिन उनसे पैदा होने वाली संतान नहीं क्योंकि अपने जन्म में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती।

जस्टिस बीवी नागरत्ना व जस्टिस एच. संजीव कुमार की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणी एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए की। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने के. संतोष की याचिका खारिज कर दी थी जिसने पिता की 2014 में मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी बैंगलोर इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया था। उनके पिता कंपनी में लाइनमैन ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत थे। याचिकाकर्ता का जन्म पिता की पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी से हुआ था, लिहाजा कंपनी ने इसे अपनी नीति के विरुद्ध बताते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। एकल पीठ के आदेश को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि कोई भी बच्चा पिता और मां के बिना दुनिया में नहीं आ सकता। लिहाजा, कानून को इस तथ्य को मान्यता प्रदान करनी चाहिए कि माता-पिता नाजायज हो सकते हैं, बच्चे नहीं। यह संसद का काम है कि वह बच्चों के वैध होने को लेकर कानून में एकरूपता लाए। इस प्रकार, यह संसद को निर्धारित करना है कि वैध विवाह से बाहर पैदा हुए बच्चों को किस तरह सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बीईएससीओएम को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर कानून व उसकी टिप्पणी के मुताबिक विचार करे। अदालत ने बिजली विभाग के दूसरी पत्नी से जन्मे बच्चों की नियुक्ति से संबंधित 23 सितंबर, 2011 को जारी सर्कुलर को भी रद कर दिया।

19 जुलाई से अनलाक होने जा रहा है ब्रिटेन। जानसन सरकार इस अनलाक को कोरोना टीकाकरण रणनीति की कड़ी परीक्षा के तौर पर देख रही है। यहां 66 फीसद वयस्कों का पूर्ण कोरोना टीकाकरण हो चुका है।

'अफगान में आतंकी संगठनों की वापसी रोकेंगे'

अशांत अफगानिस्तान ▸ अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले, मिशन अभी खत्म नहीं


अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

व्यापारिक शहर पर कब्जे को लेकर परस्पर विरोधी दावे

वाशिंगटन, प्रेट्र: अफगानिस्तान में तीन साल तक अमेरिकी सेना की कमान संभालने वाले जनरल मिलर अपने देश पहुंच गए हैं। यहां उनका पेंटागन में रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने स्वागत करते हुए कहा कि अफगान मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों की वापसी रोकेगा।

रक्षा मंत्री ने कहा है कि सेना की वापसी अगस्त तक जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अफगान सेना को बराबर मदद दी जाती रहेगी। किसी भी आतंकवादी संगठन को वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए सैन्य मदद के अलावा अन्य तरीके से भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

रायटर के अनुसार, पाक सीमा से लगे व्यापारिक शहर स्पिन बोल्डक पर कब्जे को लेकर परस्पर विरोधी दावे किए गए हैं। अफगानिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसने व्यापारिक शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया है। इधर तालिबान ने कहा है कि उसका कब्जा बना हुआ है। स्पिन बोल्डक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर है और यहां से हर रोज नौ सौ ट्रक सामान की आवाजाही होती है।

अमेरिकी सैन्य अड्डे के लिए मध्य एशिया का कोई देश तैयार नहीं

एपी के अनुसार, अफगानिस्तान से सेना वापसी के बाद अमेरिका मध्य एशिया के किसी देश में सैन्य अड्डा बनाने का इच्छुक है। इसके लिए सभी मध्य एशियाई देशों में राजनयिक प्रयास तेज हो गए हैं। फिलहाल अमेरिका को इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। अधिकांश देश रूस के प्रभाव में हैं। एएनआइ के अनुसार व्हाइट हाउस की सलाहकार एलिजाबेथ शेरवुड रैंडाल ने मध्यएशिया के पांच देशों के साथ ताशकंद में बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में शांति का आधार तैयार करेगा।

एक करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफगान नागरिक हुए बेरोजगार

एएनआइ के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान ने 28 प्रांतों में 260 नागरिक सुविधाओं को ध्वस्त कर दिया है। इसमें हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। सिविल सर्विस कमीशन के प्रमुख नादर नादेरी ने बताया कि यहां एक करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग अब तक बेरोजगार हो गए हैं।

अफगानिस्तान में हिंसा की एससीओ ने की निंदा : प्रेट्र के अनुसार, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भारत सहित सात देशों के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान में हिंसा की आलोचना की है। हिंसा के लिए आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार माना गया है। संगठन ने एक वक्तव्य में कहा है कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी भूमिका को बढ़ाना चाहिए।

22 अफगान सैनिकों की हत्या की अमेरिका ने की निंदा : एएनआइ के अनुसार, अमेरिका ने तुर्कमेनिस्तान की सीमा से लगे फरयाब प्रांत में 22 अफगान सैनिकों की गोली मारकर हत्या को नृशंस हत्याकांड बताते हुए निंदा की है।

अमेरिका के मददगार अफगानियों की निकासी का काम होगा तेज

न्यूयॉर्क टाइम्स से

▸ इसी महीने शुरू होगी अफगानिस्तान से बाहर भेजने की प्रक्रिया

▸ प्रवासी वीजा की पात्रता के बारे में सार्वजनिक नहीं की गई जानकारी

वाशिंगटन: अफगानिस्तान में बीस साल तक अमेरिकी सेना के दुभाषिए और अन्य कार्यों में सहयोगी के रूप में साथ देते रहे अफगान सहयोगियों को इसी महीने से बाहर भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इसको सहयोगी शरणार्थी अभियान का नाम दिया गया है।

बाइडन प्रशासन के अधिकारियों ने वाशिंगटन में बताया कि अफगानिस्तान से उन लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, जो अमेरिकी सेना की सहायता करने के कारण तालिबान आंतकियों के निशाने पर हैं। अभियान में तेजी जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगी।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने अभी यह विवरण नहीं दिया है कि प्रवासी वीजा प्राप्त करने वाले अफगानियों की क्या पात्रता तय की गई है। उन्हें सुरक्षित रूप से कहां ले जाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि बीस साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद अमेरिकी सेना की वापसी हो रही है जो कि अंतिम चरण में है। इसके चलते सेना के अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने का दबाव बढ़ गया है। अमेरिका ने वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने का काम शुरू कर दिया है।

अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के लिए दुभाषिए, इंजीनियर, ड्राइवर अन्य काम करने वाले लगभग 18 हजार अफगान नागरिकों ने वीजा के लिए आवेदन किया है। एक माह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगान सहयोगियों के लिए योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने सहयोगियों को असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के मतांतरण पर रोक का पाक के मंत्री ने किया विरोध

▸ धार्मिक मामलों के मंत्री 18 साल की उम्र से पहले मतांतरण पर पाबंदी के खिलाफ

▸ मंत्री नूरल हक कादरी बोले, इस्लाम में कम उम्र में धर्म बदलने के कई उदाहरण हैं

इस्लामाबाद, एएनआइ : पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के दमन को लेकर दशकों से लोग इतने आदी हो चुके हैं कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद इमरान खान की सरकार के एक मंत्री ने खुलकर जबरन मतांतरण के खिलाफ कानून बनाए जाने का खुलकर विरोध किया है।

पाकिस्तानी अखबार डान की एक रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सीनेट संसदीय समिति की एक बैठक के दौरान बुधवार को धार्मिक मामलों के मंत्री नूरल हक कादरी ने 18 साल की उम्र से पहले धर्म बदलने पर कानूनी प्रतिबंध लगाए जाने का जमकर विरोध किया। कादरी ने कहा कि अगर को 14 साल की उम्र में अपना धर्म बदलकर कोई और धर्म अपनाना चाहता है तो उसे वह कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह 18 साल से कम आयु के लोगों का धर्म बदलने के प्रतिबंध का समर्थन नहीं करते हैं।

कादरी ने कहा कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें लोगों ने 18 साल की आयु से पहले ही अपना धर्म बदलने की इच्छा जताई है। इस्लाम में भी कई उदाहरण हैं जब लोगों ने 18 साल यानी बालिग होने से पहले अपना धर्म बदलना चाहा। इस बीच, सीनेटर दानेश कुमार ने समिति को बताया कि बलूचिस्तान में लोगों के मतांतरण का एक नया चलन शुरू हो गया है। उन्होंने दावा किया कि दलबनदिन में एक धार्मिक नेता है जो सफाईकर्मियों से कहता है कि अगर उन्होंने इस्लाम कुबूल कर लिया तो उन्हें यह काम नहीं करना पड़ेगा।

पाकिस्तान में आए दिन गैर मुसलिम नाबालिग लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जबरन इस्लाम कुबूल करवाने और निकाह पढ़वाने की खबरें आती रहती हैं। पंजाब के गुजरांवाला में एक नाबालिग लड़की का बलपूर्वक मतांतरण कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर काफी दबाव डाला गया है। उसके बाद ही विगत 20 मई को 13 साल की एक ईसाई लड़की नायब गिल का अपहरण करके उसका 30 साल के एक आदमी से जबरन निकाह करा दिया गया था।

न्यूज गैलरी

यूएई में 10 लाख डालर के लकी ड्रा का विजेता बना भारतीय

दुबई : यूएई में एक भारतीय नाविक 10 लाख डालर (सात करोड़ 45 लाख रुपये) के लकी ड्रा का विजेता बन गया। महाराष्ट्र में ठाणे के रहने वाले गणेश शिंदे ने दुबई में 16 जून को जैकपाट टिकट खरीदा था। वह ब्राजील की कंपनी में नाविक रूप में कार्यरत हैं और दुबई एवं रिओ जी जेनेरियो के बीच यात्रा करते हैं। इस बार दुबई पहुंचने पर शिंदे ने पाया कि वह जैकपाट के विजेता बन गए हैं। (प्रेट्र)

यूरोप में भयंकर बाढ़ से 33 की मौत, दर्जनों लापता

बर्लिन : जर्मनी व उसके पड़ोसी बेल्जियम में आई बाढ़ की चपेट में आने से 33 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लापता हैं। गुरुवार को तेज बहाव के कारण सड़कें और स्ट्रीट नदी-नाले में तब्दील हो गए। तेज बहाव की चपेट में आकर कई कारें बह गईं। कई भवन ध्वस्त हो गए हैं। हाल के दिनों में पश्चिमी यूरोप में तूफान के कारण नदियां और जलाशय उफान पर हैं, जिससे रात में अचानक बाढ़ आ गई। जर्मनी में 26 लोगों की मौत हो गई है। कई भवनों के ध्वस्त हो जाने से 70 लोग लापता हैं। दर्जनों लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। (रायटर)

सुरंग में फंसे 14 कामगारों को बचाने में लगे 1000 लोग

बीजिंग : दक्षिणी चीन में एक निर्माणाधीन सुरंग में आई बाढ़ में फंसे 14 निर्माण कामगारों को बचाने के काम में 1000 से ज्यादा कामगार, 22 अग्निशमन वाहन और पांच पंपिंग वाहन लगाए गए हैं। बचाव दल फंसे हुए कामगारों से संपर्क नहीं कर पाया है। आसपास के शहरों से बचाव टीम रवाना कर दी गई है। मार्च में दूसरे हिस्से की सुरंग में दो कामगारों की मौत हो गई थी। सुरक्षा दीवार ढह जाने कामगार गिरते पत्थरों की चपेट में आ गए थे। (एपी)

अमेरिकी कदम विश्व व्यापार के लिए खतरा : चीन

बीजिंग : चीन की सरकार ने शिनजियांग प्रांत में जबरन मजदूरी के आरोपों को खारिज किया है। उसने कहा, वाशिंगटन विश्व व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी सांसदों द्वारा आयात पर अंकुश लगाने और अमेरिकी कंपनियों को क्षेत्र के साथ कारोबार करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद चीन ने अपना बयान जारी किया है। (एपी)

सेवा इंटरनेशनल ने भारत के लिए जुटाए तीन करोड़ डालर

वाशिंगटन : एक भारतीय-अमेरिकी संस्था ने कहा,उसने भारत में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए तीन करोड़ डालर (210 करोड़ रुपये से अधिक) जुटाए हैं। संस्था ने भारत के लिए मेडिकल उपकरण की नई खेप भेज दी है। सेवा इंटरनेशनल यूएसए आक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर जैसे मेडिकल उपकरण खरीदती है और उसे भारत भेज देती है। (एपी)

नेपाल सरकार ने 18 को संसद का सत्र बुलाने की सिफारिश की

काठमांडू : नेपाल सरकार ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को 18 जुलाई को प्रतिनिधि सभा का नया सत्र आहूत करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बहाल सदन की बैठक 18 जुलाई को आहूत करने का फैसला किया गया। 22 मई को असंवैधानिक रूप से भंग किए जाने के बाद 275 सदस्यीय निचले सदन की यह पहली बैठक होगी। नेपाल सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को पांच महीनों में दूसरी बार भंग प्रतिनिधि सभा को बहाल कर दिया था। (प्रेट्र)

शृंगला ने कहा, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होने का पूरा अधिकार

▸ विदेश सचिव बोले-देश परिषद में दो वर्षों का अधिकतम लाभ उठाएगा

▸ भारत अगस्त माह में रहेगा 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष


विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला। जागरण आर्काइव

न्यूयार्क, प्रेट्र: विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने दो वर्षों का अधिकतम लाभ उठाएगा और पुष्टि करेगा कि उसने 15 देशों की संस्था में अपनी स्थायी सदस्यता का अधिकार स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा, भारत सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी कदमों और सुरक्षा निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही परिषद की अध्यक्षता की तैयारी कर रहा है।

शृंगला ने गुरुवार को कहा, 'अगले महीने, संयुक्त राष्ट्र के साथ हमारी भागीदारी में हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनेंगे।' उन्होंने कहा, 'हम सुरक्षा परिषद में अपने दो साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। परिषद और हमारे विषयों पर अपनी छाप छोड़ेंगे और साबित करेंगे कि भारत वास्तव में इसका हकदार है। इसी जिम्मेदारी के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के अपने अधिकार को साबित करेगा।'

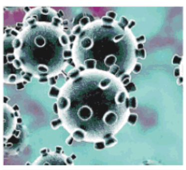
शृंगला बुधवार को न्यूयार्क पहुंचे। वह फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति के नेतृत्व में होने वाली सुरक्षा परिषद की दो उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। वह गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे और लीबिया में परिषद को संबोधित करेंगे। भारत न्याय समिति का अध्यक्ष है। शृंगला की यात्रा तब हो रही है जब भारत अगले महीने 15 देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहा है।

जयपुर फुट यूएसए और ग्रेसियस गिवर्स फाउंडेशन यूएसए द्वारा शहर में उनके लिए आयोजित एक स्वागत समारोह में शृंगला ने कहा कि यूएन में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और आतंकवाद के क्षेत्रों में नए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहल की है। भारत की वर्तमान अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति का संचालन करता है।

शृंगला ने कोरोना संक्रमण के बारे में कहा कि भारत ने कई देशों की मदद की है और दुनिया भर के देशों को 6.6 करोड़ से अधिक टीके वितरित किए हैं और 150 से अधिक देशों में कोविड-19 के साथ हस्तक्षेप करने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और इसके प्रमुख दवा उत्पाद प्रदान किए हैं।

अमेरिका में फिर बढ़ने लगे कोरोना के केस

▸ डेल्टा वैरिएंट और सुस्त टीकाकरण के कारण नए मामलों में बढ़ोतरी



वाशिंगटन, एपी : कोरोना महामारी की दो लहरों का सामना कर चुके अमेरिका में फिर दैनिक मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले तीन हफ्ते से नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। डेल्टा वैरिएंट के प्रसार, सुस्त टीकाकरण अभियान और गत चार जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में हुए जमावड़ों के कारण नए मामलों में बढ़ोतरी बताई जा रही है।

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के डाटा के अनुसार, अमेरिका में औसत दैनिक मामले सोमवार को बढ़कर 23 हजार 600 हो गए। गत 23 जून को यह संख्या महज 11 हजार 300 थी। समाचार एजेंसी आइएएनएस की खबर के मुताबिक, अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले लॉस एंजिलिस काउंटी में एक महीने में नए मामलों में 500 फीसद की वृद्धि हुई है। यहां बीते 24 घंटे में 1,103 नए पॉजिटिव केस पाए गए। यह लगातार पांचवां दिन है, जब एक हजार से अधिक नए संक्रमित मिले। इधर, अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन के मुताबिक, 55.6 फीसद अमेरिकियों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है।

रूस : देशभर में बीते 24 घंटे में 25 हजार 293 नए मामले पाए गए और 791 पीड़ितों की मौत हो गई। यहां भी डेल्टा वैरिएंट का कहर बढ़ रहा है।

पाकिस्तान : कोरोना संक्रमण की दर बढ़ने लगी है। यहां गुरुवार को 48 हजार 910 कोरोना टेस्ट किए गए और इनमें से 2,545 पॉजिटिव पाए गए हैं।

ब्राजील : देश में 57 हजार 736 नए संक्रमित मिले और 1,556 पीड़ितों की मौत हुई। एक दिन पहले 45 हजार नए केस मिले थे और 1,605 मौत हुई थी।

महामारी की तीसरी लहर के प्रारंभिक दौर में दुनिया

जेनेवा, एएनआइ : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर दुनिया को आगाह किया है। कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के बढ़ते कहर के बीच उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्य से हम अब तीसरी लहर के प्रारंभिक दौर में हैं।'

टेड्रोस ने कहा कि सामाजिक गतिविधियों के बढ़ने और रोकथाम के उपायों के असंगत उपयोग के चलते डेल्टा वैरिएंट के पांव पसारने के साथ ही नए मामलों और मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बताया, 'डेल्टा वैरिएंट अब 111 देशों में पहुंच गया है और जल्द ही पूरी दुनिया में हावी हो सकता है।' टेड्रोस ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की अपील करते हुए दोहराया कि हर देश में सितंबर तक दस फीसद आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाना चाहिए। जबकि साल के आखिर तक 40 फीसद आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग जानी चाहिए।

अमेरिका पर साइबर हमला करने वाला रूसी रैंसमवेयर ग्रुप रेविल हुआ गायब

न्यूयॉर्क टाइम्स से

▸ बाइडन की पुतिन से वार्ता के कुछ दिन बाद हो गया है निष्क्रिय


बढ़ रहे हैं साइबर हमले के मामले। फाइल फोटो/ इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन : अमेरिका में लगातार रैंसमवेयर हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन वार्ता का असर दिखाई दिया है। अमेरिका पर हमले करने वाला रूसी रैंसमवेयर ग्रुप रेविल गायब हो गया है।

अमेरिका में एक के बाद एक साइबर हमले हो रहे थे, जिनमें सैकड़ों कंपनियों के नेटवर्क शिकार हुए थे। ताजा हमला मांस उत्पादक कंपनी जेबीएस पर किया गया, जिसमें एक करोड़ 10 लाख डालर (करीब 82 करोड़ रुपये) की फिरौती मांगी गई थी। घटना के संबंध में जो बाइडन ने पुतिन से टेलीफोन पर वार्ता के दौरान अपनी गंभीर नाराजगी जताई। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इस दौरान रैंसमवेयर हमला करने वाले ग्रुप रेविल की भी पूरी जानकारी रूस को दे दी। रैंसमवेयर ईविल का संक्षिप्त नाम रेविल है। बाइडन की पुतिन से वार्ता के कुछ दिनों के बाद रेविल ग्रुप निष्क्रिय हो गया है। डार्क वेब पर इस ग्रुप की साइट अचानक गायब हो गई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि यह सब कैसे और किसने किया। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या रेविल की गतिविधियां दोबारा शुरू हो सकती हैं या नहीं। विशेषज्ञों को आशंका है कि इस समूह के रैंसमवेयर हमलावर फिर किसी अन्य नाम से सक्रिय हो सकते हैं। रेविल के फिलहाल बंद होने के बाद बाइडन और पुतिन को यह कहने का मौका जरूर मिला है कि वे समस्या के समाधान में लगे हुए हैं।

रैंसमवेयर हमलावरों की जानकारी देने पर एक करोड़ डालर का इनाम : एपी के अनुसार, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने साइबर हमलावरों की जानकारी देने वाले को एक करोड़ डालर (करीब 74 करोड़ रुपये) का इनाम देने की घोषणा की है। इसके लिए एक वेबसाइट स्टापरैंसमवेयर.जीओवी भी लांच की गई है।

दक्षिण अफ्रीका में हिंसा रोकने के लिए सेना की तैनाती शुरू

जोहानिसबर्ग, एपी : दक्षिण अफ्रीका की सेना ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के समर्थन में होने वाली हिंसा और उपद्रव की रोकथाम के लिए 25 हजार सैन्य बलों की तैनाती शुरू कर दी है।

वर्ष 1994 में श्वेतों की अल्पमत सरकार के समय से अब तक कि सबसे बड़ी सेना तैनात की गई थी। दक्षिणी अफ्रीकी नेशनल डिफेंस फोर्स ने तब 12 हजार सैन्य बलों को बुलाया था। दक्षिण अफ्रीका के ग्वातेंग और क्वाझुलु नाटल प्रांत में एक हफ्ते से जारी हिंसा को रोकने के लिए हथियारबंद ट्रक, बंदूकधारी और हेलीकाप्टर तैनात किए गए हैं। जोहानिसबर्ग समेत ग्वातेंग और क्वाझुलु नाटल इलाकों में इन सैन्य बलों की तैनाती होगी। हालांकि सात अन्य प्रांतों में भी हिंसा फैली हुई है। लेकिन पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। सोवेतु के मापोन्या मॉल में भी सैन्य बलों की तैनाती की गई है। इन प्रांतों में सैन्य बलों ने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है।

भारतीय प्रतिभा के कनाडा पलायन से अमेरिकी चिंतित

▸ 25 फीसद भारतीय छात्रों की भी घट गई है संख्या



विशेषज्ञों ने एच 1बी वीजा की पुरानी नीति को ठहराया जिम्मेदार। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारतीय प्रतिभाओं के दम पर पूरे विश्व में डंका बजा रहे अमेरिका की सरकार को विशेषज्ञों ने आगाह किया है। विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिका की पुरानी वीजा नीति के कारण भारतीय प्रतिभा अब अमेरिका के बजाए कनाडा जा रही है।

यह ऐसे समय में हो रहा है, जब अमेरिका चीन की बढ़ती लगातार ताकत से लड़ने के लिए प्रतिस्पर्द्धा को तेज करने का प्रयास कर रहा है।

विशेषज्ञों ने अमेरिकी संसद को वीजा नीति में परिवर्तन के लिए तेजी से कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से एच 1बी वीजा और देशों के कोटा निर्धारण को लेकर तत्काल नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। यदि वीजा नियमों में ग्रीन कार्ड और स्थायी निवास की सहूलियतों को आसान नहीं किया गया तो बेहतरीन भारतीय प्रतिभा से अमेरिका को वंचित होना पड़ेगा।

नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पालिसी के स्टुअर्ट एंडरसन ने चेतावनी दी है कि भारतीय पेशेवरों के लिए रोजगार आधारित श्रेणियों में वीजा का बैकलाग नौ लाख से ज्यादा है। 2030 तक यह संख्या 21 लाख से ज्यादा हो जाएगी।

एंडरसन ने सीनेट की आव्रजन संबंधी समिति के सामने ये आंकड़े पेश करते हुए कहा कि यदि अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों को नहीं बदला तो भारतीय प्रतिभा का कनाडा के लिए पलायन और तेज हो जाएगा।

यही नहीं पेशेवरों के अतिरिक्त अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के दाखिला लेने में भी कमी आ रही है। आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 से 2018-19 के बीच के शिक्षा सत्र में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 25 फीसद भारतीय छात्रों में कमी आई है।

पाक में हुए बस धमाके की जांच के लिए चीन भेजेगा जांच दल

बीजिंग, प्रेट्र: चीन ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान में बस हादसे की जांच में चीन का विशेष दल भी शामिल होगा। चूंकि इसमें चीन के इंजीनियरों की भी मौत हुई थी। इस बात की जांच चल रही है कि यह आतंकी हमला था या फिर कोई गैस विस्फोट के कारण हादसा हुआ था।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन सरकार पाकिस्तान में एक संयुक्त कार्यबल समूह भेज रही है, जो कामकाज की समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा, पाक में चीनियों की मौत से सरकार को झटका लगा है। कम्युनिस्ट पार्टी आफ चाइना (सीपीसी) और चीनी सरकार ने इस घटना पर विशेष तौर पर गौर किया है। वैसे भी चीन इस घटना को बम ब्लास्ट मानकर चल रहा है और अपने बयानों में यही दोहरा भी रहा है। जबकि पाकिस्तान विस्फोट की वजह को गैस लीक बता रहा है। यानी उसके हिसाब से यह एक हादसा था। खैबर पख्तूनवा प्रांत के ऊपरी कोहिस्तान जिले में दासु क्षेत्र में बन रहे एक बांध में काम करने वाले चीनी इंजीनियर मारे गए थे। बस में धमाके के बाद उसके खाई में गिरने पर 13 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें नौ चीनी नागरिक थे।

चुनावी पर्चे पर पीएम मोदी-जानसन की तस्वीर को लेकर ब्रिटेन संसद में तकरार

▸ पीएम जानसन ने पर्चे को नस्ली बताते हुए लेबर पार्टी से वापस लेने को कहा, भारतीय समुदाय ने भी की निंदा

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जानसन व विपक्षी नेता कीर स्टारमर के बीच उपचुनाव के एक पर्चे को लेकर हाउस आफ कामंस (निचले सदन) में तकरार हो गई। भारतीय समुदाय ने इस पर्चे को 'विभाजनकारी' व 'भारत विरोधी' करार दिया है।

प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाले प्रश्न (पीएमक्यू) सत्र के दौरान नस्लवाद के मुद्दे पर तीखी बहस हुई। जानसन ने उस पर्चे को हाथ में लिया था, जिसमें वर्ष 2019 के जी-7 सम्मेलन के दौरान वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इस पर्चे पर एक संदेश लिखा है, 'टोरी सांसद का खतरा न लें, क्योंकि वह आपके पक्ष में नहीं है।' टोरी शब्द का प्रयोग कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के लिए किया जाता है। जानसन ने लेबर पार्टी के नेता से मांग की कि वे पर्चों को वापस लें जिनका इस्तेमाल हाल में उत्तर इंग्लैंड के बैटले एंड स्पेन सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान इस्तेमाल किया गया था। यहां विपक्षी पार्टी को जीत मिली है। जानसन ने कहा, 'इस पर्चे को खुद लेबर पार्टी के नेताओं ने नस्ली करार देते हुए निंदा की थी।'

हालांकि, लेबर पार्टी के नेता इंग्लैंड के फुटबाल खिलाड़ियों द्वारा मैदान में झेले जाने वाले नस्ली दुर्व्यवहार का सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा विरोध नहीं किए जाने के मुद्दे पर अड़े दिखाई दिए। स्टारमर ने इस मुद्दे पर खासतौर पर गृहमंत्री प्रीति पटेल का संदर्भ दिया।

ब्रिटेन में रहने वाले उद्यमी व प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव अभियान दल के पूर्व सदस्य प्रोफसर मनोज लाडवा ने ट्वीट किया, 'यह बहुत ही निराशाजनक व परेशान करने वाला है कि लेबर नेता कीर स्टारमर ने उनकी पार्टी द्वारा हाल में संपन्न उपचुनाव के दौरान छपवाए नस्ली व भारत विरोधी पर्चे की निंदा करने से इन्कार कर दिया।' भारतीय मूल के सांसद निवेंदु मिश्र ने भी ट्विटर के जरिये विरोध दर्ज कराते हुए लिखा, 'नस्लवाद जिंदा है और वह भी लेबर पार्टी के भीतर।'

बता दें कि ओवरसीज फ्रेंड्स आफ बीजेपी (ओएफबीजेपी) समूह ने भी पर्चे का विरोध जताया था। यहां तक कि लेबर फ्रेंड्स आफ इंडिया (एलएफआइएन) समूह ने भी तत्काल इस पर्चे को वापस लेने की मांग की थी।

कोलंबो में एक और एंक्लेव बना रहा है चीन

कोलंबो, एएनआइ: चीन सामरिक मजबूती प्राप्त करने और भारत को घेरने के लिए श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी (सीपीसी) के माध्यम से पैठ बनाने में लगा है। अब उसने सीपीसी के साथ ही एक और एंक्लेव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है।

भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है कि देश के दक्षिणी छोर के कुछ सौ किमी. पर ही चीन की योजनाएं चल रही हैं। श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह को पहले ही चीनी कंपनियों को 99 साल की लीज पर दे दिया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाह बनाकर चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। यहां पर 269 हेक्टेयर में विशेष आर्थिक जोन बनाने की योजना चल रही है। इसके लिए राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने संसद में विशेष कानून पारित किया था। इस योजना पर अमल 2014 में शुरू किया गया था। ज्ञात हो राजपक्षे भाई (राष्ट्रपति गोटाबाया और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे) चीन के लंबे समय से मित्र हैं।

अमेरिका में धू-धू कर जल रहा जंगल


अमेरिका के ओरेगन के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। मंजर इतना भयानक है कि आसपास रहने वाले हजारों लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। इसके चलते लगभग दो हजार घरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। आग से अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। सरकारी स्तर पर आग पर काबू पाने के हर प्रयास किए जा रहे हैं, जो फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। रायटर

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 16 जुलाई, 2021

स्पोर्ट्स

www.jagran.com



मुझे ओलिंपिक की तैयारी करने का पर्याप्त समय मिला जिससे मैं और बेहतर खिलाड़ी बन सकी।
— पीवी सिंधू, बैडमिंटन खिलाड़ी, भारत

अपने करियर के शिखर पर हूं : शरत कमल

नई दिल्ली : 39 वर्षीय शरत कमल ने सोचा था कि टोक्यो उनका चौथा व अंतिम ओलिंपिक होगा लेकिन अपने दो दशक के करियर में उन्होंने अब से पहले इतना फिट व बेहतर महसूस नहीं किया जिससे यह टेबल टेनिस खिलाड़ी भविष्य की योजना पर फिर से विचार कर रहा है। दुनिया के 32वें नंबर के खिलाड़ी कमल ने कहा कि वह इस समय खुद को अपने खेल के शिखर पर देखते हैं।



बिजनेसमैन के घर में रुके पंत हुए पाजिटिव

एक सहयोगी स्टाफ को भी कोरोना, तीन खिलाड़ी क्वारंटाइन, क्या कर रही थी एंटी करप्शन यूनिट

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

इंग्लैंड दौरे पर चार अगस्त से शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जिसके चलते युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत कोरोना पाजिटिव हो गए हैं। पंत के अलावा थ्रोडाउन विशेषज्ञ दयानंद गिरानी भी पाजिटिव पाए गए हैं। साथ ही गेंदबाजी कोच भरत अरुण, सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और स्टैंडबाई ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन को आठ दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया गया है, क्योंकि ये तीनों दयानंद के संपर्क में आए थे।

भारतीय टीम से जुड़े सूत्र के मुताबिक, पंत ने हल्के बुखार के बाद परीक्षण कराया था, जिसमें वह पाजिटिव पाए गए। पंत साउथ हाल ट्रैवल्स कंपनी के मालिक कुलजिंदर बहिया की मेहमाननवाजी में उनके घर में रह रहे थे। इस दौरान काफी लोगों से उनका मिलना-जुलना हुआ। वह उनके बेटे कनवीर के साथ 29 जून को इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुए यूरो कप का मैच देखने भी गए थे। पंत फिलहाल बहिया के घर पर ही क्वारंटाइन हैं। उनका कुछ दिनों बाद फिर से परीक्षण होगा, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह भारतीय टीम के साथ कब जुड़ेंगे। दूसरी ओर दयानंद, अरुण, साहा और ईश्वरन लंदन में ही क्वारंटाइन में हैं।

बीसीसीआइ के एक पदाधिकारी ने एंटी करप्शन यूनिट के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी को एक महीने की छूट दी गई थी। अधिकतर खिलाड़ी होटल में रुके थे। पंत एक बिजनेसमैन की मेहमाननवाजी में रुके थे। एक बिजनेसमैन के यहां रुकना और उसके बाद जब दौरा शुरू होना है तो उस पर एंटी करप्शन यूनिट को भी ध्यान देना चाहिए था। आखिर बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट क्या कर रही थी? मालूम हो कि कुलजिंदर बहिया पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के दोस्त रहे हैं और धौनी ने ही पंत को उनसे मिलवाया था। टीम इंडिया के कई खिलाड़ी उनके दोस्त हैं।

पंत के पाजिटिव होने और साहा के क्वारंटाइन होने से अब यह स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों 20 जुलाई से डरहम में होने वाले संयुक्त काउंटी टीम के खिलाफ अभ्यास मैच नहीं खेल सकेंगे। ऐसे में केएल राहुल के इस मैच में विकेटकीपर की भूमिका निभाने की उम्मीद है।

इस अभ्यास मैच के लिए भारतीय टीम पंत, दयानंद, साहा, अरुण, ईश्वरन और चोटिल शुभमन गिल को छोड़कर गुरुवार को डरहम रवाना हो गई। गिल को इस महीने की शुरुआत में पैर में चोट लगी थी और यह युवा बल्लेबाज टीम के बायो-बबल (कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित माहौल) से बाहर आ चुका है।

इससे पहले बीसीसीआइ सचिव जय शाह ने भी इंग्लैंड में मौजूद भारतीय दल को हाल में ईमेल भेजकर वहां कोविड-19 के बढ़ते मामलों के प्रति चेताया था। शाह ने भारतीय दल से भीड़ वाले इलाकों में, खासकर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप और यूरो कप में जाने से बचने को कहा था। समझा जा रहा है कि पंत वायरस के डेल्टा प्रकार से संक्रमित हैं, जिसके कारण इंग्लैंड में संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है।



यूरो कप मैच के दौरान कुलजिंदर बहिया के बेटे कनवीर के साथ पंत • फाइल फोटो, ट्विटर

भारतीय टीम प्रबंधन ने मांगे अतिरिक्त खिलाड़ी

पंत के पाजिटिव आने के बाद भारतीय टीम प्रबंधन ने बीसीसीआइ के चयन प्रमुख से चर्चा की। इस दौरान टीम प्रबंधन ने कुछ अतिरिक्त खिलाड़ियों को इंग्लैंड भेजने का अनुरोध किया है। मालूम हो कि गिल के चोटिल होने के बाद भी टीम प्रबंधन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर पृथ्वी शा और देवदत्त पडीक्कल को इंग्लैंड भेजे जाने की मांग की थी, जो फिलहाल शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम के साथ श्रीलंका दौरे पर हैं। टीम में पहले से ही वैकल्पिक ओपनर होने की वजह से टीम प्रबंधन की इस मांग को चयन समिति ने कोई तवज्जो नहीं दी थी।

भारत के खिलाफ अभ्यास मैच में सिलेक्ट काउंटी टीम की कप्तानी करेंगे रोड्स

डरहम, प्रेट्र : वारविकशायर के कप्तान विलफ्रेड रोड्स भारत के खिलाफ 20 से 22 जुलाई तक होने वाले तीन दिवसीय अभ्यास मैच में 14 सदस्यीय काउंटी एकादश की कप्तानी करेंगे। ईसीबी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज और यंग लायंस के मौजूदा मुख्य कोच रिचर्ड डासन मेजबान टीम के कोच होंगे। मैच दर्शकों के बिना खेला जाएगा। सिलेक्ट काउंटी टीम में नाटिंघमशायर के सलामी बल्लेबाज हसीब हामिद भी हैं, जिन्होंने 2016 में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। ईसीबी इस मैच के लिए एक छोटा बायो-बबल बनाएगा व सारे चयनित खिलाड़ियों की कोरोना जांच होगी। मैच डरहम काउंटी क्रिकेट क्लब के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकेगा।

टीम इंडिया ने शुरू किया फ्लड लाइट्स में अभ्यास



अभ्यास सत्र के दौरान चर्चा करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी • ट्विटर

कोलंबो, एएनआइ : शिखर धवन की कप्तानी वाली भारत की सीमित ओवरों की टीम ने गुरुवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में अपना पहला अभ्यास सत्र शुरू किया। बीसीसीआइ ने इसकी तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर साझा की।

बीसीसीआइ ने तस्वीर के साथ लिखा, 'नेट्स हिट करने का समय, फ्लड लाइट्स में हमारा पहला अभ्यास सत्र अब शुरू हुआ।'

अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विश्व कप से पहले भारत की यह आखिरी सीमित ओवरों की सीरीज होगी। टीम में चेतन सकारिया, के गौतम, नीतीश राणा, देवदत्त पडीक्कल, वरुण चक्रवर्ती और रुतुराज गायकवाड़ के रूप में छह खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव नहीं है।

द्रविड़ से सीखना चाहते हैं देवदत्त, सकारिया व राणा

नई दिल्ली : नई दिल्ली, प्रेट्र : श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम तीन वनडे और इतने ही टी-20 मुकाबले खेलेगी, लेकिन देवदत्त पडीक्कल, नीतीश राणा और चेतन सकारिया कोच राहुल द्रविड़ से सीखने को उत्सुक हैं। पडीक्कल ने कहा, उम्मीद करता हूं कि मैं उनसे काफी कुछ सीख पाऊंगा। राणा ने कहा, उनमें जितना धैर्य है मैं उसका एक प्रतिशत भी अपने अंदर ला पाऊं। सकारिया ने कहा, मैं सीखना चाहता हूं कि विरोधी टीमें दबदबा बनाती तो वह कैसे प्रतिबद्ध रहते थे।

सौरव की बायोपिक से सामने आएगा चैपल से जुड़ा विवाद

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता : टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व मौजूदा बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली की बायोपिक में टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल के साथ उनके विवाद पर कई अहम रहस्योद्घाटन होंगे। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिल्म की स्क्रिप्ट में सौरव के क्रिकेट जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना पर प्रमुखता से काम चल रहा है। इसे लेकर आने वाले दिनों में सौरव के साथ कई बार बातचीत भी की जाएगी। यह भी पता चला है कि फिल्म के शीर्षक के तौर पर सौरव, दादा और प्रिंस आफ कलकत्ता जैसे नामों पर विचार किया जा रहा है।

1996 में इंग्लैंड दौरे पर गई भारतीय टीम में सौरव के चयन के समय पूर्वी क्षेत्र से राष्ट्रीय चयनकर्ता रहे संबरन बनर्जी ने कहा, सौरव-चैपल प्रकरण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बड़े विवादों में से एक है। फिल्म में इसे प्रमुखता से दिखाया जाना तय है। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मुझसे संपर्क किया गया है। फिल्म में मेरा रोल मुझसे खुद करने का अनुरोध किया गया है। सौरव-चैपल विवाद को लेकर मुझसे जब भी मेरा वर्जन देने को कहा जाएगा तो मैं जरूर दूंगा।' सौरव को बेहद करीब से जानने वाले बंगाल के पूर्व क्रिकेटर व ईडन गार्डेंस स्टेडियम के क्यूरेटर सुजान मुखर्जी ने कहा, 'सौरव-चैपल विवाद को लेकर बहुत सी कहानियां हैं। बायोपिक से सच सामने आएगा।'

टेनिस हाल आफ फेम में शामिल इर्विन का निधन

नेपल्स, एपी : टेनिस हाल आफ फेम में शामिल शर्ली फ्राई इर्विन का निधन हो गया। वह 94 वर्ष की थीं। शर्ली ने पिछली सदी के छठे दशक में लगातार तीन मेजर खिताब जीतकर करियर ग्रैंडस्लैम पूरा किया था।

अंतरराष्ट्रीय टेनिस हाल आफ फेम ने उनके निधन होने की पुष्टि की। शर्ली नेपल्स में रहती थीं और उन्हें 1970 में हाल आफ फेम में शामिल किया गया। शर्ली ने अपना पहला ग्रैंडस्लैम सिंगल्स खिताब 1951 में फ्रेंच ओपन में अपनी मित्र और डबल्स जोड़ीदार डोरिस हार्ट को हराकर जीता।

शर्ली ने 1956 में 28 वर्ष की उम्र में संन्यास से वापसी की जब उन्हें वेटमैन कप में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने इसके बाद उसी साल विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप तथा 1957 में आस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप के साथ लगातार तीन मेजर खिताब जीते और फिर संन्यास लिया।

शर्ली ने 13 ग्रैंडस्लैम डबल्स खिताब भी जीते। वह 1946 से 1956 तक 10 में से नौ बार साल के अंत में रैंकिंग में शीर्ष-10 में शामिल रहीं।



शर्ली फ्राई इर्विन • फाइल फोटो, ट्विटर

लगातार चौथी सीरीज हारी भारतीय महिला टीम

चेम्सफोर्ड, प्रेट्र : सलामी बल्लेबाज डैनी वायट की 56 गेंद में नाबाद 89 रन की पारी की बदौलत इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को देर रात हुए तीसरे और अंतिम टी-20 मैच में भारत को आठ विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली।

इस तरह भारतीय टीम मिताली राज और हरमनप्रीत कौर की अगुआई में सीमित ओवरों की लगातार चार सीरीज गंवा चुकी है। इससे पहले स्वदेश में उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी-20 दोनों सीरीज गंवाई थी। भारत ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना की 70 रन की पारी से छह विकेट पर 153 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

मंधाना ने 51 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के मारे। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत (26 गेंद में 36 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी भी की। युवा रिचा घोष ने भी 13 गेंद में 20 रन बनाकर टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया।

आस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराया

ग्रोइस आइलेट (सेंट लूसिया), एपी : मिशेल मार्श की 75 रन की पारी और तीन विकेट के बाद अंतिम ओवर में तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की शानदार गेंदबाजी से आस्ट्रेलिया ने चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में चार रन की जीत के साथ वेस्टइंडीज के जीत के क्रम को तोड़ दिया।

वेस्टइंडीज की टीम पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है और बुधवार को लगातार चौथा मैच जीतने के भी बेहद करीब थी। टीम को अंतिम ओवर में 11 रन की दरकार थी लेकिन, स्टार्क ने लगातार पांच गेंद खाली फेंकी और फिर अंतिम गेंद पर छक्का पड़ा जिससे आस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज की टीम 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए छह विकेट पर 185 रन ही बना सकी।

आस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दो बार बारिश के खलल के बीच छह विकेट पर 189 रन का स्कोर खड़ा किया। मार्श ने 44 गेंद में 75 रन की पारी खेली और सीरीज में तीसरा अर्धशतक जड़ा। उन्होंने कप्तान आरोन फिंच (53) के साथ दूसरे विकेट के लिए 114 रन जोड़े। जवाब में लेंडल सिमंस और एविन लुइस ने 4.5 ओवर में 62 रन जोड़कर वेस्टइंडीज को तूफानी शुरुआत दिलाई। कलाई के स्पिनर एडम जांपा ने लुइस को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा। लुइस ने 14 गेंद में 31 रन बनाए। मार्श ने इसके बाद क्रिस गेल (01) को पवेलियन भेजा। मार्श ने 16वें ओवर में निकोलस पूरन (16) और सिमंस (48 गेंद में 72 रन) को लगातार गेंदों पर आउट कर आस्ट्रेलिया की जीत की राह बनाई। वेस्टइंडीज को अंतिम दो ओवर में 36 रन की दरकार थी। एंड्रयू रसेल (नाबाद 24) और फाबियन एलेन (29) ने रिली मेरेडिथ के 19वें ओवर में 25 रन बटोरे।

आनंद ने स्पार्कसन ट्राफी में जीत के साथ की शुरुआत

डोर्टमंड : पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने यहां स्पार्कसन ट्राफी के लिए चार बाजियों के मुकाबले की पहली बाजी में रूस के ग्रैंडमास्टर व्लादिमीर क्रैमनिक को हराया। आनंद ने बुधवार को सफेद मोहरों से खेलते हुए क्रैमनिक को 66 चाल में शिकस्त दी। यह मुकाबला नो-कास्लिंग शतरंज का हिस्सा है जिससे रूस के ग्रैंडमास्टर ने तैयार किया है। खेल को और अधिक रोचक बनाने के लिए इस प्रारूप में कास्लिंग की स्वीकृति नहीं है। कास्लिंग शतरंज में एक विशेष चाल होती है जिसमें राजा को बचाया जाता है और हाथी को मुकाबले के लिए आगे किया जाता है। यह एकमात्र समय होता है जब खिलाड़ी एक चाल में दो मोहरों को हिला सकता है।

141 समलैंगिक एथलीट ओलिंपिक में लेंगे भाग

जागरण न्यूज नेटवर्क : टोक्यो ओलंपिक में कम से कम 141 सार्वजनिक रूप से समलैंगिक (एलजीबीटीक्यू) समुदाय के एथलीट भाग लेंगे। इनमें गे, लेस्बियन, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर और गैर-बाइनरी एथलीट शामिल हैं, जो कि ओलिंपिक इतिहास में एक रिकार्ड संख्या है। टोक्यो में इन एथलीटों की संख्या पिछले 2016 रियो ओलंपिक की तुलना में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या के दोगुने से अधिक है। रियो में कुल 56 तो उससे पहले 2012 लंदन ओलिंपिक में कुल 23 समलैंगिक एथलीटों ने भाग लिया था।

इन एथलीटों में अभी तक सबसे ज्यादा 30 एथलीट अमेरिका से हैं, जबकि कनाडा (16), ब्रिटेन (15), नीदरलैंड्स (13), न्यूजीलैंड (9), आस्ट्रेलिया (9) और ब्राजील से आठ एथलीट भाग ले रहे हैं। इस सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों से लगभग 8-1 के अंतर से अधिक है, जिसमें महिला फुटबाल में 30 से अधिक खिलाड़ी हैं शामिल हैं। इसमें और भी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने अभी तक अपने इस समुदाय में आने का अधिकारिक एलान नहीं किया है और वह ओलिंपिक में भाग ले रहे हैं।

इस बार सबसे ज्यादा समलैंगिक एथलीट अमेरिका के होंगे, रियो में 56 व लंदन में 23 समलैंगिक एथलीटों ने लिया था भाग

नेत्रा और विष्णु की नौकाएं ओलिंपिक के लिए टोक्यो पहुंचीं

ओलिंपिक डायरी

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय सेलर विष्णु सरवनन और नेत्रा कुमानन को गुरुवार को अपनी नौकाएं मिल गईं जिसका इस्तेमाल वे 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलिंपिक की लेजर क्लास स्पर्धा के दौरान करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने हानेडा हवाई अड्डे पर पहुंची नौकाओं की फोटो जारी की।

नेत्रा लेजर रेडियल स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। वह स्पेन में ट्रेनिंग में जुटी थीं। वहीं, लेजर स्टैंडर्ड क्लास में हिस्सा लेने वाले विष्णु माल्टा में अपनी तैयारियां कर रहे थे। ये दोनों और वरुण ठक्कर और गणपति चेंगप्पा की जोड़ी मंगलवार को टोक्यो पहुंचने वाले देश के पहले खिलाड़ी थे। इतिहास में पहली बार रिकार्ड चार सेलर ओलिंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहली बार देश तीन स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। नौकायन स्पर्धायें 25 जुलाई से शुरू होंगी।

नरेंद्र बत्रा ने कहा , टोक्यो में भारतीय अधिकारी इंतजामों से खुश : भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने गुरुवार को कहा कि टोक्यो पहुंचे आइओए अधिकारियों को सुविधाएं बहुत अच्छी लगी हैं।

बत्रा ने कहा, 'भारत के दल प्रमुख बी पी बैश्य, उप दल प्रमुख और कोविड संपर्क अधिकारी डा. प्रेम वर्मा, दल के डाक्टर अरुण बासिल और आइओए के संयुक्त निदेशक जार्ज 14 जुलाई को खेल गांव पहुंच गए। उप दल प्रमुख द्वारा सूचित किया गया कि खेल गांव में रहने के इंतजाम काफी अच्छे हैं और डाइनिंग हाल का मुद्दा भी निपटा लिया गया है।'



ओलिंपिक के लिए टोक्यो पहुंची अपनी नौका के साथ नेत्रा कुमानन • साई

याजदानी से भिड़ता है दीपक तो अलग होगा मैच : कोच विरेंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : दीपक पूनिया के कोच विरेंद्र कुमार का मानना है कि अगर ओलिंपिक के ड्रा में दीपक का सामना फिर से ईरान के हसन याजदानी से होता है तो यह मैच देखने वाला होगा। विरेंद्र ने कहा, 'आप जिस पहलवान को आदर्श मानते हुए बड़े हुए हो और उसे अपने सामने पाकर घबराना लाजमी है। अगर दीपक को उससे भिड़ने का मौका मिलता है तो वह पूरी तरह तैयार होगा।

उद्घाटन में 1000 से कम अतिथि होंगे शामिल

टोक्यो, प्रेट्र : टोक्यो ओलिंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान स्टेडियम में एक हजार से भी कम अति विशिष्ट अतिथियों और विदेशी प्रतिनिधियों के मौजूद रहने की संभावना है। इससे पहले 10 हजार लोगों को प्रवेश देने का फैसला किया गया था लेकिन, यहां कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण इस संख्या में भारी कटौती की गई है। जापान की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट ने खबर दी कि आयोजक 23 जुलाई को राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले समारोह के दौरान वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या में कटौती का प्रयास कर रहे हैं।

एशिया में पहला महाकुंभ



1964 के टोक्यो ओलिंपिक खेलों की मशाल को प्रज्ज्वलित करने का सम्मान योशिनोरी सकाई को मिला। हिरोशिमा पर परमाणु बम विस्फोट के दिन (छह अगस्त, 1945) इनका जन्म हुआ था।

टोक्यो ओलिंपिक (1964)

TOKYO 1964

10 अक्टूबर से 24 अक्टूबर

5151 एथलीट | 93 देश | 19 खेल 163 मुकाबले

इस ओलिंपिक खेलों में पहली बार दो नई खेल स्पर्धाओं जूडो (पुरुष) और वालीबाल (पुरुष और महिलाएं) को शामिल किया गया था।



तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	36	90
सोवियत संघ	30	96
जापान	16	29
जर्मनी	10	22
इटली	10	27

जापान को सम्मान

जापान इस तरह का आयोजन करके दुनिया को अपनी क्षमता से वाकिफ कराना चाहता था। इसकी सफलता ने अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति द्वारा उसे तीन पुरस्कार (ओलंपिक कप, बोनाकोसा ट्राफी और डिप्लोमा आफ मेरिट) प्रदान किया गया।

खेल भावना का सम्मान

स्वीडन के याचमैन लार्स गुन्नार काल और स्टिग लेनार्ट काल टोक्यो ट्राफी हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। साथी खिलाड़ी की जान बचाने के लिए रेस छोड़कर उन्होंने खेल भावना का अद्वितीय परिचय दिया था।

खिलाड़ियों के खिलाड़ी

इथियोपिया के अबेबे बिकिला दूसरी बार मैराथन जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। सोवियत जिम्नास्ट लैरियासा लैतिनिना ने अपने करियर के कुल 18 पदक पूरे किए। ग्रीको-रोमन कुश्ती में इमरे पोलयाक ने ओलिंपिक में चौथा स्वर्ण पदक हासिल किया।

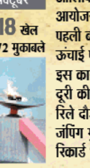
भारतीय प्रदर्शन : शुरू से ही लय में दिख रही टीम ने सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया को 3-1 से मात दी। फाइनल में भारतीय टीम ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराकर फिर से पीला तमगा जीता।

मैक्सिको ओलिंपिक (1968)

12 अक्टूबर से 27 अक्टूबर

5516 एथलीट | 112 देश | 18 खेल 172 मुकाबले





ओलिंपिक का आयोजन पर पहली बार रिकार्ड ऊंचाई पर हुआ। इस कारण कम दूरी की दौड़, रिले दौड़ और जंपिंग मुकाबलों में रिकार्ड भी बने।

तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
अमेरिका	45	107
सोवियत संघ	29	91
जापान	11	25
हंगरी	10	32
जर्मनी	09	25

नस्लवाद का विरोध

मानवाधिकारों के हनन का विरोध करते हुए अफ्रीकी अमेरिकी खिलाड़ी टामी स्मिथ और जान कार्लोस ने ब्लैक पावर को सैल्यूट किया। उन्होंने बिना जूता पहने अपना पदक स्वीकार किया। काला दस्ताना पहनकर उन लोगों ने काले लोगों में गरीबी और नस्लवाद के खिलाफ विरोध जताया। आइओसी ने इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया।

रिकार्डों की लगी झड़ी : अमेरिकी खिलाड़ी बाब बीमन ने लंबी कूद में 8.9 मीटर का रिकार्ड बनाया। यह पुराने कीर्तिमान से 55 सेमी ज्यादा था। अगले 23 वर्ष तक यह विश्व रिकार्ड कायम रहा। अमेरिकी एथलीट जिम हाइंस और ली इवांस ने भी क्रमश: सौ मीटर और चार सौ मीटर दौड़ में रिकार्ड बनाए जो काफी समय बने रहे।

भारतीय प्रदर्शन : हाकी टीम को इस ओलिंपिक में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इस बार पीला तमगा पाकिस्तान ने हासिल किया। आस्ट्रेलियाई टीम के खाते में रजत आया। भारत ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में जर्मनी को 2-1 से पराजित कर कांसा जीता।

ओलिंपिक पर आतंकी साया

आतंकी कार्रवाई के कारण पहली बार ओलिंपिक की खेल भावना को धक्का लगा। इजरायल-फलस्तीन विवाद की काली छाया म्यूनिख ओलिंपिक (1972) पर पड़ती देखी गई। लिहाजा भाईचारे और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला ओलिंपिक खेल रक्तरंजित हुआ।



म्यूनिख ओलिंपिक (1972)

Munich 1972

26 अगस्त-10 सितंबर

7134 एथलीट | 121 देश | 21 खेल 195 मुकाबले



पश्चिमी जर्मनी की लाइसलॉट लिंसेनहॉफ घुड़सवारी में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनीं।

आतंकी हमला

पांच सितंबर को फलस्तीनी आतंकी समूह ब्लैक सितंबर के आठ आतंकी ओलिंपिक गांव में घुस गए। उन्होंने इजरायली खिलाड़ियों को निशाना बनाते हुए दो को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा नौ इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। आतंकियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में पांच आतंकी मारे गए, लेकिन इस बीच आतंकियों ने सभी नौ बंधकों को मौत के घाट उतार दिया। एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। कुल मिलाकर इजरायल के 11 खिलाड़ी आतंकियों का शिकार बने



तालिका में शीर्ष पांच देश

देश	स्वर्ण	कुल पदक
सोवियत संघ	50	99
अमेरिका	33	94
पूर्वी जर्मनी	20	66
प. जर्मनी	13	40
जापान	13	29

शुरुआत

पुरुष इंडोर हैंडबाल, स्लेलम कैनोइंग और क्यकिंग स्पर्धाओं की ओलिंपिक में शुरुआत हुई। 52वर्षों के अंतराल के बाद तीरंदाजी की वापसी हुई। ओलिंपिक अधिकारियों को भी शपथ दिलाने की परंपरा शुरू हुई।

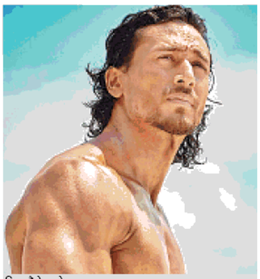
'द गेम्स मस्ट गो आन'

ओलिंपिक में आतंकी हमले से दुनिया हतप्रभ रह गई। अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) सकते में आ गई। खेल 34 घंटे के लिए रुक गया। खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य स्टेडियम में लोग उमड़ पड़े। आइओसी अध्यक्ष आवेरी ब्रंडेज ने आतंकियों के हौसले ध्वस्त करने के लिए आयोजन जारी रखने की घोषणा करते हुए प्रसिद्ध नारा दिया, 'द गेम्स मस्ट गो आन।'

दैनिक जागरण
सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021

जो हिट है वो बालीवुड में फिट है

सिने चर्चा


फिल्म रैंबो का पोस्टर


फिल्म लाल सिंह चड्ढा का पोस्टर


फिल्म धमाका का पोस्टर

बालीवुड में रीमेक फिल्में बनती रही हैं, पर इन दिनों इस ट्रेंड में काफी तेजी आई है। साउथ की सफल फिल्मों 'हिट', 'सूरराई पोटरु', 'सिंघम 3', 'यू टर्न', 'अला वैकुंठपुरमलो', 'दृश्यम 2', 'विक्रम वेधा', 'मास्टर', 'कैथी' इत्यादि की रीमेक बनाने की घोषणा हुई है, वहीं 'एज्रा', 'आरएक्स 100', 'जर्सी' सहित कई रीमेक फिल्में सिनेमाघरों के खुलने का इंतजार कर रही हैं। आमिर खान अभिनीत 'लाल सिंह चड्ढा', दीपिका पादुकोण की फिल्म 'द इंटर्न', टाइगर श्राफ की फिल्म 'रैंबो' हालीवुड फिल्मों की रीमेक होंगी। रीमेक में निर्माताओं की दिलचस्पी, इन्हें बनाने की चुनौतियों और बजट संबंधी पहलुओं की पड़ताल की स्मिता श्रीवास्तव व प्रियंका सिंह ने...

महबूब खान ने अपनी फिल्म 'औरत' की रीमेक 'मदर इंडिया' बनाई थी। 'मदर इंडिया' हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। हिंदी सिनेमा में जितेंद्र अकेले अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने पूरे करियर में करीब पांच दर्जन से अधिक रीमेक फिल्मों में काम किया। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श कहते हैं कि मनोरंजक फिल्मों की रीमेक बनती हैं, क्योंकि वे दर्शकों को सहज ही आकर्षित करती हैं। जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन ने कई रीमेक फिल्मों में काम किया है। अब वह दौर फिर से शुरू हुआ है, जहां साउथ की फिल्मों की हिंदी रीमेक बड़े पैमाने पर बन रही हैं। चाय सभी के घर में बनती है, लेकिन उसका स्वाद अलग होता है, क्योंकि बनाने का तरीका अलग होता है। उसी तरह एक ही कहानी को चार अलग फिल्ममेकर्स बनाएं तो फिल्म अलग बनती है। रीमेक फिल्म बनाना आजमाया हुआ फार्मूला रहा है। कोई फिल्म किसी रीजन में पसंद की गई है, इसलिए उसे रीमेक किया जाता है। पहले से मेकर्स तैयार होते हैं कि किस सीन में ताली बजेगी, किसमें ड्रामा होगा। 'लाल सिंह चड्ढा' हालीवुड फिल्म 'फारेस्ट गम्प' की आधिकारिक रीमेक है। करोड़ों लोगों ने 'फारेस्ट गम्प' फिल्म देखी है। रीमेक में आमिर खान क्या बदलाव लाएंगे, वह देखना दिलचस्प होगा।

मूल फिल्म से बेहतर बनाना चुनौती: तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का निर्देशन कर चुके संदीप रेड्डी वांगा ने उसकी हिंदी रीमेक 'कबीर सिंह' का भी निर्देशन किया था। वह कहते हैं कि जब आप फिल्मों को रीमेक करते हैं तो यह स्वाभाविक खयाल आता है कि लोग फिल्म एक बार देख चुके हैं, अब इसमें क्या नयापन लाऊं, लेकिन यह विचार प्री प्रोडक्शन तक ही रहते हैं। जैसे ही आप एक दूसरे कलाकार को कास्ट्यूम्स में उन इमोशंस को लाते हुए देखते हैं तो अपने आप ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। मन में यही खयाल रहता है कि मूल फिल्म के स्तर तक रीमेक को पहुंचाना है या उससे भी ऊपर ले जाना है। वह पैरामीटर हमेशा दिमाग में चलता रहता है।

हर भाषा में दर्शक चाहते हैं अपना कलाकार: मलयालम में बनी फिल्म 'दृश्यम' को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मंदारिन भाषा में रीमेक किया गया था। अलग-अलग भाषाओं में रीमेक की जरूरत को लेकर मूल फिल्म के अभिनेता मोहनलाल कहते हैं कि हर भाषा के दर्शक अपने हीरो को उस फिल्म में देखना चाहते हैं। मलयालम फिल्म में दर्शक मुझे देखना चाहेंगे, वैसे ही तमिल दर्शक 'दृश्यम 2' में कमल हासन को देखेंगे, तेलुगु दर्शक वेंकटेश को, कन्नड़ दर्शक रविचंद्रन और हिंदी के दर्शक अजय देवगन को ही देखना चाहेंगे। 'दृश्यम' के मुख्य किरदार को अलग भाषाओं में अलग कलाकारों ने निभाया है। उनके किरदारों के नाम भी अलग हैं। हर भाषा में इस फिल्म को सबने अपने स्टाइल से बनाया है। हिंदी कहानी में मैंने छोटे-छोटे बदलाव देखे थे, जो हिंदी भाषी दर्शकों के लिए सही थे। अजय देवगन की परफार्मेंस बहुत अच्छी थी। चाइनीज रीमेक में क्लाइमेक्स को बदल दिया गया है। वहां पर उन्होंने पुलिस के साथ खेलने की कोशिश नहीं की थी। महामारी के बाद भी वह फिल्म चीन में बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई थी। अब उन्होंने 'दृश्यम 2' के राइट्स मांगे हैं, जो हमारे लिए बड़ी बात है। कोरियन इसे अपनी भाषा में बनाना चाहते हैं। अगर फिल्म का विषय वैश्विक हो तो फिल्म की रीमेक बनाई जा सकती है।

दूसरी संस्कृति में फिल्म लगती है नई: मराठी फिल्म 'लपाछपी' और मलयालम फिल्म 'फारेंसिक' की हिंदी रीमेक का निर्देशन विशाल फुरिया कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जब किसी पुरानी फिल्म को उसी भाषा में रीमेक किया जाता है तो दौर का अंतर साफ नजर आता है, लेकिन जब किसी दूसरी भाषा की फिल्म को हिंदी में रीमेक किया जाता तो सीधे संस्कृति का अंतर हो जाता है। दूसरी भाषा में डबिंग का विकल्प हमेशा होता है, लेकिन जब कहानी को एक संस्कृति से निकालकर दूसरी संस्कृति में सेट किया जाता है तो उससे फिल्म नई दिखने लग जाती है। जैसे मैंने जब अमेरिकी शो 'क्रिमिनल जस्टिस' का रीमेक तैयार किया था तो उस कहानी को भारत में सेट करते ही वह अलग बन गई थी। 'फारेंसिक' और 'लपाछपी' की हिंदी रीमेक 'छोरी' फिल्म के साथ भी ऐसा ही होगा, जब वह फिल्म नए कल्चर में जाएगी तो अलग दिखेगी। रीमेक में जो सबसे जरूरी बात ध्यान में रखनी होती है, वह है कि फिल्म की आत्मा न बदल जाए। कई बार क्षेत्रीय भाषा वाली फिल्में सिर्फ एक ही राज्य तक बंधकर रह जाती हैं। जब फिल्मों को डब किया जाता है तो फिल्म का चार्म कम हो जाता है। अगर फिल्म को सही तरह से रीमेक किया जाए तो पैन इंडिया दर्शकों तक वह फिल्म पहुंचती है। हिंदी इंडस्ट्री की पहुंच ज्यादा है।

भारतीय दर्शकों के मुताबिक बदलाव: रीमेक करते वक्त भारतीय दर्शकों की पसंद और उनके टेस्ट का ध्यान भी रखना होता है। फिल्म 'लूप लपेटा' जर्मन फिल्म 'रन लोला रन' की आधिकारिक हिंदी रीमेक है। इस फिल्म के अभिनेता ताहिर राज भसीन का कहना है कि 'रन लोला रन' में रोमांस का इतना बड़ा हिस्सा नहीं था, जितना 'लूप लपेटा' में है। हिंदी फिल्मों में रोमांस पर खासा ध्यान दिया जाता है। 'रन लोला रन' में पीछा करने वाले कई दृश्य थे, लेकिन हिंदी रीमेक में इन दृश्यों के साथ प्यार वाला एंगल और केमिस्ट्री भी लानी थी, ताकि दर्शक उससे जुड़ पाएं। हालांकि कई बार निर्देशक रीमेक फिल्मों में दृश्यों को हूबहू शूट करते हैं। सुजाय घोष ने स्पेनिश फिल्म की रीमेक 'बदला' बनाई थी। 'बदला' और 'द इनविसिबल गेस्ट' के कई दृश्य एकसमान दिखने को लेकर उनका कहना था कि मैं अच्छी चीज के साथ छेड़छाड़ क्यों करूं।

हिट फार्मूला हैं रीमेक फिल्में: आने वाले दिनों में हिंदी में कई रीमेक फिल्में देखने को मिलेंगी। साउथ की फिल्मों की रीमेक बाक्स आफिस पर हिट फार्मूला साबित हुआ है। तमिल एक्शन फिल्म 'सिंघम 3' की हिंदी रीमेक बना रहे फिल्ममेकर गुड्डू धनोआ कहते हैं कि रीमेक के मुकाबले नई कहानियों को नई दिशा देना, नया संगीत बनाने में जो मजा है, वह संतुष्टि रीमेक फिल्में नहीं देती हैं, पर आजकल निर्माता बिजनेस माइंडेड हो गए हैं, इसलिए रीमेक फिल्में अधिक बन रही हैं। प्रमोशन में यह बात जरूर बताई जाती है कि यह फलां फिल्म की रीमेक है। इससे दर्शकों को फिल्म देखने का भरोसा आता है। मैं 'सिंघम 3' को रीमेक कर रहा हूं। हालांकि मेरी फिल्म के हीरो की एंट्री मूल फिल्म से अलग होगी, डिजिटल पोस्टर अलग होगा। 'सिंघम 3' सूर्या के साथ बनी थी, वह साउथ के बड़े स्टार हैं। हमारी फिल्म रीमेक है, लेकिन हम नए हीरो को लांच कर रहे हैं, इसलिए हमारा बजट मूल फिल्म से कम होगा।


हालीवुड की फिल्म 'द इंटर्न' की रीमेक में दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में होंगी।

रीमेक करने में अव्वल अजय देवगन



अजय देवगन को साउथ की फिल्मों के रीमेक का बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 'सिंघम' अभिनेता नौ रीमेक फिल्में कर चुके हैं। वह तमिल फिल्म 'कैथी', तेलुगु फिल्म 'नांधी' की हिंदी रीमेक बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इससे पहले वह साउथ की फिल्मों की रीमेक 'दृश्यम', 'एक्शन जैक्सन', 'हिम्मतवाला', 'सन आफ सरदार', 'सिंघम', 'संडे', 'गोलमाल- फन अनलिमिटेड', 'इंसान', 'युवा' कर चुके हैं, वहीं सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम', 'वांटेड', 'रेडी', 'बॉडीगार्ड', 'जय हो', 'गाड तुस्सी ग्रेट हो', 'किक' साउथ की रीमेक रही हैं। उनकी फिल्म 'राधे- योर मोस्ट वांटेड भाई' कोरियन फिल्म 'आउटलाज', जबकि 'भारत' 'ओड टू माई फादर' की रीमेक है। तमिल फिल्म 'मास्टर' की हिंदी रीमेक में सलमान खान के होने की खबरें हैं।

साउथ की फिल्मों की बनेंगी हिंदी रीमेक

- तेलुगु फिल्म 'हिट' की रीमेक में राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा होंगे।
- साल 2016 में बनी कन्नड़ फिल्म 'यू टर्न' की रीमेक बना रही हैं एकता कपूर। फिल्म में अलाया एफ होंगी।
- साल 2017 में रिलीज हुई तमिल एक्शन फिल्म 'सिंघम 3' की रीमेक 'रोमियो' बना रहे हैं गुड्डू धनोआ।
- तमिल फिल्म 'सूरराई पोटरु' की रीमेक बनाने की घोषणा निर्माता विक्रम मल्होत्रा ने की है। यह एयर डेक्कन के संस्थापक जी आर गोपीनाथ के जीवन से प्रेरित होगी।
- तेलुगु फिल्म 'नांधी' की रीमेक अजय देवगन बनाएंगे।
- तमिल फिल्म 'अरुवी' की रीमेक में फातिमा सना शेख होंगी।
- साल 2017 में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'विक्रम वेधा' की रीमेक में रितिक रोशन और सैफ अली खान होंगे।
- तेलुगु फिल्म 'जर्सी' की रीमेक में शाहिद कपूर होंगे।
- तमिल फिल्म 'पितामगन' की रीमेक के राइट्स सतीश कौशिक ले चुके हैं।
- तेलुगु फिल्म 'अला वैकुंठपुरमलो' के रीमेक में कार्तिक आर्यन हैं।
- मलयालम हारर थ्रिलर फिल्म 'एज्रा' की रीमेक भी बनकर तैयार है। फिल्म में इमरान हाशमी प्रमुख भूमिका में हैं।
- मलयालम फिल्म 'हेलेन' की रीमेक पर अगस्त से जाह्नवी कपूर काम शुरू करेंगी।
- तेलुगु फिल्म 'आर एक्स 100' की रीमेक से सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी डेब्यू करेंगे।
- तमिल फिल्म 'थाडम' की रीमेक में आदित्य राय कपूर के होने की खबरें हैं।

विदेशी फिल्मों की रीमेक

- आमिर खान और करीना कपूर अभिनीत फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' टाम हैंक्स अभिनीत हालीवुड फिल्म 'फारेस्ट गम्प' की रीमेक है।
- तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन अभिनीत फिल्म 'लूप लपेटा' जर्मन फिल्म 'रन लोला रन' की रीमेक है।
- हालीवुड की फिल्म 'द इंटर्न' की रीमेक में दीपिका पादुकोण के साथ अमिताभ बच्चन होंगे।
- कार्तिक आर्यन अभिनीत फिल्म 'धमाका' कोरियन फिल्म 'द टेरर लाइव' की रीमेक होगी।
- साल 2011 में रिलीज हुई कोरियन फिल्म 'ब्लाइंड' की इसी नाम से बनी रीमेक की शूटिंग सोनम कपूर खत्म कर चुकी हैं।
- सिल्वेस्टर स्टेलान अभिनीत हालीवुड फिल्म 'रैंबो' की रीमेक में टाइगर श्राफ काम करेंगे।

सेलेब स्पीक

खुद को चुनौती देना जरूरी है

अभिनेता फरहान अख्तर फिल्म 'तूफान' में मुक्केबाज के किरदार में हैं। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। इससे पहले वह फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' में फ्लाइंग सिख नाम से प्रख्यात स्वर्गीय एथलीट मिल्खा सिंह के जीवन को पर्दे पर निभा चुके हैं। अभिनय के अलावा निर्देशन, लेखन और गायन में सक्रिय फरहान बता रहे हैं फिल्म में किरदार, उसकी तैयारियों और जिंदगी से जुड़ी बातें...

शारीरिक से ज्यादा मानसिक तैयारी: फरहान कहते हैं, 'अलग-अलग रोल के लिए शारीरिक तैयारी की अलग-अलग डिमांड होती है। मेरी पिछली फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में भले ही फिजिकल डिमांड कम रही हो, लेकिन उसमें इमोशनल चैलेंज काफी थे। 'तूफान' के लिए मैं अपनी तैयारी सिर्फ इतनी चाहता था कि अगर बाक्सिंग या उसकी दुनिया से जुड़ा कोई शख्स मुझे स्क्रीन पर देखे तो उन्हें लगे कि मैं एक बाक्सर को स्क्रीन पर ठीक से निभा पा रहा हूं। सच कहूं तो जो भी काम होता है, वह आपके दिमाग में ही होता है। हर किरदार के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को तैयार करना पड़ता है। स्क्रीन पर दर्शक जो देखते हैं, वह कलाकार के दिमाग में चल रही गतिविधियों का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन (भौतिक रूपांतरण) होता है। इसलिए सबसे ज्यादा मेहनत अपने दिमाग को मजबूत बनाने में होती है।'



आगे बढ़ते रहना जरूरी: फरहान के मुताबिक, खेल जीवन में असफलताओं को भूलकर आगे बढ़ना सिखाता है। वह कहते हैं, 'हम सभी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में असफलता महसूस की है। यह तो जीवन का हिस्सा है। मैंने सिर्फ यही सीखा है कि हार हो या जीत, हर चीज को खुशी-खुशी स्वीकार करें। जीत का जश्न विनम्रता से मनाएं और हार का बोझ इतना मत लें कि फिर कभी आप उठकर आगे ना बढ़ सकें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना, कुछ न कुछ सीखते रहना और खुद को लगातार नई चुनौतियां देना जरूरी है।'

कुछ किरदार साथ रह जाते हैं: कई बार किरदारों से निकलना कलाकारों के लिए आसान नहीं होता है। फरहान के लिए भी अपने किरदार से निकलना मुश्किल होता है। वह कहते हैं, 'कभी-कभी किरदार आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। जिसे आप आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। फिल्म 'रॉक ऑन' ने मेरी जिंदगी में म्यूजिक को फिर से जोड़ा। उसी की वजह से मैंने अपना बैंड बनाया और कई देशों और कालेजों में जाकर परफार्म किया। बिना 'रॉक ऑन' के मुझे यह एहसास ही नहीं होता कि म्यूजिक मेरे जीवन में कितना अहम है। फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' करने के दौरान मिल्खा सिंह जी और उनकी कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनका अनुशासन और कठिन परिश्रम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि 'भाग मिल्खा भाग' किए बगैर मैं 'तूफान' फिल्म कर पाता।'

जल्द करेंगे निर्देशन: साल 2011 में रिलीज फिल्म 'डॉन 2' के बाद से निर्देशक की कुर्सी से दूर रहे फरहान अपनी अगली फिल्म पर कहते हैं, 'आने वाले दिनों में मैं एक फिल्म निर्देशित करने वाला हूं। निर्देशन और लेखन मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, वह मैं करता रहूंगा। जब मैं फिल्म में एक्टिंग कर रहा होता हूं तो निर्देशक के काम में दखल नहीं देता हूं। बतौर अभिनेता मुझे उनके नजरिए, सहारे और भरोसे की जरूरत होती है। मैं अपने निर्देशक को उतना ही सम्मान देने की कोशिश करता हूं, जितना मैं बतौर निर्देशक अपने कलाकारों से चाहता हूं।'

नकारात्मकता को बना लेता हूं ईंधन: 'तूफान' को लेकर इंटरनेट मीडिया में की गई नकारात्मक टिप्पणियों पर फरहान कहते हैं, 'ऐसे लोगों की सोच उनको मुबारक। अगर कोई मेरी तरफ नकारात्मकता भेजता है तो मैं उसे अपना ईंधन बना लेता हूं और फिर अपने अंदर की आग में डाल देता हूं, ताकि और बेहतर काम कर सकूं।' टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों से फरहान का कहना है, 'ओलंपिक में परफार्म करना ही एक बड़ी उपलब्धि है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर आएंगे। खेल के परिणाम जो भी हों, ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने पर ही हमें आप पर गर्व है।'

दीपेश पांडेय

मुलाकात

नई राहों का ख्वाहिशमंद हूं

साल 2019 में संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन तले बनी फिल्म 'मलाल' से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले अभिनेता मीजान जाफरी फिल्म 'हंगामा 2' में केंद्रीय किरदार में हैं। साल 2003 में बनी फिल्म 'हंगामा' की सीक्वल 'हंगामा 2' डिज्नी प्लस हाटस्टार पर 23 जुलाई से स्ट्रीम होगी। स्वर्गीय अभिनेता जगदीप के पोते और जावेद जाफरी के बेटे मीजान पहली बार कामेडी करते नजर आएंगे...



'हंगामा 2' का प्रस्ताव मिलने पर जेहन में क्या था?

प्रोडक्शन हाउस ने मुझसे बस यह पूछा था कि प्रियदर्शन की फिल्म करोगे? प्रियदर्शन सर इतनी बड़ी हस्ती हैं कि मैं तुरंत तैयार हो गया। जब पता चला कि यह फिल्म 'हंगामा' की सीक्वल है तो उत्साह बढ़ गया। एक जिम्मेदारी भी आ गई कि मुझे उसके लेवल को बरकरार रखना होगा।

'हंगामा' को लेकर क्या यादें हैं?

मैंने साल 2003 में मुंबई के ग्लोबस थिएटर में एक दोस्त और उसकी मम्मी के साथ 'हंगामा' देखी थी। तब मैं आठ साल का था। फिल्म में राजपाल यादव जी का किरदार मेरा पसंदीदा था। 'हंगामा 2' की कहानी बिल्कुल नई है, जिसे प्रियदर्शन सर ने अपने अलग अंदाज में बनाया है।

उम्र और अनुभव में सीनियर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ रोमांस करने में कोई हिचक रही?

शिल्पा जी से मुलाकात से पहले मन में डर था कि इतनी सीनियर एक्टर के साथ कैसे बात होगी, क्या करूंगा? लेकिन सेट पर पहली मुलाकात के दौरान ही उन्होंने मुझसे बेहिचक बातें और हंसी-मजाक शुरू कर दिया। जिससे सब सहज हो गया। अब वह मेरी अच्छी दोस्त हैं। उन्होंने अपने अनुभवों से सेट पर कई चीजों में मेरी मदद की।

परेश रावल और आशुतोष राणा जैसे कलाकारों के बीच खुद को साबित करने की चुनौती को कैसे पार किया?

वह तो आज तक मेरे लिए चुनौती ही है, क्योंकि दोनों कमाल के अभिनेता हैं। वैसे मैं मानता हूं कि किसी सीन में परेश रावल, शिल्पा शेट्टी या मीजान नहीं होते हैं, बल्कि उनके किरदार होते हैं। उनके साथ यही कोशिश रहती थी कि मैं भी उन्हीं की तरह बेस्ट परफार्मेंस देकर सीन को अच्छा बना पाऊं। सेट पर पहले दिन परेश जी को शायद मेरी नर्वसनेस दिख गई थी। उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, इसी तरह बिंदास होकर करते रहो। इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया।

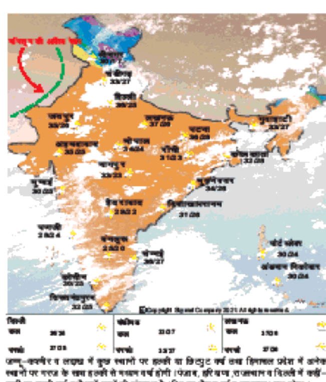
आपके दादा और पिता लोकप्रिय कामेडी कलाकार रहे हैं। इस जानर में लोगों को आपसे अपेक्षाएं होंगी..

मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूं। सिर्फ काम पर फोकस करता हूं। मेरे दादा या पिता जी ने मुझे कभी काम को लेकर सलाह नहीं दी, लेकिन जिंदगी और इंसानियत के बारे में कई चीजें बताईं। वे सबसे बढ़कर हैं।

रोमांस और कामेडी के बाद आगे किस जानर पर ध्यान रहेगा?

अब मैं एक्शन फिल्म करना चाहता हूं। खुद को वर्सेटाइल एक्टर साबित करना है। जल्द ही मेरी दो-तीन फिल्मों की घोषणा होगी।

दीपेश पांडेय





स्वीडन में स्टाकहोम बैंक ने जारी किया पहला बैंक नोट



1661 में आज की ही तारीख पर स्वीडन के स्टाकहोम बैंक ने पहला बैंक नोट जारी किया था। वहां सरकार ने नए सिक्के जारी किए थे, जिससे बैंक से पुराने सिक्के निकालने की होड़ लग गई थी। इसी क्रम में बैंक ने क्रेडिट नोट जारी किया था। हालांकि प्रयोग विफल रहा था।



चांद के सफर पर रवाना हुआ अमेरिका का अपोलो-11 यान

1969 में आज की ही तारीख को अपोलो-11 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लांच किया गया था। इसी यान से नील आर्मस्ट्रांग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कालिंस चांद पर पहुंचे थे और 20 जुलाई को पहली बार वहां इंसान ने कदम रखा। तीनों यात्री 24 जुलाई को सुरक्षित लौट आए थे।

हाकी के 'कपिल देव' के नाम से जाने जाते हैं धनराज पिल्लै



हाकी के 'कपिल देव' कहे जाने वाले भारतीय हाकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्लै का जन्म आज की ही तारीख को पुणे में 1968 में हुआ था। इन्होंने हाकी खेलने की शुरुआत टूटी हुई लकड़ियों और फेंकी हुई गेंदों से की थी। 1989 में हाकी में पदार्पण किया और 1992, 1996, 2000 और 2004 ओलिंपिक में हिस्सा लिया। इनकी अगुआई में 1998 के एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को पेनाल्टी शूट आउट में 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें 2000 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

लकवाग्रस्त व्यक्ति भी कर सकेंगे संवाद

बड़ी सफलता ▸ पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगों से पता चल सकेगा कि वह क्या कहना चाहता है

कैलिफोर्निया, एपी : अब लकवाग्रस्त व्यक्ति भी संवाद कर सकेंगे। यह सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन सच है। विज्ञानियों ने इस दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि लकवाग्रस्त व्यक्ति की मस्तिष्क की तरंगों के जरिये यह पता लगाया जा सकेगा कि वह क्या कहना चाहता है और उसकी वह बातें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे सकेंगी।

इस पूरे अध्ययन में भले ही अभी काफी समय लगेगा, लेकिन इस दिशा में विज्ञानियों ने बढ़त हासिल कर ली है। विज्ञानियों का कहना है कि किसी चोट या बीमारी के कारण अपनी बात कहने में असमर्थ व्यक्ति इस खोज की मदद से संवाद करने में सक्षम हो सकेगा।

इस कार्य का नेतृत्व करने वाले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में न्यूरोसर्जन डा. एडवर्ड चांग के मुताबिक, हम इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं कि हम वार्तालाप के जरिये कितनी आसानी से संवाद कर पाते हैं। यह सोचना बेहद रोमांचकारी है कि हमने इस दिशा में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, जिसकी मदद से अब वे लोग भी अपनी बात कह सकेंगे, जो बोलने की क्षमता खो चुके हैं। पक्षाघात के कारण बोलने और लिखने में असमर्थ लोगों के संवाद करने की तरीके आज बहुत ही सीमित हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रयोग में शामिल किया गया पीड़ित बेसबाल कैप से जुड़े एक प्वाइंटर का उपयोग करता है, जो उसे स्क्रीन पर शब्दों या अक्षरों को छूने के लिए अपना सिर हिलाने देता है। दूसरी डिवाइस उसकी आंखों की गतिविधियों को पकड़ती है। इस तरह यह बेहद ही थकाऊ और धीमी प्रक्रिया होती है, जिसमें कई बार पूरी बात स्पष्ट भी नहीं हो पाती। विज्ञानियों के मुताबिक, अब इस काम को आसान बनाने के लिए वे इस दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं। उनके मुताबिक, मस्तिष्क के संकेतों को निकालना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। हाल के वर्षों में इस दिशा में कामयाबी मिल चुकी है कि कृत्रिम रूप से मस्तिष्क की तरंगों के जरिये रोबोटिक भुजाओं की मदद से लकवाग्रस्त व्यक्ति हाथ मिला सकता है व स्वयं पानी पी सकता है। अब विज्ञानी मस्तिष्क के उन्हीं संकेतों को संवाद के लिए प्रयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वे इस दिशा में काम कर रहे हैं कि पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगों से उसके मन की बात को कंप्यूटर स्क्रीन पर लाया जा सके।



कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में न्यूरोसर्जन डा. एडवर्ड चांग वर्ष 2017 में पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति की सर्जरी के बाद उसके मस्तिष्क के स्कैन को स्क्रीन पर देखते हुए। एपी

इस पर किया जा रहा है काम

चांग की टीम स्पीच न्यूरोप्रोस्थेटिक तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। इसके जरिये मस्तिष्क की तरंगों को डीकोड किया जा सकेगा। यह तरंगें ही वोकल ट्रैक, होठों, जबड़ों, जीभ और कंठ की मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं।

परीक्षण में दिखे अच्छे परिणाम : डिवाइस का परीक्षण विज्ञानियों ने एक वालंटियर पर किया, जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक थी और उसे 15 वर्ष पहले ब्रेन-स्टेम स्ट्रोक के कारण पक्षाघात हो गया था। शोधकर्ताओं ने उसके मस्तिष्क की उस सतह पर इलेक्ट्रोड लगाए, जो बातचीत में मदद करती है। विज्ञानियों ने प्रयोग में देखा कि जब उसने 'पानी' या 'अच्छा' जैसे शब्दों को बोलने का प्रयास किया तो उससे मिलते-जुलते करीब 50 शब्द बने, जिससे एक हजार वाक्य तैयार हुए। जब उससे कुछ सवाल जैसे कि 'आज आप कैसे हैं', 'क्या आपको प्यास लगी है' तो जवाब में क्रमशः 'मैं अच्छा हूं' और 'नहीं, मैं प्यासा नहीं हूं' सामने आया।

सुधार की जरूरत : न्यू इंग्लैंड जर्नल आफ मेडिसिन में प्रकाशित इस शोध के प्रमुख लेखक और चांग की प्रयोगशाला के इंजीनियर डेविड मोसेस के मुताबिक, व्यक्ति क्या कहना चाहता है अभी इसे स्क्रीन पर दिखाई देने में तीन से चार सेकंड लगते हैं। बातचीत के क्रम में देखें तो यह प्रक्रिया कुछ धीमी है। विज्ञानियों का कहना है कि अभी इस प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। उम्मीद है कि जल्द इस दिशा में कामयाबी मिलेगी और बोलने व लिखने में असमर्थ व्यक्ति अपनी बात को कंप्यूटर स्क्रीन के जरिये दूसरों तक पहुंचा सकेंगे।



छतों पर उगने लगी सब्जियां : महानगरों में उपजाऊ और कृषि योग्य जमीन घट रही है। ऐसे में रूफटाप खेती भविष्य की जरूरत के रूप में तेजी से बढ़ रही है। हाईराइज बिल्डिंगों के देश हांगकांग में स्काई गार्डन का प्रचलन बढ़ा है। यहां शापिंग माल और सार्वजनिक सोसाइटियों की छतों पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। मेट्रो प्लाजा शापिंग माल में करीब 1200 वर्ग मीटर में तैयार किए गए गार्डन में सब्जी की देखभाल करता माली। हांगकांग में करीब 60 रूफटाप गार्डन हैं। रूफटाप के सहसंस्थापक एंड्रयू त्सुई का कहना है कि अब ताजा सब्जियां आसानी से उपलब्ध हैं। इस खेती को इंसटेंट नूडल सिटी लाइफस्टाइल नाम दिया गया है। एएफपी

इधर-उधर की

न्यूयार्क में अब हर दिन कटवा सकेंगे बाल



रविवार को बाल कटवाने पर सजा और जुर्माने का था कानून। इंटरनेट मीडिया

न्यूयार्क, एजेंसी : चौंकिए मत! भारत में भले आप किसी भी दिन बाल कटवाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन न्यूयार्क के लोगों के लिए ऐसा नहीं था। यहां वर्षों पहले ऐसा कानून बना था, जिसके तहत रविवार को बाल काटने पर सजा और जुर्माने का प्रविधान था। अब लोगों को इससे राहत मिल गई है। इस कानून को वहां के गवर्नर एंड्रू कुओमो ने रद करते हुए कहा, 'यह एक पुराना व अर्थहीन कानून था, जिसका 21वीं सदी में कोई मतलब नहीं है। पता नहीं यह कानून बना क्यों था।'



अमेजन के जंगलों में 10 हजार प्रजातियों पर संकट

अमेजन के नष्ट होते वर्षा वन में 10 हजार से ज्यादा पेड़ों और जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। साइंस पैनल फार द अमेजन (एसपीए) की ओर से जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यहां के वन का 35 फीसद हिस्सा अब तक नष्ट हो चुका है। दुनिया के इस सबसे बड़े वर्षा वन को लेकर दुनियाभर के 200 विज्ञानियों के अध्ययन को रिपोर्ट में शामिल किया गया है। यह इस वन को लेकर अब तक का सबसे विस्तृत आकलन है। इसमें वैश्विक जलवायु में अमेजन की भूमिका और इसके सामने आए संकट दोनों का उल्लेख किया गया है। अमेजन का वर्षा वन ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गिनी देशों में फैला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन वनों में कटाई और इनके नष्ट होने की गति को दशक से भी कम समय में शून्य पर लाना जरूरी है। साथ ही, अब तक नष्ट हो चुके हिस्से को फिर हरा-भरा करना भी महत्वपूर्ण है।

200 अरब टन कार्बन समाई हुई है यहां की मिट्टी और घासों में, जो दुनियाभर में सालाना उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाई आक्साइड से पांच गुना है

8,000 पेड़-पौधों की प्रजातियां मानवीय गतिविधियों के कारण विलुप्त होने के कगार पर

2,300 जीवों की प्रजातियों पर भी खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है

(इनपुट : प्रेट्र)

ब्राजील में सत्ता परिवर्तन से बढ़ गया खतरा

2019 में ब्राजील में राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के सत्ता में आने के बाद से वनों की कटाई बहुत बढ़ गई है। बोल्सोनारो ने अमेजन के संरक्षित क्षेत्रों में खनन एवं कृषि की पैरवी की है और पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों की ताकत को कम किया है। पिछले साल यहां कटाई 12 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी।

18% अमेजन बेसिन में अब तक वन नष्ट हो चुके हैं

17% हिस्सा डीग्रेड हुआ है यानी वन का स्तर गिरा है

पिछले साल भारत में कैंसर के 62 हजार से ज्यादा नए मामले शराब से संबंधित

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले साल भारत में शराब पीने से कैंसर के 62,100 नए मामले सामने आए। लैंसेट आंकोलाजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह बात सामने आई। इससे यह भी पता चला कि देश में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। शोधकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर पाया कि 2020 में सामने आए कैंसर के कुल मामलों में से 7,40,000 यानी चार फीसद की वजह शराब थी।

वैश्विक स्तर पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि शराब पीने के कारण पुरुषों के मुकाबले कैंसर की चपेट में आने वाली महिलाएं की संख्या बेहद कम थी। पुरुषों के 77 फीसद (568,700) मामले शराब पीने से जुड़े थे, जबकि महिलाओं में 23 फीसद (172,600) मामले सामने आए। शोधकर्ताओं ने शराब और कैंसर के बीच संबंध के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत पर बल दिया है।

कोरोना संबंधी हृदय समस्या से जल्द उबर सकते हैं बच्चे

अनुसंधान



कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने लगाया पता। फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

कोरोना की चपेट में आने वाले बच्चों को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसका दावा है कि मल्टीसिस्टम इंफ्लेमेटोरी सिंड्रोम (एमआइएस-सी) के चलते अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चे हृदय संबंधी समस्या से जल्द उबर सकते हैं। यह समस्या महज कुछ माह में शीघ्रता के साथ दूर हो सकती है। एमआइएस-सी एक इंफ्लेमेटोरी या सूजन वाली स्थिति है। यह दुर्लभ समस्या कोरोना के कारण खड़ी होती है।

अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, एमआइएस-सी की चपेट में आने वाले कई कोरोना पीड़ित बच्चों में पहले कोई लक्षण नहीं होता है या मामूली लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते और हृदय संबंधी समस्या समेत गैर श्वसन वाले लक्षण उभरते हैं। बेहद निम्न ब्लड प्रेशर के भी कुछ मामले पाए गए हैं। हालांकि, इनमें से ज्यादातर लक्षण महज कुछ माह में खत्म हो जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कंवल एम फारूकी ने कहा, 'अध्ययन से हमें पता चला कि कोरोना के चलते बच्चों में विविध समस्याएं खड़ी होती हैं। कई मामले बिना लक्षण वाले तो कुछ मामूली लक्षण वाले होते हैं, जबकि एमआइएस-सी की चपेट में आने से कुछ बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को आइसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। राहत की बात यह है कि एमआइएस-सी के साथ बच्चों में उभरने वाली हृदय संबंधी समस्या जल्द दूर हो जाती है।' एमआइएस-सी पीड़ित 45 बच्चों के डाटा का विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला गया। यह अध्ययन पीडीऐट्रिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। -आइएएनएस

स्क्रीन शॉट

जब भुज के लिए अजय ने दोबारा शूट किया गाना



डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज होगी अजय देवगन अभिनीत फिल्म भुज : द प्राइड आफ इंडिया। इंस्टाग्राम

फिल्म की छोटी-छोटी बारीकियों को लेकर सितारे बेहद सतर्क रहते हैं। बात करें अजय देवगन अभिनीत फिल्म भुज : द प्राइड आफ इंडिया की तो उन्होंने इस फिल्म के लिए एक गाने को दोबारा शूट किया है। हैदराबाद में इस साल इस फिल्म का बड़ा हिस्सा शूट किया गया था, वहीं जून में मुंबई में भी फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिल्म रिलीज के लिए तैयार भी है, लेकिन म्यूजिक कंपोजर गौरव दासगुप्ता से मुलाकात के बाद अजय ने फिल्म के एक गाने को दोबारा शूट किया। दैनिक जागरण के सहयोगी अखबार मिड डे से बातचीत में गौरव ने बताया कि हंजुगम... गाना अजय सर ने द बिग बुल फिल्म के म्यूजिक सेशन में सुना था। उन्होंने तभी कहा था कि यह गाना उन्हें अपनी फिल्म भुज : द प्राइड आफ इंडिया के लिए चाहिए। कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि उन्होंने दूसरा लव सांग शूट कर लिया है, लेकिन अजय सर को यह गाना इतना पसंद था कि उन्होंने और फिल्म निर्देशक ने सीक्वेंस को रीशूट किया। तीन दिनों में इस गाने को महबूब स्टूडियो में शूट किया गया। भुज : द प्राइड आफ इंडिया फिल्म डिज्नी प्लस हाटस्टार पर 13 अगस्त को रिलीज होगी। यह फिल्म वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

प्रोड्यूसर बनीं तापसी पन्नू ने कहा, इंडस्ट्री का कर्ज चुकाना चाहती हूं

अभिनेता या अभिनेत्रियों का प्रोड्यूसर बनके कंटेंट निर्माण के क्षेत्र में उतरना कोई नई बात नहीं है। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, कंगना रनोट और ईशा देओल के बाद अब पिंक अभिनेत्री तापसी पन्नू भी प्रोड्यूसर बन गई है। गुरुवार को तापसी ने अपने प्रोडक्शन हाउस आउटसाइडर्स फिल्म्स की घोषणा की। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर प्रांजल खंढडिया के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की। इसके साथ ही तापसी ने अपने प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली पहली फिल्म ब्लर की भी घोषणा की। इस फिल्म का निर्माण वह जी स्टूडियो के साथ मिलकर करेंगी। फिल्म की प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ वह इस फिल्म में अभिनय भी करेंगी। इस फिल्म के निर्देशन की बागडोर बीए पास और सेक्शन 375 जैसी फिल्मों के निर्देशक अजय बहल के हाथों में होगी। फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाएगा। तापसी ने बयान जारी किया, 'मैं अपने इस नए सफर तथा आउटसाइडर्स फिल्म्स के जरिये सिनेमा के प्रति एक अलग तरह का प्यार जताने को लेकर बेहद रोमांचित हूं। पिछले 11 वर्षों के करियर में मुझे दर्शकों और इंडस्ट्री का बहुत प्यार और सहयोग मिला है। आउटसाइडर्स फिल्म्स के माध्यम से मैं इंडस्ट्री का कर्ज चुकाना और इस इंडस्ट्री में काम तलाश रही गैर फिल्मी बैकग्राउंड की प्रतिभाओं को मौका मुहैया कराना चाहती हूं। प्रांजल और मेरा दोनों का बैकग्राउंड बहुत साधारण रहा है। इसलिए हमने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम 'आउटसाइडर्स फिल्म्स' रखने के फैसला किया।'



तापसी ने घोषित की अपनी अगली फिल्म ब्लर। सौ. टीम तापसी

मुझे अपनी टीम और उसके जज्बे पर गर्व है : बाबी देओल

सिंगिंग लीग शो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग (आइपीएमल) अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस रविवार को शो का फाइनल होगा। फाइनल में पहुंची चार टीमों मुंबई वारियर्स, पंजाब लायंस, गुजरात राकर्स और बंगाल टाइगर्स में से कोई एक टीम विजेता बनेगी। शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फाइनल एपिसोड की शूटिंग के दौरान मुंबई वारियर्स के मैस्काट (प्रतिनिधि) रितेश देशमुख पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ तथा पंजाब लायंस के मैस्काट बाबी देओल भी पहुंचे। इतना ही नहीं सेट पर तीनों सितारों ने परफार्मेंस भी दी। रितेश और जेनेलिया ने जहां दिल में बजी गिटार... और मराठी गाने ढगाला लागली... गानों पर परफार्म किया, वहीं बाबी ने दुनिया हसीनों का मेला... गाने पर परफार्म किया। इस मौके पर परिणाम घोषित होने से पहले अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए बाबी ने कहा, 'हमारी टीम शुरू से ही शानदार रही है। सुपरस्टार मीका सिंह और शेरनी असीस कौर की अगुआई में टीम इस कंपटीशन में दिन-प्रतिदिन मजबूत होती गई। रुपाली जग्गा, शहनाज अख्तर और दिव्य कुमार जैसी नई प्रतिभाओं ने भी लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे अपनी टीम और उसके कभी हार न मानने वाले जज्बे पर गर्व है। हमारी टीम ने हर सप्ताह अपने संगीत के माध्यम से पंजाब की संस्कृति, मूल्यों और प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जीतेंगे तो हम ही।'



आइपीएमल के फाइनल में अपनी टीम का उत्साहवर्धन करने पहुंचे बाबी। सौ. टीम जी टीवी



स्कूली दिनों में पढ़ाई के मामले में बहुत तेज नहीं थे आदर्श • इंटरनेट मीडिया

जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा, तो खो जाऊंगा : आदर्श गौरव

सात सवाल

नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म द व्हाइट टाइगर में आदर्श गौरव के अभिनय को काफी सराहा गया था। लगभग 10 वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रहे आदर्श के लिए यह बड़ा बदलाव है। वेब सीरीज हास्टल डेज के दूसरे सीजन में आदर्श फिर नजर आएंगे। इसके पहले सीजन में भी आदर्श का काम पसंद किया गया था। दूसरा सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर 23 जुलाई से स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा। इस शो, करियर में बदलाव, स्कूल-कालेज की यादों को लेकर उनसे हुई बातचीत के अंश।

• डिजिटल प्लेटफार्म आपको बहुत रास आ रहा है। द व्हाइट टाइगर के बाद आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं...

-द व्हाइट टाइगर के बाद यकीनन करियर में बदलाव तो आया ही है। डिजिटल प्लेटफार्म की वजह से हर कलाकार के लिए मौके बहुत बढ़ गए हैं। इस मौके को हल्के में नहीं ले सकते हैं। मौके बढ़ने की वजह से हर किसी को बराबरी का काम करने का मौका मिल जाता है। आप अपने नाम की वजह से नहीं, बल्कि अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। द व्हाइट टाइगर फिल्म के बाद मुझे मौके ज्यादा मिल रहे हैं। ऐसे निर्देशकों और लेखकों से बातचीत हो पा रही है, जिनके साथ पहले काम करना बस एक सपना था।

• हास्टल डेज का पहला सीजन साल 2019 में रिलीज हुआ था। हास्टल डेज-2 दो साल बाद आ रही है। उस किरदार को फिर से पकड़ना कितना मुश्किल था?

-वह किरदार मैं एक बार निभा चुका हूं। यही वजह है कि मुझे उस किरदार की आदतें, पैटर्न, गहराई सबकी समझ है, लेकिन जब शो का नया सीजन बनता है तो नए रिश्ते बनते हैं, जो मजेदार बात होती है। जब हम पहले सीजन की तैयारी कर रहे थे, तब हम सारे कलाकार एक-दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। वहीं, दूसरे सीजन में हम गहरे दोस्त बन गए थे। हमारे बीच एक सहजता आ गई थी। दूसरे सीजन में पहले सीजन के मुकाबले ज्यादा मस्ती, जोक्स, ड्रामा होगा।

• आपके स्कूल-कालेज की क्या यादें हैं? आप कैसे स्टूडेंट रहे हैं?

-मैं हास्टल में तो नहीं रहा हूं, लेकिन कई मस्तियां हमने हास्टल के बाहर की हैं, जो इस शो में भी दिखाई गई हैं। मैं कभी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। माता-पिता का सपना था कि मैं टाप 10 में आऊं, लेकिन मैं कभी नहीं आया। छठी क्लास तक मैं बहुत सीधा-साधा बच्चा था। उसके बाद मेरा ध्यान पढ़ाई से थोड़ा हट गया था। शैतानियां ज्यादा करने लगा था। मुझे इतिहास विषय बहुत पसंद था, गणित और विज्ञान से बहुत डर लगता था। मेरे नानाजी ने मुझे पढ़ाया था, इसलिए मैं उनकी वजह से दसवीं में अच्छे नंबरों से गणित में पास हो पाया था।

• आपने काफी कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था...

-हां, मैंने 14 साल की उम्र में माय नेम इज खान में अभिनय किया था। मैं बाल कलाकार नहीं था कि शूटिंग के लिए स्कूल छोड़ना पड़े। एक बार शूटिंग करने के बाद मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आता था। मेरा बचपन बहुत ही सामान्य था। शूटिंग के लिए कभी स्कूल नहीं छोड़ा। मैंने कालेज के दूसरे या तीसरे साल में अभिनय को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। उससे पहले तक एक्टिंग सिर्फ मेरा शौक था।

• अब अभिनय की अहमियत पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है?

-अब तो अभिनय जीवन में बहुत अहमियत रखता है। ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरी चीजों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा मजा कहानी को अलग-अलग किरदारों के जरिये बताने में आता है। अभिनय मेरे लिए खुद को जाहिर करने का सबसे अहम जरिया है।

• आप रियलिस्टिक किरदार लगातार निभा रहे हैं। क्या बालीवुड के हीरो वाले किरदार करने का मन है?

-हां, वह भी करना चाहूंगा, लेकिन स्क्रीन पर हीरो बनना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अनोखी कहानियों और निर्देशकों के साथ काम करूं।

• क्या अब संघर्ष खत्म हो गया है?

-संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है। मैं चाहता भी नहीं कि संघर्ष खत्म हो, क्योंकि मुझे अपने काम को हल्के में नहीं लेना है। जिस दिन अपने सपनों का पीछा करना बंद कर दूंगा, उस दिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होगा, मैं खो जाऊंगा। (प्रियंका सिंह)

मेरे और दिशा के बीच सोचने के लिए कुछ था ही नहीं : राहुल वैद्य

बिग बास 14 फेम गायक राहुल वैद्य तथा उनकी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री दिशा परमार शुक्रवार को शादी के बंधन में बंधकर जीवनसाथी बन जाएंगे। राहुल ने दिशा से अपने प्यार का इजहार रियलिटी शो बिग बास के दौरान ही किया था। अक्सर लोग प्यार का इजहार के बाद एक-दूसरे को समझने के लिए वक्त लेते हैं, लेकिन राहुल की सोच अलग है। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा, 'दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो एक-दूसरे को समझने में बहुत वक्त लेते हैं और दूसरे वो जो सीधा शादी करते हैं। हम दूसरे वर्ग में आते हैं। एक-दूसरे से मिलने के बाद हम दोनों ने देखा कि जीवन के प्रति हमारी सोच मिलती-जुलती है तो हमारे पास ज्यादा कुछ सोचने या इंतजार करने के लिए था ही नहीं। अपने प्यार के साथ आप कितना भी समय व्यतीत कर लें, वह कम ही लगता है। इसलिए अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति के अनुसार हमने बिना ज्यादा समय गंवाए सीधे शादी करने का फैसला किया। मेरे खतरों के खिलाड़ी 11 पर जाने से पहले ही हमने जून में शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन बीच में यह शो आ गया तो योजना रद करनी पड़ी। फिर दक्षिण अफ्रीका से ही वीडियो काल के माध्यम से हमने शादी की नई डेट पर निर्णय लिया। हम मुंबई में ही अपने घर के बड़ों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर शादी कर रहे हैं। वैसे तो हम अपनी शादी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सिर्फ 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है।' शादी के बाद राहुल और दिशा कुछ दिनों तक काम से दूर रहेंगे।



आज अभिनेत्री दिशा परमार के साथ परिणय सूत्र में बंधेंगे राहुल। इंस्टाग्राम

12 अगस्त को डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज की जाएगी शेरशाह

बीते दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म शेरशाह को डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज होने की खबरें आई थी। गुरुवार को फिल्म के निर्माताओं की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले 12 अगस्त को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। यह फिल्म साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य शौर्य और साहस का प्रदर्शन करने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक है। कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। पहले इस फिल्म को दो जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए इसे डिजिटल प्लेटफार्म पर रिलीज किया जा रहा है। फिल्म के बारे में निर्माता करण जौहर का कहना है, 'शेरशाह कारगिल युद्ध के हीरो की सच्ची कहानी है। जिसके अदम्य साहस और बहादुरी ने हमारे देश को जीत दिलाई। उनका बलिदान अमूल्य है और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज करने को लेकर हम बेहद खुश हैं। शेरशाह हमारी तरफ से हमारे सैनिकों की बहादुरी को एक श्रद्धांजलि है। मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म देखकर हर भारतीय अपनी देश की सेना पर गर्व करेगा।' इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ कियारा आडवाणी, शिव पंडित, निकितन धीर और साहिल वैद्य भी अहम भूमिकाओं में हैं।



कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक में लीड किरदार में नजर आएंगे सिद्धार्थ • इंस्टाग्राम